हरिभूमि

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

आम बजट- 2026

जैसा था वैसा

- इनकम टैक्स
- एलपीजी गैस सिलेंडर
- बिजली बिल
- मोबाइल रिचार्ज
- स्कूल फीस

बजट का 'पावर बूस्टर'

- **पूंजीगत निवेश** 12.2 लाख करोड़
- **फोकस** नई सड़कें, पुल और औद्योगिक बुनियादी ढांचा
- **लक्ष्य** विकास की रफ्तार को टॉप गियर में डालना

■ टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं ■ 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा

रक्षा, शिक्षा, हेल्थ पर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा काम, फिर भी बाजार धड़ाम!

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए लोकलुभावन योजनाओं से परहेज किया और 'सुधार एक्सप्रेस' को जारी रखने की घोषणा की। सीतारमण ने अपना लगातार रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करते हुए किसानों, युवाओं और छोटी कंपनियों पर विशेष ध्यान देने के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दिया और सुधारों का खाका पेश किया। कुल मिलाकर, यह बजट आत्मनिर्भरता, तेज विकास और चुनावी राज्यों में निवेश पर केंद्रित है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, रोजगार बढ़ेगा और भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत बनेगा। इधर, बजट को बाजार समझ नहीं पाया और धड़ाम हो गया। कुछ ही पल में निवेशकों ने लाखों करोड़ रुपए डूब गए।

किसे कितना बजट

रक्षा मंत्रालय	7,84,678.28 करोड़
गृह मंत्रालय	2,55,233.53 करोड़
आयुष मंत्रालय	4,408.93 करोड़
रेल मंत्रालय	2,77,830 करोड़
कृषि मंत्रालय	1,62,671 करोड़
स्वास्थ्य मंत्रालय	1,06,530.42 करोड़
खेल मंत्रालय	4479.88 करोड़

बजट में खास

- 85 मिनट के भाषण में सीतारमण ने इस बार नहीं किया किसी कवि और कविता का उल्लेख
- नई ग्रामीण रोजगार योजना 'वीबी-जी राम जी' के लिए 95,000 करोड़ आवंटित
- वित्त मंत्री ने पांच चिकित्सकीय पर्यटन केंद्र स्थापित करने का रखा प्रस्ताव
- संशोधित आयकर रिटर्न जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव

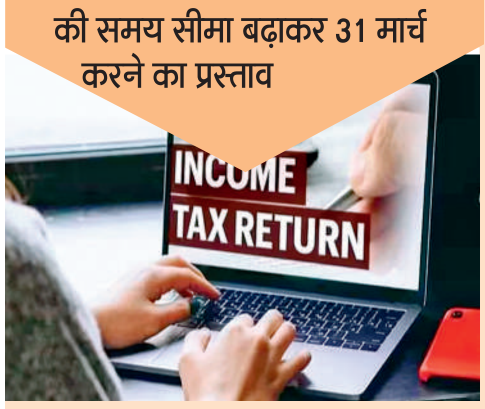

- बजट में छोटे करदाताओं के लिए छह महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना की घोषणा
- पुनर्खरीद से होने वाली प्राप्ति पर अब लगेगा 'पूंजीगत लाभ कर'
- बजट में अगले पांच साल में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव
- केंद्र सरकार प्रमुख औद्योगिक 'लॉजिस्टिक' केंद्रों के पास पांच विवि टाउनशिप स्थापित करेगी
- मंत्रियों, मंत्रिमंडल सचिवालय और पीएमओ के खर्च के लिए 1,102 करोड़
- बाबुओं के प्रशिक्षण के लिए 299 करोड़ रुपए, प्रशासनिक सुधारों को 65 करोड़

किसानों के लिए खास

कोकोनट प्रमोशन स्कीम

नई स्कीम का उद्देश्य नारियल का उत्पादन बढ़ाना। इस योजना के तहत प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में कम उत्पादक पेड़ों को नए, उच्च उपज देने वाले पौधों से बदलने जैसे कदम उठाए जाएंगे।

पशुपालन और डेयरी

पशुपालन क्षेत्र में सरकार ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करेगी। इसके साथ ही किसानों के उत्पादक संगठन बनाने पर काम किया जाएगा।

काजू-कोको और चंदन

काजू और कोको सेक्टर को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की। चंदन के महत्व पर भी जोर दिया केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर लक्षित खेती को बढ़ावा देगी।

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिर्माण पर जोर देने के साथ पूंजीगत व्यय लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जो चालू वित्त वर्ष के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री ने लगभग सवा घंटा के अपने बजट भाषण में सुधारों का खाका पेश करते हुए 'विकसित भारत' के लिए बैंकों को तैयार करने को लेकर एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का भी प्रस्ताव किया। उन्होंने वृद्धि के प्रमुख इंजन के रूप में एमएसएमई के महत्व को रेखांकित करते हुए 10,000 करोड़ रुपए के एसएमई विकास कोष का प्रस्ताव रखा। इसका मकसद क्षेत्र में भविष्य के 'चैंपियन' तैयार करना और उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। बजट का ताना-बाना 'तीन कर्तव्यों' यानी आर्थिक वृद्धि को गति देने, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और 'सबका साथ, सबका विकास' के इर्द-गिर्द बुना गया है। बजट में किसानों की आय बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य से 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास करने, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को मजबूती प्रदान करने तथा स्टार्टअप एवं महिलाओं की अगुवाई वाले समूह को मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों के साथ शामिल करते हुए बाजार से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। सीतारमण ने तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों में सहायता प्रदान कर उच्च मूल्य वाली खेतीबाड़ी पर जोर दिया। बजट में आयकर की दरों एवं संरचना के मोर्चे पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब | गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती

महंगा

मिनरल्स
स्क्रैप
शराब

सस्ता

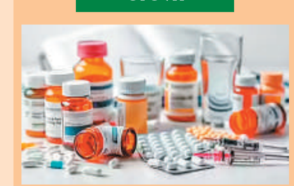

- लैदर
- कपड़ा
- सिंथेटिक फुटवियर
- विदेशी यात्रा
- कैंसर की 17 दवाएं
- माइक्रोवेव ओवन
- जूते
- एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी चीजें
- ईवी बैटरी
- शुगर की दवाएं
- चमड़े और कपड़े का निर्यात
- बायोगैस मिक्स्ड सीएनसी
- सोलर ग्लास
- मिक्स्ड गैस सीएनजी
- विमानों का ईंधन

चुनावी राज्यों पर फोकस

- तमिलनाडु और केरल में रेयर अर्थ कॉरिडोर से खनन और इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा
- पश्चिम बंगाल में वाराणसी-सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी बेहतर होगी
- असम और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी

सरकार के तीन कर्तव्य

- अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना
- जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमताओं को मजबूत करना और उन्हें भारत की समृद्धि की यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाना।
- 'सबका साथ, सबका विकास' सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य परिवार, समुदाय और क्षेत्र को संसाधन प्रदान करना है।

इनकम टैक्स चोरी पर जेल नहीं, जुर्माना

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगर किसी करदाता की आय में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया गया है, तो अब उसे जेल की सजा नहीं होगी। ऐसे मामलों में केवल जुर्माना भरकर मामला रफा-दफा किया जा सकेगा। यह नया बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 'नए इनकम टैक्स एक्ट' का हिस्सा होगा। साथ ही, जिनके पास विदेशों में अघोषित संपत्ति है, उन्हें भी एक मौका दिया गया है। वे अगले 6 महीनों के भीतर डिस्क्लोजर स्कीम के तहत अपनी संपत्ति की जानकारी दे सकते हैं।

संसद परिसर में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सीतारमण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ

हर जिले में बालिका छात्रावास

- देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल स्थापित करने की घोषणा की। देश में 700 से अधिक जिले हैं। गर्ल्स हॉस्टल के बन जाने के बाद लड़कियों को घर से बाहर सुरक्षित और आसान निवास की सुविधा मिलेगी।

5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप

- देश में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप का विकास होगा। इन टाउनशिप में पढ़ाई, रिसर्च, हॉस्टल, खेल और स्टार्टअप जैसी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही देश में 5 नए विश्वविद्यालय खोले जाने की भी घोषणा की गई।

युवाओं को क्या मिला

1.5 लाख केयरगिवर्स की ट्रेनिंग

सरकार देश में तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी और स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले एक साल में 1.5 लाख केयरगिवर को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। यह ट्रेनिंग मुख्य रूप से योग, वेलनेस और चिकित्सा उपकरणों के संचालन से संबंधित होगी।

किसने क्या कहा

विकसित भारत के लिए स्पष्ट रूपरेखा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को 'ऐतिहासिक' बताते हुए कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है। विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि बजट में 'अवसरों की अपार संभावनाएं' हैं।

संकटों से मूंद ली आंखें

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि केंद्रीय बजट में भारत के सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में हैं। आसन्न वैश्विक झटके, सभी को नजरअंदाज कर दिया गया।

विकास को मिलेगी और गति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है। बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है। यह बजट विकास को और अधिक गति देगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलवाले में महत्वपूर्ण भूमिका ▶▶ शेष पेज 19 पर

बजट पूरी तरह से दिशाहीन

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम कमलनाथ ने केंद्रीय बजट पर कहा कि केंद्र सरकार का पेश बजट पूरी तरह से दिशाहीन है। इसमें किसानों, नौजवानों, महिलाओं, आदिवासी, दलित, ओबीसी और सर्व समाज के लिए दृष्टि का अभाव है। मध्यम वर्गीय परिवार आयकर में छूट की आशा रखते थे, लेकिन उस दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं बढ़ाया। बजट में मप्र को पूरी तरह उपेक्षित ▶▶ शेष पेज 19 पर

विकसित भारत होगा साकार

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि विभाग का बजट बढ़ाकर इस वर्ष 1,32,561 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कृषि शिक्षा और अनुसंधान, विशेषकर आईसीएआर सहित, के लिए 9,967 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे शोध और नवाचार को बल मिलेगा। सस्ता खाद और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 1,70,944 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है, ताकि उत्पादन की ▶▶ शेष पेज 19 पर

हरिभूमि के लिए ...

केंद्रीय बजट पर मप्र के दो पूर्व वित्त मंत्रियों और वर्तमान वित्त मंत्री की राय

तेजी से आगे बढ़ते मप्र को मिलेगा विशेष लाभ

जगदीश देवड़ा
वित्त मंत्री, मप्र

वर्ष 2026-27 का बजट विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की ओर एक बड़ा कदम है। इस बजट से मप्र जैसे तेजी से विकसित हो रहे राज्य को भी लाभ मिलेगा। पूंजीगत व्यय में हमारा प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। अब कैपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया गया है। बजट में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष पूंजीगत सहायता योजना में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जो पिछले वर्ष से 50 हजार करोड़ रुपए अधिक है। इस योजना में मप्र को लगभग 15 हजार करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना होगी। इससे अधोसंरचनात्मक ▶▶ शेष पेज 19 पर

आर्थिक हालात को धरातल पर ले जाने वाला बजट

तरुण भनोट
पूर्व वित्त मंत्री मप्र

केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों के कारण हर वर्ग परेशान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में किसी भी वर्ग को राहत देने की बात नहीं की गई। रिजर्व बैंक के पास जो कोष है, उसका उपयोग ब्याज में राहत देने में किया जाता तो लोगों का धंधा बढ़ता। आमदनी बढ़ती लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। केंद्र की आर्थिक नीतियों के कारण देश के आर्थिक हालात धरातल पर जा रहे हैं। इसलिए ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार की जरूरत थी लेकिन बजट में ऐसे कोई संकेत नहीं मिले। इसीलिए, बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। इससे न किसी वर्ग को ▶▶ शेष पेज 19 पर

युवाओं, महिलाओं व उद्योगों पर रहेगा फोकस

राघव जी भाई
पूर्व वित्त मंत्री मप्र

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में रोजगार के लिए युवा और महिलाओं सहित छोटे उद्योगों पर फोकस किया गया है। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, कृषि के क्षेत्र में और प्रयास करने की आवश्यकता थी। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स पर भी काम किया गया है। कुल मिलाकर छोटे व्यापारियों और महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में राहत देने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में 40 हजार करोड़ का प्रावधान है। 10 हजार लोगों को पर्यटक गाइड के रूप में ट्रेनिंग ▶▶ शेष पेज 19 पर

बजट में खास

शिक्षा के क्षेत्र को सौगात

- 01 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
- 05 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापना की घोषणा
- 04 टेलीस्कोप/खगोल विज्ञान सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी
- 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना
- 15000 माध्य. स्कूलों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना
- डिजिटल नॉलेज ग्रिड खोले जाएंगे
- हर जिले में छात्राओं के लिए होगी गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना

स्वास्थ्य क्षेत्र में ये नए संस्थान खोलने की घोषणा

- 05 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापना की घोषणा
- 02 नए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान खुलेंगे
- 03 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनेंगे
- 17 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म
- 1,000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनेगा
- 07 नए आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव
- 07 पहले से मौजूद संस्थान होंगे अपडेट
- भारत ग्लोबल बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा
- कैंसर व शुगर की दवाइयां होंगी सस्ती
- एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के नए संस्थान बनेंगे
- वेटनरी और पैरा-वेट कॉलेज/अस्पताल की स्थापना

हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, मेडिकल में बढ़ी सुविधा तीन आयुर्वेदिक एम्स, पांच चिकित्सकीय पर्यटन केन्द्र

बजट 2026-27 में शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें 55,727 लाख करोड़ रुपए उच्च शिक्षा विभाग और 83,562 लाख करोड़ रुपए स्कूल और साक्षरता विभाग के लिए हैं। इस बार शिक्षा के लिए आवंटित बजट पिछले वर्ष की तुलना में 8.27 फीसदी अधिक रहा। सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए बजटीय प्रावधान करते हुए भविष्य की तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौशल विकास और मेडिकल शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। साथ ही, देश के हर जिले में महिला छात्रावास खोलने की भी घोषणा की गई है। बजट में टियर-2 और टियर-3 कस्बों में कॉर्पोरेट मित्र बनाने की भी घोषणा की गई है, जिससे पेशेवर संस्थानों को सुविधा और प्रशिक्षण मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस बजट का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

शिक्षा बजट 8.27% बढ़कर हुआ 1.39 लाख करोड़ रुपए

पिछले वर्ष से 8.27% **अधिक आवंटन**

2026-27 के लिए शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं 2025-26 के बजट में शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल 1,28,650 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।

दवा उत्पादन के लिए दस हजार करोड़ किए जाएंगे खर्च

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत के दवा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के लिए अगले 5 साल में 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में हम दुर्लभ दवाओं के लिए विदेशों पर निर्भर है लेकिन इस पहल से अब भारत में ही आधुनिक दवाओं का निर्माण होगा और भारत दुनिया को दवाई सप्लाई कर सकेगा। देश में ऐसे पहले से ही 7 संस्थान मौजूद हैं और इन्हें भी आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। जिला अस्पताल आधुनिक तकनीक से लैस होंगे तथा इमरजेंसी वार्ड की संख्या भी बढ़ाई जाएंगी।

क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनेगा

वित्त मंत्री ने दवाओं के साथ उसके विशेषज्ञों की भी जरूरत पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पूरे देश में 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके जरिए थेरेपी और दवाओं की जांच जल्दी से हो जाएगी। ऐसे में देश में तीन नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खोले जाने की घोषणा हुई है।

स्कूलों व कॉलेजों में 'कन्टेंट क्रिएटर लैब' बनेंगी

सरकार ने माना है कि भविष्य 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' और 'डिजिटल कंटेंट' का है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कन्टेंट क्रिएटर लैब' बनाने का फैसला लिया गया है। युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए 'एआई एप्लीकेशन' पर आधारित विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, जिससे देश की युवा शक्ति डिजिटल युग के लिए पूरी तरह तैयार हो सके।

गर्ल्स हॉस्टल और जिला अस्पतालों का कायाकल्प

महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के हर जिले में एक 'गर्ल्स हॉस्टल' बनाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला अस्पतालों की क्षमता में 50% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। लघु उद्योगों की मदद के लिए सरकार एक अनूठी योजना लेकर आई। सीए, सीएस और सीएमए जैसे संस्थान अब शॉर्ट टर्म कोर्स तैयार करेंगे, जिससे देश में 'कॉर्पोरेट मित्र' तैयार होंगे। ये एक्सपर्ट्स विशेष रूप से छोटे शहरों के व्यापारियों और उद्योगों को प्रोफेशनल मदद देंगे। आईआईएम की मदद से 10 हजार टूरिस्ट गाइड्स तैयार किए जाएंगे।

बेटियों की पढ़ाई में अब नहीं आएगी कोई रुकावट

अक्सर देखा जाता है कि गांव या छोटे शहर की लड़कियों को बड़े कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन वहां रहने का इंतजाम करना बहुत महंगा और मुश्किल होता है। बजट में लिया गया यह फैसला लड़कियों को कॉलेज तक पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होगा। जब हर जिले में अपना एक हॉस्टल होगा, तो मां-बाप भी बिना किसी डर के अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए भेज सकेंगे। इससे न केवल पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या कम होगी, बल्कि लड़कियां खुद को ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करेंगी। यह कदम महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की तरह देखा जा रहा है।

7 दवाओं से कस्टम ड्यूटी खत्म

सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसके अलावा, कई दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से मंगवाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे उन परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी जो इलाज के लिए महंगी विदेशी दवाओं पर निर्भर हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत के दवा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के लिए अगले 5 साल में 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में हम दुर्लभ दवाओं के लिए विदेशों पर निर्भर है लेकिन इस पहल से अब भारत में ही आधुनिक दवाओं का निर्माण होगा और भारत दुनिया को दवाई सप्लाई कर सकेगा। देश में ऐसे पहले से ही 7 संस्थान मौजूद हैं और इन्हें भी आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा।

युवाओं पर फोकस

युवाओं के सपनों को पांव रफ्तार से दौड़ेगा देश

सरकार ने आम बजट में सबसे बड़ी धुरी 'युवा शक्ति' और 'आधुनिक तकनीक' को बनाया है। सरकार ने इस बजट के जरिए न केवल शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने की कोशिश की है, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए बायो-फार्मा और एआई जैसे उभरते क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि सरकार युवाओं को 'जॉब सीकर' के बजाय 'जॉब क्रिएटर' बनाना चाहती है। बजट में टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए भी विशेष रोडमैप तैयार किया गया है जो रोजगार व व्यापार में सहायक बनेंगे। बायो-फार्मा व एआई क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

बायो-फार्मा और मेडिकल सेक्टर में आएगी क्रांति

सरकार ने भारत को दुनिया का मेडिकल हब बनाने के लिए सरकार ने 'बायो फार्मा शक्ति' योजना का ऐलान किया है। अगले पांच सालों में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत को ग्लोबल बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत तीन नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च खुलेंगे। वहीं 7 पुराने संस्थानों को आधुनिक बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, पशुपालन के क्षेत्र में भी 20 हजार नए वेटरनरी प्रोफेशनल तैयार करने के लिए विशेष कॉलेज खोले जाएंगे।

बुजुर्गों को रेल यात्रा में नहीं मिली छूट बाकी सब यथावत

भारतीय रेलवे ने कोरोना महामारी के बाद से बुजुर्गों को सफर में मिलने वाली रियायत खत्म कर दी थी। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार वित्त मंत्री अपने पिटारे से यह तोहफा जरूर देंगी लेकिन ऐसी किसी भी प्रकार की घोषणा इस बजट में नहीं की गई जिससे बुजुर्गों को निराशा हाथ लगी। वहीं बुजुर्गों के लिए इनकम टैक्स की मौजूदा छूट सीमा भी पूर्व जैसे ही यानी 60 से 79 साल की उम्र वालों के लिए टैक्स छूट 3 लाख रुपए और 80 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 5 लाख रुपए ही रहेगी।

महिलाओं को मिला शी-मार्ट का तोहफा

- ग्रामीण महिलाओं के लिए स्व-स्हायता उपक्रम शी-मार्ट का ऐलान
- भारत- विस्तार एआई टूल्स से कृषि उत्पादन में होगी सहायता
- पीएम दिव्यांशा केंद्रों को बनाया जाएगा मजबूत

रोजगार के क्षेत्र में घोषणा

- 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' योजना
- खादी हथकरघा क्षेत्र को दिया जाएगा बढ़ावा
- निर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को मजबूती देने का लक्ष्य

केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए एक नई पहल शी-मार्ट की घोषणा की है। यह योजना महिलाओं के व्यवसाय और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई है। ताकि महिलाओं को और अधिक आर्थिक अवसर मिल सकें। शी-मार्ट्स समुदाय-संचालित रिटेल आउटलेट होंगे जहां स्व सहायता समूह की महिलाएं खुद का कारोबार चला सकेंगी।

महिलाओं की वार्षिक आय कम से कम एक लाख रुपए हो

वित्त मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की वह महिला सदस्य होती है जिसकी वार्षिक घरेलू आय कम से कम एक लाख रुपए हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, अब तक दो करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और लक्ष्य 2027 तक तीन करोड़ महिला एसएचजी सदस्यों की वार्षिक आय को एक लाख रुपए तक पहुंचाना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उधार पर निर्भर रहकर काम करने की बजाय स्वयं के व्यवसाय की मालिक बनने में सहायता देना है। इस योजना के तहत महिलाओं को कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता (लोन) भी उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि वे अपने व्यापार को मजबूत कर सकें। बजट 2026 में महिलाओं के लिए यह नई पहल उनके आर्थिक सशक्तिकरण, उद्यमिता और स्वयं-का व्यवसाय चलाने वाली क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कदम है। लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इसे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के लिए 'उद्यमों के मालिक' बनने की दिशा में "अगला कदम" बताया।

आम बजट पर विशेषज्ञों का नजरिया

विकसित भारत के लिए मानव पूंजी निर्माण का मजबूत आधार प्रदान करता है सरकार ये बजट

संसद में पेश केंद्रीय बजट 2026-27 शिक्षा क्षेत्र के लिए युवा शक्ति को केंद्र में रखते हुए अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी साबित हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल आवंटन 1,39,285.95 करोड़ रुपए किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.27 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। स्कूल शिक्षा के लिए 83,561.41 करोड़ रुपए (लगभग 6.35 प्रतिशत वृद्धि) और उच्च शिक्षा के लिए 55,724.54 करोड़ रुपए (तेज वृद्धि) का प्रावधान किया गया है। सबसे सराहनीय पहलू लड़कियों की शिक्षा पहुंच बढ़ाना है। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल स्थापित करने की घोषणा से स्टीम और उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ेगी। इसके अलावा, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव रिसर्च, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट को एकीकृत मॉडल देगा। मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के सहयोग से 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित होंगी, जो युवाओं को एआई, डिजिटल क्रिएटिविटी और भविष्य की नौकरियों (2030 तक 20 लाख प्रोफेशनल्स की आवश्यकता) के लिए तैयार करेंगी। विदेशी शिक्षा के लिए टीसीएस दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने से छात्र परिवारों को राहत मिलेगी। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज हाई-पावर्ड कमेटी गठित कर शिक्षा को रोजगार से मजबूती से जोड़ेगी। कुल मिलाकर, यह बजट शिक्षा को मात्र आवंटन नहीं, बल्कि विकसित भारत के लिए मानव पूंजी निर्माण का मजबूत आधार प्रदान करता है।

प्रो. (डॉ.) केजी सुरेश
निदेशक, भारत पर्यावास केंद्र

सीमित संसाधनों में विकास का रोड मैप बनाना वास्तव में देश के लिए अच्छा बजट कहा जाएगा

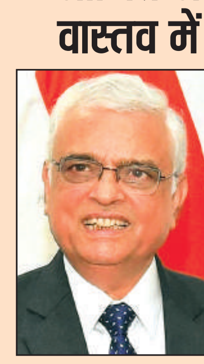

वित्त मंत्री सीतारमण ने अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। सीमित संसाधनों में देश के विकास का रोड मैप तैयार करना वास्तव में अच्छा बजट कह सकते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के बजट में इस वर्ष 21 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। ग्रामीण विकास और कृषि विभाग को जोड़कर देखें तो ग्रामीण विकास का काफी बजट हो गया है, जो गांव और किसान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्रामीण विकास के कुल बजट में अकेले 'विकसित भारत जी राम जी' योजना के लिए राज्यों के अंशदान सहित लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। पंचायतों को दोगुनी सीधी सहायता, विकसित और स्वावलंबी ग्राम की दिशा में बड़ा कदम है।

ओपी रावत, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

बजट में खास

कॉरपोरेट कर में न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) घटाकर 14%

होटल में रहने व ठहरने पर टीडीएस अब कुल व्यय राशि का सिर्फ 2%

भूमि अधिग्रहण से प्राप्त आय पर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को विशिष्ट छूट दी जाएगी

वायुसेना के आयातित इंजनों सहित एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट के पार्टों पर सीमा शुल्क शून्य किया

चबाने वाला तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू पर टैक्स 25% से बढ़कर 60%

मिश्रित कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) में प्रयुक्त बायोगैस/कम्प्रेस्ड बायोगैस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट

क्रिप्टो करंसी के संबंध में गलत विवरण देने पर अर्थदंड प्रतिदिन 200 रुपए, विवरण ठीक न करने पर 50,000 रुपए

रिटर्न अपडेट में एक्स्ट्रा आय बताने पर दंड नहीं लगाए जाने का प्रस्ताव

विवरण प्रस्तुत करने में भूल पर 7 साल के बजाए 2 वर्ष की सजा

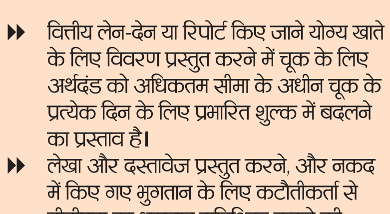

- वित्तीय लेन-देन या रिपोर्ट किए जाने योग्य खाते के लिए विवरण प्रस्तुत करने में चूक के लिए अर्थदंड को अधिकतम सीमा के अधीन चूक के प्रत्येक दिन के लिए प्रभारित शुल्क में बदलने का प्रस्ताव है।
- लेखा और दस्तावेज प्रस्तुत करने, और नकद में किए गए भुगतान के लिए कटौतीकर्ता से टीडीएस का भुगतान सुनिश्चित करने की अपेक्षा को पूरी तरह अपराध से बाहर करने का प्रस्ताव है।
- सभी अभियोजनों को युक्तिसंगत करते हुए सश्रम कारावास से बदल कर साधारण कारावास किया जाएगा।
- किसी अपराध (बार-बार के अपराध को छोड़कर) के लिए अधिकतम अधिकतम दंड को 7 वर्ष से कम करके 2 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
- ऐसे मामलों में जहां वर्तमान में अधिकतम दंड दो वर्ष है, वहां दंड को जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना तथा न्यूनतम कारावास की सीमा से रहित करते हुए कम करके 06 माह कर दिया गया है।
- यह भी प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम 2025 के तहत अपराधों के लिए अभियोजन बचाई गई कर की राशि के आधार पर होगा और दंड अपराध की गंभीरता के अनुपात में होगा। ऐसे मामलों में कारावास के अधिकतम दंड की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है और अनिवार्य जुर्माने की अपेक्षा को शिथिल करके वैकल्पिक बना दिया गया है।
- यह भी प्रस्ताव है कि गौण अपराध के लिए दंड के रूप में केवल जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा।

हर साल नया अंदाज...

साल 2019 | साल 2020 | साल 2021 | साल 2022 | साल 2023 | 2024 अंतरिम | साल 2024 | साल 2025 | साल 2026

आम आदमी छात्र और बुजुर्गों को वित्त मंत्री ने दिए ये खास तोहफे

इनकम टैक्स स्लैब जस के तस, थोड़ी फीस से 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न

नई और पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं

आम बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई और पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की आय ही आयकर से मुक्त रहेगी। हालांकि, आयकर अधिनियम के सेक्शन 87ए के तहत आप 5 लाख तक की आय पर कर बचा सकते हैं। वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 4 लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं देना होगा। इसमें आयकर अधिनियम के सेक्शन 87ए के तहत वेतन प्राप्त करने वालों को 12.75 लाख रुपए तक की आय पर और अन्य 12 लाख तक की आय पर कर छूट पा सकते हैं।

टैक्स को लेकर ये बड़े बदलाव

- **1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून:** केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया जाएगा। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें टैक्स रेट्स या स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, इसके जरिए सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी।
- **विदेश यात्रा करना हुआ सस्ता:** बजट में आम आदमी का विदेश घूमना हुआ सस्ता। विदेश यात्रा करने वालों के लिए ओवरसीज टूर पैकेज पर टीसीएस अब सिर्फ 2% होगा, जो पहले 5% और कुछ मामलों में 20% तक था। इससे घूमने-फिरने का खर्च तुरंत बढ़ने से बचेगा।
- **31 मार्च तक फाइल कर सकेंगे रिवाइज्ड रिटर्न** इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में सुधार करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब मामूली फीस देकर 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकेगा।

इन चीजों को समझिए

पुरानी में 2.5 लाख और नए में 12 लाख रुपए तक की आयकर छूट

सवाल 1: पुरानी और नई टैक्स रिजीम में क्या अंतर है?

जवाब: नए टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपए तक की कमाई आय कर मुक्त रहती है, लेकिन इसमें टैक्स डिडक्शन नहीं मिलते हैं। वहीं, अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।

सवाल 2: पुरानी टैक्स रिजीम में किस तरह की छूट मिलती है?

जवाब: अगर आप ईपीएफ, पीपीएफ और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में निवेश करते हैं। तो आपकी कुल कर योग्य आय में से ये आय कम हो जाएगी। वहीं, मेडिकल पॉलिसी पर किए गए खर्च, होम लोन पर चुकाए गए ब्याज और नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश किए गए रुपए भी आपकी कर योग्य आय से घट जाते हैं।

सवाल 3: पुरानी टैक्स रिजीम किन लोगों के लिए बेहतर है?

जवाब: अगर आप निवेश और टैक्स छूट का फायदा लेना चाहते हैं, तो पुरानी टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकती है। वहीं अगर आप कम टैक्स रेट और टैक्स डिडक्शन के झंझटों से बचना चाहते हैं तो नई टैक्स रिजीम आपके लिए सही हो सकती है।

टीडीएस के लिए अब आवेदन नहीं

- **टीडीएस न कटवाने के लिए आवेदन की जरूरत नहीं:** टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) नहीं कटवाने के लिए अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। नियमों के अनुसार अब अगर आप पर इनकम टैक्स नहीं बनता है तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अभी इसके लिए फॉर्म 15जी (60 साल से कम वालों के लिए) या फॉर्म 15एच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) जमा करना होता था।
- **फ्यूचर-ऑप्शंस ट्रेडिंग करना महंगा:** सरकार ने फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है। ऑप्शंस पर भी एसटीटी को बढ़ाकर 0.15% किया गया है। इसे ट्रेडिंग करना महंगा हो जाएगा।

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026-25 में इनकम टैक्स को लेकर किसी तरह की राहत नहीं दी है। बजट में इनकम टैक्स को लेकर को कोई बड़ी घाोषणा नहीं हुई है। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की गई है। वहीं, विदेश रुपए भेजने पर अब 5% के बदले 2% टैक्स लगेगा। कर विशेषज्ञों के अनुसार सरकार ने पिछले बजट में ही न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स छूट को 7 लाख बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया था। ऐसे में इस साल बदलाव होने की संभावना न के बराबर ही थी। हालांकि, बजट 2026 में आम आदमी, मध्यमवर्गीय परिवारों, छात्रों और बुजुर्गों के लिए कई अहम राहत भरे कदम उठाए गए हैं। बजट में इन पर टैक्स का बोझ कम, आसान नियम और सुरक्षित, बचत के लिए नियम लाए हैं। सरकार ने इसे 'परिवारों की समृद्धि से राष्ट्र की मजबूती' के लक्ष्य से जोड़ा है। अब विदेश से यात्रा के दौरान एक लैपटॉप को पर्सनल सामान के साथ लाने पर स्पष्ट नियम तय कर दिए गए हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए कस्टम डिक्लेरेशन और ड्यूटी पेमेंट की सुविधा दी जाएगी, जिससे एयरपोर्ट पर लगने वाला समय और तनाव दोनों कम होंगे।

छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए आसान मौका

- विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों और उनके परिवारों के लिए बजट राहत लेकर आया है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत शिक्षा और मेडिकल खर्चों के लिए भेजी जाने वाली राशि पर टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है, जो पहले 5% होता था। इससे छात्रों पर शुरुआती वित्तीय बोझ कम होगा, एजुकेशन लोन पर निर्भरता घटेगी और इंपोर्टेड स्टडी मटेरियल या पार्सल की क्लियरेंस भी तेज होगी।

टीडीएस की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड

- छोटे करदाताओं के लिए लोअर या निल टीडीएस सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड होगी। अब अफसरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ी राहत देते हुए 17 कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म की गई है। वहीं 7 और दुर्लभ बीमारियों के इलाज से जुड़े दवाइयों और विशेष भोजन को भी ड्यूटी-फ्री किया गया है। यह छूट बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

अत्यधिक सट्टेबाजी रोकने के लिए वित्त मंत्री ने सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ाया

शेयर बाजार के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में एसटीटी बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया

निफ्टी 25500 के नीचे गया और बाद में 25800 के ऊपर क्लोज हुआ

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान जैसे ही शेयर बाजार के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में एसटीटी टैक्स को बढ़ाने का ऐलान किया, उसके बाद ही मार्केट में गिरावट हावी हो गई। इंट्रा में निफ्टी 25500 के नीचे चला गया और उतार-चढ़ाव के बाद 25800 के ऊपर क्लोज हुआ। वित्त मंत्री ने बताया कि एसटीटी में बढ़ोतरी मामूली है और इसका एकमात्र उद्देश्य अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसटीटी में वृद्धि केवल वायदा और विकल्प सौदों पर ही लागू होगी, क्योंकि इनमें अत्यधिक सट्टेबाजी और जोखिम शामिल है।

क्या होता है एसटीटी?

एसटीटी (सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स) एक प्रकार का टैक्स है जो शेयर बाजार में शेयरों की खरीद-बिक्री पर लगता है। शेयर, डेरिवेटिव्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदते या बेचते समय यह टैक्स लागू होता है। इस टैक्स को सरकार ने साल 2004 में शुरू किया था ताकि शेयर बाजार में सट्टेबाजी कम हो और सरकार को टैक्स से कमाई हो सके। फ्यूचर सेगमेंट में एसटीटी को पहले के 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। वहीं, ऑप्शंस पर एसटीटी बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है, जो कि पहले 0.10 फीसदी था।

करों से 44,04,086 करोड़ की आय

वर्ष 2026-27 में सरकार को टैक्स से कुल 44,04,086 करोड़ की आय होने का अनुमान है। इसमें इनकम टैक्स से 14,66,000 करोड़, कंपनियों पर लगने वाले टैक्स से 12,31,000 करोड़, जीएसटी से 10,19,020 करोड़, एक्साइज ड्यूटी से 3,88,910 करोड़ और कस्टम ड्यूटी से 2,71,200 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि जीडीपी की तुलना में टैक्स रेवेन्यू घटने की आशंका है। 2026-27 में 11.2% रहने का अनुमान है।

लागत कम कर उत्पादन बढ़ाने पर जोर

नवकरणीय और नाभिकीय उर्जा विमान के इंजन, पुर्जों पर 0 टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आदान लागत कम करने, घरेलू विनिर्माण पर बल देने तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कई मदों पर सीमा-शुल्क डयूटी कम किए जाने का प्रस्ताव रखा है। महत्वपूर्ण खनिज मोनाजाइट पर मूल सीमा शुल्क ड्यूटी की दर 2.5% से घटाकर शून्य कर दी गई है। एयरक्राफ्ट और उनके विनिर्माण के लिए एयरक्राफ्ट के इंजनों सहित उसके घटक या पार्ट पर सीमा शुल्क पूरी तरह से शून्य किए जाने का प्रस्ताव है।

सौर ग्लास पर सीमा शुल्क शून्य

नवकरणीय ऊर्जा के तहत सौर ग्लास के विनिर्माण में उपयोग हेतु सोडियम एंटीमोनेट 7.5% से कम करके शून्य, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की बैटरियों के लिए लिथियम ऑयन सेलों के विनिर्माण में उपयोग हेतु वस्तुएं शून्य कर पर उपलब्ध होंगी। नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपेक्षित वस्तुएं पर सीमा शुल्क ड्यटी शून्य कर दी गई है।

आम बजट पर विशेषज्ञों का नजरिया

शिक्षा पर समग्र दृष्टिकोण, तकनीकी कौशल के साथ युवाओं को रोजगार

डॉ. भूपेंद्र सुल्लेरे
शिक्षाविद
भोपाल

केंद्रीय बजट में शिक्षा को मानव पूंजी का मूल आधार मानते हुए स्कूली, तकनीकी और उच्च शिक्षा दोनों में निवेश और सुधार पर बल दिया गया है। बजट में सरकारी स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब तथा डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे कदमों से सीखने की गुणवत्ता और तकनीकी कौशल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवा आधुनिक रोजगार के अवसरों के लिए तैयार होंगे। साथ ही, हर जिले में लड़कियों के होस्टल और नए डिजाइन/ क्रिएटिव संस्थान जैसे उच्च शिक्षा संवर्धन प्रस्ताव हैं, जो लिंग समानता और समावेशी शिक्षा को मजबूत करेंगे। बजट में नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप, उन्नत तकनीकी पाठ्यक्रम, शोध-उन्मुख केंद्रों और विद्यालय-विश्वविद्यालय लिंकिंग को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है, जिससे भारत वैश्विक शिक्षा-केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एजुकेशन टू इम्प्लॉयमेंट कमेटी जैसे संस्थागत ढांचे का प्रस्ताव रखा है, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच पुल मजबूत होगा।

स्थिर नीति, संतुलित आर्थिक संकेत और राजकोषीय अनुशासन से विश्वास बढ़ा

प्रो. हिमांशु राय
निदेशक
आईआईएम, इंदौर

केंद्रीय बजट 2026 की एक उल्लेखनीय विशेषता इसकी नीतिगत स्थिरता और पूर्वानुमेय आर्थिक दिशा है। सरकार ने राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि विकास को कर्ज-आधारित विस्तार के बजाए संतुलित संसाधन प्रबंधन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। यह दृष्टिकोण सार्वजनिक वित्त की विश्वसनीयता को मजबूत करता है और दीर्घकालिक आर्थिक योजना के लिए आवश्यक आधार तैयार करता है। पूंजीगत व्यय को रूपए 12.2 लाख करोड़ तक बनाए रखना यह दर्शाता है कि सरकार अल्पकालिक लोकप्रिय निर्णयों के बजाय आर्थिक क्षमता के निर्माण पर ध्यान दे रही है। बेहतर अवसंरचना और स्थिर नीतिगत माहौल का प्रत्यक्ष लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिल सकता है, जो कम लागत, बेहतर संपर्कऔर अधिक भरोसेमंद मांग वातावरण में विस्तार करने में सक्षम होंगे। नीति निरंतरता से इन उद्यमों के लिए निवेश और उत्पादन संबंधी निर्णय लेना सरल होता है। इस व्यापक आर्थिक ढांचे में शिक्षा को एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा के लिए 1.28 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन दर्शाता है कि सरकार मानव पूंजी में प्राथमिकता दे रही है।

क्या मीम्स बनाने वालों को बजट समझ आया?

वैसे तो हर बजट पर मीम्स बनते हैं। पर, इस बार मीम्स की बाढ़ नहीं आई क्योंकि, बजट तत्काल प्रभाव देने वाला नहीं है। वह दूरगामी प्रभाव का बजट है। इसलिए, मीम्स कम्युनिटी को बजट जल्दी और ठीक से समझ नहीं आया। यानि, हमारी वित्त मंत्री मीम्स वालों की तीखी प्रतिक्रियाओं से फिलहाल बच गईं। पर, जितना भी बजट समझ आया, इन मीम्स वालों ने उसका अपने अंदाज में आनंद लिया। आप भी लीजिएगा।

बजट-2026 पर मीम्स के माध्यम से कुछ व्यंग्यात्मक प्रतिक्रियाएं

ओए... चूना लगा दिया रे...

ये... ले और चाहिए तो बता देना बहुत माल है... अपने पास....

अब तो पैसा ही पैसा है भैया

सिगरेट पर 40% जीएसटी

का कहें भैया... बहुत मारे हैं

मैं तो टैक्स लूंगी, मेरा थैला तो भर गया, अब तुम जानो भैया

अब तो बल्ले-बल्ले आएगा ही आएगा

बजट के बाद बीड़ीबाजों की हालत में भी परिवर्तन दिखाई दिया

बजट से पहले

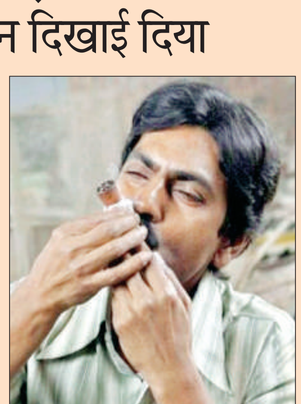
बजट के बाद

सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री सीतारमण का प्रतीकात्मक मीम्स दिनभर वायरल होता रहा। लोगों ने देखा और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दीं कहा- दीदी कह रही हैं लो अब आप जानो

आज पूरे दिन निर्मला ताई ही चर्चा में रहीं हैं क्यों?

बल्ले-बल्ले

यही तो...

ज्यादा भौंक रहे हो, बताऊं क्या....

ये मीम्स भी खूब वायरल हुआ। कुत्तों का झुंड भौंकने लगा तो फायरिंग कर चुप करा दिया

बजट से किस पर क्या असर होगा

चांदी में निवेश करने वाले

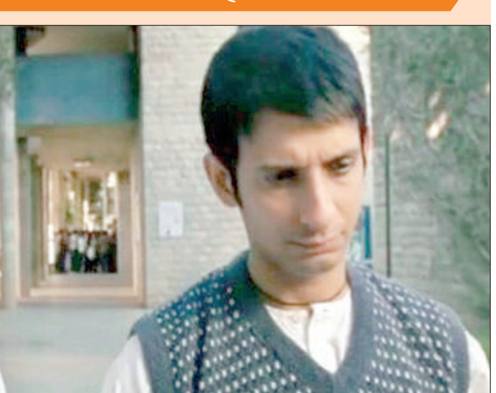
सोने में निवेश करने वाले

निवेशकों पर बजट का असर

दैनिक कारोबारियों का हाल भी कुछ इस तरह बयां किया गया

लंबे समय तक निवेश करने वालों की हालत इस तरह दिखी

उद्योगपति मुकेश अंबानी बजट पर शर्माए, निर्मला बोली-ठीक

कवियों की नजर में बजट

विकसित भारत के लक्ष्य की बात

नीतेश व्यास
भोपाल

विकसित भारत के लक्ष्य की बात।

2026 के बजट में सरकार की सौगात।

आत्मनिर्भर भारत की संकल्पित चाह।

राष्ट्रीय फाइबर योजना से बनेगी राह।

कैंसर जैसी दुर्लभ बीमारियों से जल्द मिले आराम।

नए बजट में सरकार ने सस्ते किए दवाओं के दाम।

इलेक्ट्रिकल व्हीकल सोलर पैनल ग्रीन एनर्जी को मिला दम।

ऐसे उपकरणों के उत्पादन बढ़े इसलिए हुई ड्यूटी कम।

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज शुरू करने का प्रस्ताव।

खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प कला की मजबूती में दिखेगा प्रभाव।

न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में भी दिखेगी ब्यूटी।

आयातित उपकरणों पर नहीं लगी कस्टम ड्यूटी।

बजट न डराता है, न हंसाता है

डॉ.संदीप शर्मा
धार

बजट ऐसा आया है कि न टैक्स पूरी तरह डराता है
न पूरी तरह हंसाता है
मध्यम वर्ग की आदत के अनुसार संयम में
खुश रहना सिखाता है
फिर जेब हल्की होने की तैयारी है
पर हां - इरादे बहुत भारी हैं
पीड़ा पर कर का भार नहीं है
कम यह भी उपहार नहीं है
सस्ते रेशम, जूट की बात
राहें कठिन, पर सस्ते बूट की सौगात
यह नहीं कह सकते कि विकास का मौका नहीं है
सपने बढ़े हैं इरादों में धोखा नहीं है

1.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए

भारत-विस्तार एआई टूल, किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य

भारत-विस्तार एआई टूल की मदद से किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। अपने नौवें बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और एआई के इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एआई का बूस्ट मिलेगा, जो किसानों को एडवांस खेती के तरीकों के बारे में बताएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 'भारत विस्तार' की घोषणा की है। यह एक एआई बेस्ड पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी मदद से एग्रीकल्चर सेक्टर, खास तौर पर किसानों को फायदा होगा।

बजट में 500 रिजरवॉयर में मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा

बजट में मछली पालन को बढ़ावा देने का ऐलान किया। 500 रिजर्वायर में मछली पालन को बढ़ावा दिया। अमृत सरोवरों में मछली पालन को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत करने का लक्ष्य है। मछली पालन में स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा मिलेगा। इसमें महिला-नेतृत्व वाले समूहों को भी जोड़ा जाएगा। फिश फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गनाइजेशन बजट में गांव में रोजगार बढ़ाने पर फोकस होगा। एनिमल हसबेंड्री में आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा। क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के जरिए आसान फंडिंग होगी। पशुपालन के विस्तार और आधुनिकीकरण पर जोर है।

05 लाख रुपए हुई केसीसी के तहत सब्सिडी वाले अल्पकालिक ऋण

नारियल और चंदन जैसी हाई-वैल्यू फसलों के समर्थन के लिए कोकोनट प्रोत्साहन योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। पशुपालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। दुग्ध, पोल्ट्री और पशु व्यवसायों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और वैल्यू चेन से किसान संगठनों को बढ़ावा मिलेगा। नारियल और चंदन जैसी हाई-वैल्यू फसलों के समर्थन के लिए कोकोनट प्रोत्साहन योजना की मदद से 1 करोड़ किसानों और 3 करोड़ लोगों की मदद की जाएगी।

कोकोनट से जुड़े तीन करोड़ लोगों को मदद

अखरोट, बादाम, खुमानी को भी प्रोत्साहित करेंगे

एआई एग्री टूल, उत्पादकता बढ़ाने में होगा सहायक

डेयरी और मुर्गी पालन पर सरकार का बड़ा फोकस

डेयरी और मुर्गी पालन को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। इन क्षेत्रों से लाखों किसान और छोटे परिवार जुड़े हुए हैं। सरकार चाहती है कि किसान दूध, अंडे और इससे जुड़े उत्पादों के जरिए स्थायी आमदनी कमा सकें।।

अब काजू और कोको को मिलेगी नई पहचान

कृषि बजट 2026 में काजू और कोको को भी खास जगह दी गई है। इसके साथ ही निर्यात को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। काजू और कोको से जुड़े उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए किसानों और उद्यमियों को सहायता दी जाएगी।

चंदन की खेती को फिर मिलेगा पुराना गौरव

वित्त मंत्री ने कहा कि चंदन सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। सरकार राज्यों के साथ मिलकर चंदन की खेती, संरक्षण और वैल्यू चैन विकास पर काम करेगी, ताकि इसकी खोई हुई गरिमा को फिर से बहाल किया जा सके। इस पर निर्भर लोगों की आय बढ़ने की उम्मीद है।

इन फसलों पर फोकस

महंगी फसलों का उत्पादन: सरकार ने इस बजट में हाई वैल्यू फसलों पर खास जोर दिया है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने और ज्यादा कमाई के लिए सरकार हाई वैल्यू उत्पादन जैसे काजू, अखरोट, नारियल, चंदन इत्यादि को सपोर्ट करेगी। इसके साथ ही सरकार ने काजू को प्रीमियम ब्रांड के रूप में रखा है। इससे एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी होगी।

पहाड़ी इलाकों में खेती को बढ़ावा : पहाड़ी इलाकों में होने वाली खेती जैसे अखरोट, बादाम, खुमानी इत्यादि को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसी स्कीम लागू की जाएगी जिससे भूगोल स्थिति की वजह से होने वाली परेशानी से राहत मिल सके।

चंदन की खेती पर भी दिया गया जोर: केंद्र, राज्य के साथ चंदन की खेती और कटाई के बाद होने वाले प्रोसेस पर फोकस है, ताकि चंदन को को ज्यादा बढ़ावा मिले। चंदन जैसे बढ़ती मांग और महंगी फसल फिर से पहचान बन सके।

बजट में खास

पशुपालकों के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना शुरू होगी

1.70 लाख करोड़ रु. से अधिक उर्वरक सब्सिडी, किसानों की लागत में राहत

पशुधन, मुर्गीपालन और डेयरी के लिए इंटीग्रेडेड वैल्यू चेन बनाने की योजना

सस्ते खाद के लिए 1,70,944 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान

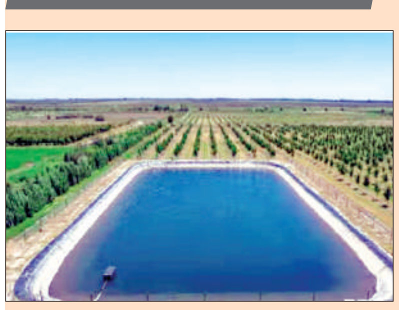

एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या हाई सीज में पकड़ी गई मछली पर शुल्क मुक्त किया

मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास शुरू होगा

कृषि शिक्षा और अनुसंधान विशेषकर आईसीएआर सहित, के लिए 9,967 करोड़ रुपए का प्रावधान

पिछले बजट में ये हुए थे नवाचार

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र को 137756.55 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को पिछले बजट में 63500 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। इस योजना का मकसद जमीन वाले किसानों की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत, देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड से हर साल 6000 रुपए की फाइनेंशियल मदद तीन बराबर चार महीने की किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को पिछले बजट में 120 करोड़ रु. का आवंटन हुआ था। इस योजना का मकसद सबसे कमजोर किसान परिवारों को सोशल सिक्योरिटी देना है। यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, जो कुछ शर्तों के तहत, पेंशन फंड में हर महीने पैसे जमा करके इस स्कीम के सदस्य बन सकते हैं।

संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना

संशोधित ब्याज सबवेंशन योजनाको पिछले बजट में 22600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। एमआईएसएस , फसल उगाने वाले किसानों और पशुपालन, डेयरी और मछली पालन जैसी दूसरी संबंधित गतिविधियों के लिए रियायती शॉर्ट टर्म कृषि लोन देती है। यह उन किसानों के लिए उपलब्ध है जो 3 लाख तक का शॉर्ट टर्म फसल लोन लेते हैं, जिस पर एक साल के लिए 7% सालाना ब्याज दर लगती है। लोन का समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाती है।

किसानों की प्रगति और विकास का बजट

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट 2026-27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने वाला ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बजट बताया है। यह बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने का महाकाव्य है। यह समाज की समृद्धि और संकल्पों की सिद्धि का बजट है। यह डेवलप्ड इंडिया का डायनामिक बजट है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और विज़न से प्रेरित यह बजट वर्ष 2047 के आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत की मजबूत नींव रख रहा है। कृषि विभाग का बजट बढ़ाकर इस वर्ष 1,32,561 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

लखपति दीदी और 'शी मार्ट': ग्रामीण बहनों को उद्यमी बनाने में होगा कारगर

शिवराज सिंह ने कहा कि लखपति दीदी योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए बजट में सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर शी मार्ट की व्यवस्था की गई है। हर ज़िले में बहनों के उत्पादों को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कम्युनिटी-ओन्ड रिटेल आउटलेट स्थापित होंगे, जहां स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण बहनों द्वारा तैयार उत्पादों को नया बाज़ार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पशुपालन, कृषि से जुड़ी गतिविधियों और अन्य कार्यों में लगी बहनें अब केवल आजीविका तक सीमित न रहकर उद्यमी के रूप में आगे बढ़ सकेंगी, यही इस पहल का उद्देश्य है।

शिवराज सिंह ने कहा कि लखपति दीदी योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए बजट में सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर शी मार्ट की व्यवस्था की गई है। हर ज़िले में बहनों के उत्पादों को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कम्युनिटीओन्ड रिटेल आउटलेट स्थापित होंगे, जहां स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण बहनों द्वारा तैयार उत्पादों को नया बाज़ार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पशुपालन, कृषि से जुड़ी गतिविधियों और अन्य कार्यों में लगी बहनें अब केवल आजीविका तक सीमित न रहकर उद्यमी के रूप में आगे बढ़ सकेंगी।

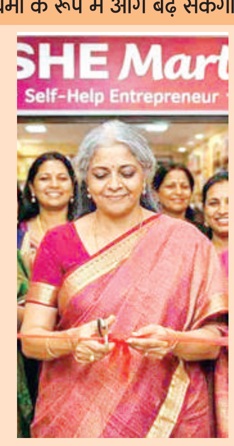

पंचायतों को दोगुनी सीधी सहायता

शिवराज ने कहा कि 16वें वित्त आयोग के ताज़ा निर्णय के अनुसार पंचायतों को सीधे 55,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जाएगी। पहले पांच वर्षों में पंचायतों को कुल लगभग 2,36,000 करोड़ रुपए सीधे मिले थे, जो अब बढ़कर 4,35,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। 'विकसित भारत जी राम जी' की 1,51,000 करोड़ रु. की राशि और वित्त आयोग के तहत मिलने वाले 55,900 करोड़ रु. मिलकर विकसित ग्राम, स्वावलंबी ग्राम, रोजगारयुक्त और गरीबीमुक्त गांव के निर्माण में अभूतपूर्व भूमिका निभाएंगे।

अनुसंधान और सस्ती खाद पर विशेष ज़ोर

कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने बताया कि कृषि शिक्षा और अनुसंधान, विशेषकर आईसीएआर सहित, के लिए 9,967 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे शोध और नवाचार को बल मिलेगा। किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी पर उन्होंने कहा कि सस्ता खाद और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 1,70,944 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है, ताकि उत्पादन की लागत कम हो और किसान को राहत मिले।

फाइबर-मेडिसिनल प्लांट्स से सीधा लाभ

नेशनल फाइबर स्कीम के अंतर्गत सिल्क, वूल और जूट जैसे फाइबर पर फोकस किया गया है, जिससे इनसे जुड़े किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। आयुष मंत्रालय में मेडिसिनल प्लांट्स के सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट से संबंधित प्रावधानों का फायदा औषधीय पौधे उगाने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। परंपरागत फसलों के साथ नारियल, कोको, काजू जैसी फसलों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

आम बजट पर विशेषज्ञों का नजरिया

किसान हितैषी मंशा पर खरा नहीं उतरा बजट

मोहिनी मोहन मिश्र
अखिल भारतीय महामंत्री
भारतीय किसान संघ

केंद्र सरकार का आम बजट में छोटे किसानों की समस्याएं, कृषि यंत्रों पर जीएसटी अधिक होना, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी कार्ड) की 5 लाख रुपए तक की सीमा बढ़ाने की घोषणा करने के बावजूद उसका क्रियान्वयन न होना, प्राकृतिक खेती का लक्ष्य घोषणा करने के बाद भी प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को डीबीटी के माध्यम से अपना जैविक खाद बनाने को प्रोत्साहन न देना चिंता का विषय है। प्राकृतिक खेती के समर्थन में देशभर में सारी फसलों में रसायन की मात्रा के स्तर की जांच बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस बजट में कोई योजना नहीं है। बजट में 500 अमृत सरोवर का एकीकृत विकास और पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता की सहायता करना जैसी योजना एक अच्छा कदम है। इससे अंतर्देशीय मत्स्य पालन मजबूत होगा। ग्रामीण महिला समूहों को सशक्त बनाने शी मार्ट की स्थापना भी अच्छी पहल है। इससे स्थानीय स्वयं सहायता समूह भी मजबूत होंगे। किसान परिवार के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को किसान हितैषी मांगों को शामिल कर बजट में संशोधन करना चाहिए। ताकि देश भर के जरूरतमंद किसानों का जीवन आसान हो सके।

किसान विरोधी बजट है, किसान निराश

धर्मेंद्र सिंह चौहान
अध्यक्ष, मप्र किसान कांग्रेस

कांग्रेस ने बजट को लेकर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मप्र ही नहीं देशभर के किसानों को हाशिए पर धकेल दिया। बजट में खेती को लेकर कोई राहत नहीं दी, उपकरण को लेकर भी कोई राहत नहीं दी। जीएसटी में कोई कमी नहीं की गई। किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य उपकरण खरीदने को लेकर कोई राहत नहीं है। यह निराशाजनक और किसान विरोधी बजट है। किसानों को बजट से भारी निराशा हुई है। फिर एक बार साबित हो गया कि भाजपा सरकार केवल पूंजीपतियों की है, किसानों से की समस्याओं से कुछ नहीं लेना देना है। यूरिया खाद की बोरी पहले जहां 43 किलो की आती थी। अब उसे 40 किलो कर दिया। धर्मेंद्र सिंह चौहान ने मांग की कि किसानों की उपज एमएसपी पर ही खरीदी करने का ऐलान होना चाहिए था।

आम बजट 2026

कार्टूनिस्ट हरिओम की नजर में बजट

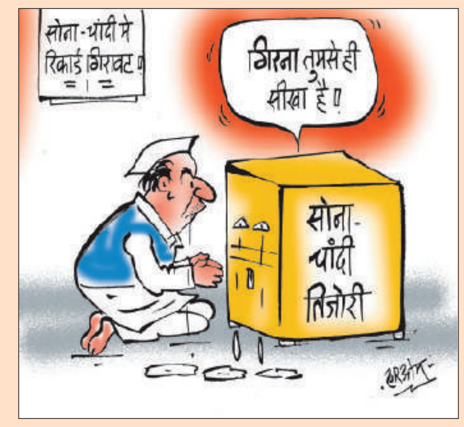

जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट

राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह जनभावनाओं और जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह बजट प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त आधार देता है।

'विकसित भारत' का ठोस ब्लूप्रिंट

धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा मंत्री

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए कहा है कि 'विकसित भारत बजट' सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। उनके मुताबिक यह बजट शिक्षा और रोजगार सृजन को नई रफ्तार देता है। साथ ही केंद्रीय बजट देश के विकास के अगले चरण के लिए एक साफ और मजबूत रोडमैप पेश करता है। धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में 'रेयर अर्थ कॉरिडोर' बनाने की घोषणा का स्वागत किया।

बजट बहुत अच्छा

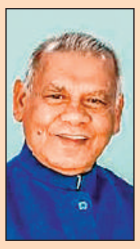

जीतन राम मांझी
केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा है कि एमएसएमई के माध्यम से भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में काफी प्रयास किया गया है, जो सराहनीय है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "मैं समझता हूं कि एमएसएमई के लिए ही ये बजट है, इसलिए क्योंकि ये एमएसएमई भारतीय आर्थिक व्यवस्था का ऋण है।

देश की युवा शक्ति का बजट

जेपी नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आम बजट को एक लोक-कल्याणकारी और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को नई दिशा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी एवं सर्वस्पर्शी है, जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। यह देश की युवा शक्ति का बजट है। इस ऐतिहासिक आत्मनिर्भर भारत के बजट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता।

बजट क्रांतिकारी, समाज के हर वर्ग को छूता है

रामदास अठावले
आरपीआई
सांसद

आरपीआई सांसद रामदास अठावले ने केंद्रीय बजट को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि यह समाज के सभी वर्गों को संबोधित करता है और सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। अठावले ने बताया कि निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट क्रांतिकारी है क्योंकि यह समाज के हर वर्ग को छूता है। यह सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों प्रदान करेगा।

अगले 25 वर्षों के लिए 'रोडमैप' पेश करेगा बजट : गृहमंत्री शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बजट भारत को वैश्विक मंच पर पारंपरिक से लेकर नये दौर के विभिन्न क्षेत्रों में सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने की रफ्तार को तेज करेगा। शाह ने कहा कि 'विनिर्माण से लेकर बुनियादी ढांचे तक, स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, खेल से लेकर तीर्थ स्थलों तक, विकसित भारत बजट एक ऐसा बजट है, जो हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं एवं किसानों के सपनों को सशक्त बनाता है, ताकि वे उन सपनों को साकार कर सकें।'

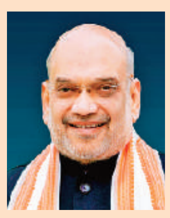

2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य

शाह ने कहा कि बजट राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने के लक्ष्य को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि बजट 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की परिकल्पना और अगले 25 वर्षों के लिए 'रोडमैप' पेश करता है। उन्होंने कहा, 'वित्त वर्ष 2026-27 के इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है। यह बजट न केवल हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए एक स्पष्ट खाका प्रस्तुत करता है, बल्कि इसे प्रोत्साहित करने के लिए एक ठोस दृष्टिकोण भी प्रदान करता है, जो हर कदम पर इसका समर्थन करेगा।

किसानों और हथकरघा उद्योग को नया समर्थन

विकसित भारत बजट एक ऐसे भारत के निर्माण का दृष्टिकोण है, जो विश्व के हर क्षेत्र में अग्रणी हो। गृह मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में योजना शुरू करने का एक ऐतिहासिक निर्णय बजट प्रस्ताव में लिया गया है। उन्होंने कहा, 'इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और बुनकरों, किसानों और हथकरघा उद्योग को नया समर्थन मिलेगा।' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तटीय क्षेत्रों में नारियल प्रोत्साहन योजना के माध्यम से तीन करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने, काजू और नारियल के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने तथा चंदन के संरक्षण का निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों की समृद्धि और कृषि को एक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

बदलेगी युवाओं-महिलाओं की तकदीर : सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट को 'विकसित भारत' की परिकल्पना का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह महिलाओं, युवाओं और आम जनता पर केंद्रित है। उन्होंने अवसंरचना विकास के लिए 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन की सराहना की, जिसमें सात नए रेल गलियारे शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्रीय बजट आम जनता पर केंद्रित है और महिला-केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य 2047 तक "विकसित भारत" के मिशन को हासिल करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने 'विकसित भारत' का रोडमैप तैयार करते हुए आज केंद्रीय बजट पेश किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को बजट दिशा-निर्देशों के मार्गदर्शन और देखरेख के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी इस बजट को पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

विकसित भारत' के मिशन का प्रतीक

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बजट में सात रेल गलियारों के निर्माण सहित अवसंरचना विकास के लिए 12 लाख रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के 145 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को दर्शाता है।

आने वाली पीढ़ियों के फायदे के लिए बनाया गया बजटः जी किशन रेड्डी

केंद्रीय बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट में खानों और जरूरी खनिजों के लिए एक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है और जरूरी खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए विदेश से आयात किए जाने वाले उपकरणों पर टैक्स में छूट भी दी गई है। इसके साथ ही, बजट में रोजगार पैदा करने, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर ध्यान दिया गया है और फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, कृषि सेक्टर और कपास सेक्टर जैसे दूसरे सेक्टरों के लिए कई सुधार शामिल हैं। यह चुनावी बजट नहीं है। यह आने वाली पीढ़ियों के फायदे के लिए बनाया गया बजट है। इसी तरह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत अब देश में रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर बनाने पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिन्हें हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं जबकि हमारे पास खदानें हैं, हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज है।

खरगे ने कहा दिशाहीन बजट, किसान बेहाल

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्रीय बजट 2026 को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के पास कोई नए विचार नहीं बचे हैं और बजट में विनिर्माण, किसान, रोजगार और बढ़ती असमानता जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए कोई नीतिगत दूरदर्शिता नहीं है। खरगे ने केंद्रीय बजट को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि इसमें देश की गंभीर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत दूरदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मेक इन इंडिया कहां है और दावा किया कि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 13% पर अटकी हुई है। खरगे ने किसानों के लिए समर्थन की कमी पर भी निराशा व्यक्त की और कहा कि वे अभी भी सार्थक कल्याणकारी सहायता या आय सुरक्षा योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि असमानता ब्रिटिश राज के समय के स्तर को भी पार कर गई है, लेकिन बजट में इसका उल्लेख नहीं है और न ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को कोई सहायता प्रदान की गई है।

मोदी सरकार के पास कोई नए विचार नहीं

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी सरकार के पास अब कोई नए विचार नहीं बचे हैं। बजट 2026 भारत की अनेक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का एक भी समाधान नहीं देता। 'मिशन मोड' अब 'चुनौती मार्ग' बन गया है। 'सुधार एक्सप्रेस' शायद ही किसी 'सुधार' जंक्शन पर रुकती है। नतीजाः कोई नीतिगत दूरदृष्टि नहीं, कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं। हमारे अन्नदाता किसान अभी भी सार्थक कल्याणकारी सहायता या आय सुरक्षा योजना का इंतजार कर रहे हैं। असमानता ब्रिटिश राज के समय के स्तर को भी पार कर गई है, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं है और न ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को कोई सहायता प्रदान की गई है।

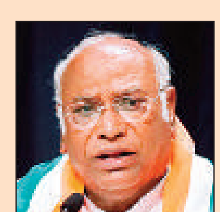

संघवाद को भारी नुकसान

खरगे ने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों का और अधिक अध्ययन करना होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकारों को कोई राहत प्रदान करती हैं। संघवाद को भारी नुकसान हुआ है।

विकसित भारत का बजट

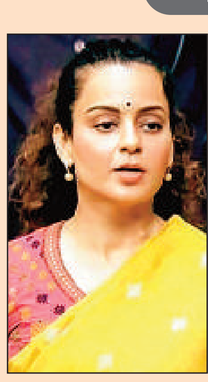

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने पर्यटन, पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाली योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा, यह विकसित भारत का बजट है। हम विकसित भारत के लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि भारत में ट्रेकिंग और प्रकृति-आधारित पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं। ये योजनाएं स्थानीय रोजगार बढ़ाएंगी, पर्यावरण की रक्षा करेंगी और पर्यटकों को बेहतर अनुभव देंगी। ये घोषणाएं हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए खास फायदेमंद साबित होंगी।

-कंगना रनौत
सांसद

दिशाहीन, इसमें कुछ नहीं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इसमें शिक्षा क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया गया है और इसने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। उन्होंने केंद्र पर जानबूझकर पश्चिम बंगाल को आवंटन में नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और दावा किया कि भाजपा को आगामी विधानसभा चुनावों में हार की आशंका के चलते राज्य को दरकिनार किया गया है।

- **ममता बनर्जी**
मुख्यमंत्री
पश्चिम बंगाल

केरल के लिए कुछ नहीं

शशि थरूर
कांग्रेस सांसद

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बजट भाषण में केरल के लिए कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, जो निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि अभी हमने केवल भाषण सुना है, पूरा बजट दस्तावेज नहीं पढ़ा है, इसलिए हो सकता है कि आगे विवरण में कुछ बातें सामने आएं। लेकिन फिलहाल भाषण में जरूरी जानकारियों की कमी साफ नजर आती है।

टैक्स ब्यूएंसी बेहद कम

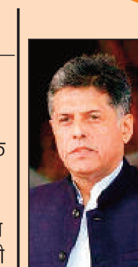

मनीष तिवारी
कांग्रेस सांसद

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बजट के आर्थिक पहलुओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक समस्याएं अभी भी जस की तस हैं। पिछले 10 वर्षों से नाममात्र जीडीपी में गिरावट देखने को मिली है और टैक्स ब्यूएंसी बेहद कम है, जिससे सरकारी राजस्व पर असर पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत खर्च बढ़ाया गया है, जिससे साफ है कि निजी निवेश अभी भी गति नहीं पकड़ पा रहा है।

जनता के साथ छलावा

अशोक गहलोत
पूर्व सीएम
राजस्थान

गहलोत ने केंद्रीय बजट को प्रदेश की जनता के साथ छलावा करार दिया है। बजट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का बजट भाषण में नाम तक न होना यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार का राज्य के प्रति रवैया 'सौतेला' है। उन्होंने कहा, प्रदेश को उम्मीद थी कि डबल इंजन सरकार होने का लाभ मिलेगा, लेकिन न तो किसी नई रेलवे परियोजना की घोषणा हुई और न ही जयपुर मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को कोई सहारा मिला।"

पारदर्शिता की कमी

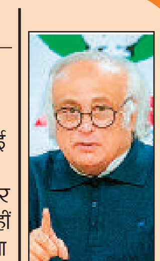

जयराम रमेश
कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए इसे बिल्कुल नीरस बताया है। रमेश ने बजट से जुड़ी कई कमियों को उजागर किया, जिनमें पारदर्शिता की कमी भी शामिल है और कहा कि बजट प्रचार के अनुरूप नहीं था। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कई प्रमुख कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन स्पष्ट नहीं किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि बजट पूरी तरह नीरस निकला।

5 फीसदी आबादी वाला बजट

अखिलेश यादव
सांसद

समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट गरीबों और गांवों में रहने वालों की समझ से परे है। इस बजट में न तो नौकरी दी गई है और न ही रोजगार के अवसर। उन्होंने कहा कि ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकती है। नौकरी रोजगार दिए नहीं। सपने दिखाने वाला बजट है।

विकसित भारत 2047 के लिए 'संकल्प से सिद्धि': नितिन नबीन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत 2047 के लिए 'संकल्प से सिद्धि' बताया। नितिन नबीन ने विनिर्माण क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनसे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं कर्तव्य भवन में तैयार किए गए बजट का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 'सबका साथ, सबका विकास' का सिद्धांत इस बजट में झलकता है। साथ ही, यह विकसित भारत 2047 के लिए 'संकल्प से सिद्धि' वाला बजट है।

बजट एक्सपर्ट व्यू

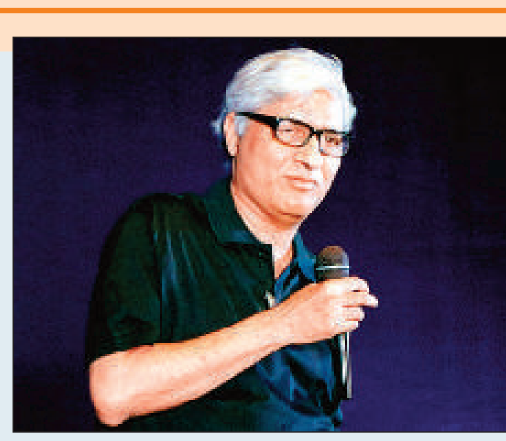

जवाहर सूरीसेट्टी
प्रख्यात मनोवैज्ञानिक

परिणाम आधारित रोजगार पर ध्यान

केंद्रीय बजट 2026, पारंपरिक डिग्री-आधारित शिक्षा के बजाय परिणाम-आधारित रोजगार क्षमता पर ध्यान केंद्रित है। यह विशेष रूप से शैक्षणिक स्नातक और नौकरी के बाजार की जरूरतों के बीच के अंतर को पाटने का लक्ष्य रखता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और क्रिएटिव इकोनॉमी जैसे उभरते क्षेत्रों पर भारी जोर दिया गया है। प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह एक रणनीतिक कदम है ताकि शिक्षा जगत और उद्योग जगत एक ही माहौल में साथ काम कर सकें, जिससे उच्च शिक्षा का अलगाव और उसकी व्यावहारिक दूरी कम हो सके। साथ ही, 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। यह कदम पारंपरिक कॉर्पोरेट नौकरियों के बजाय 'क्रिएटर इकोनॉमी' की ओर 'जेन-जी' की बदलती करियर प्राथमिकताओं को स्वीकार करता है।

बजट में **खास**

दिल्ली-वाराणसी समेत कुछ मार्गों पर दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेनें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 के साथ-साथ रेल बजट भी पेश किया है। इसमें एक ऐसी बड़ी घोषणा की गई है, जिससे रेलवे का सफर बिना रुकावट वाली तीव्र यात्रा बनने जा रही है। केंद्रीय बजट 2026 में हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का बनाने का ऐलान किया गया है। ये सात प्राइम रेल कोरिडोर्स होंगी जो सात रेल रूट्स को कनेक्ट करेंगी। इसके सबसे बड़ी बात ये होगी, कि ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होंगे.. जिन पर सिर्फ कुछ स्पेशल ट्रेनें दौड़ेंगी। इससे इन शहरों के बीच रेल सफर की आम समय सीमा घट जाएगी।

7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर

लोगों की यात्रा आसान करने बनाया जा रहा है तेज रेल नेटवर्क

ये हैं सात कॉरिडोर

- मुंबई-पुणे-महाराष्ट्र के इन दो बड़े शहरों के बीच सफर अब बहुत तेज होगा
- पुणे-हैदराबाद-महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ेगा
- हैदराबाद-चेन्नई-दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करेगा
- हैदराबाद-बेंगलुरु-आईटी हब बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच तेज कनेक्शन
- चेन्नई-बेंगलुरु-तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हाई-स्पीड लिंक
- दिल्ली-वाराणसी-राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी से जोड़ेगा। इससे पर्यटन और व्यापार बढ़ेगा।
- वाराणसी-सिलीगुड़ी-पूर्वी भारत को मजबूत कनेक्टिविटी देगा, खासकर बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए फायदेमंद

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में 7 नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। जो मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, वाराणसी और सिलीगुड़ी जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेंगे। ये कॉरिडोर भारत के प्रमुख शहरों को तेज और बेहतर तरीके से जोड़ेंगे। इससे यात्रा का समय बहुत कम हो जाएगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री ने इन हाईस्पीड रेल मार्गों को 'ग्रोथ कनेक्टर्स' यानी विकास के जोड़ने वाले बताया है। ये पर्यावरण के अनुकूल होंगे और लंबी दूरी की यात्रा को तेज, सुरक्षित और कम कार्बन वाला बनाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा) पर जोर देने का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है कि देश में तेज रेल नेटवर्क बढ़ाकर लोगों की यात्रा आसान हो। व्यापार तेज हो और रोजगार के मौके बढ़ें। फिलहाल मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अब इन 7 नए कॉरिडोर से भारत का रेल नेटवर्क और आधुनिक बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स देश को तेज विकास की राह पर ले जाएंगे। इससे शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। यह कदम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

सरकार सीप्लेन के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा के लिए देगी प्रोत्साहन

सीप्लेन वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव

विमानों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स और पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव

मोदी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए बड़े कदम

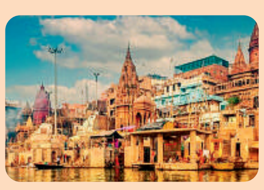

पूर्वोत्तर के छह राज्यों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने विशेष योजना

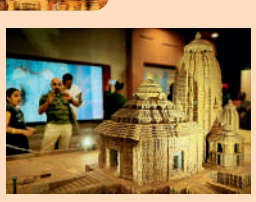

पर्यटन स्थलों के पास होगी इंटरप्रिटेशन सेंटर्स की स्थापना

पर्यटन स्थलों को मिलेंगी **4,000** ई-बसें

पर्यटन स्थलों पर **10 हजार** गाइड्स के लिए विशेष कोर्स

15 पुरातात्विक स्थल होंगे जीवंत तरीके से विकसित

बनाया जाएगा राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड

खेलो इंडिया प्रोग्राम को मिलेगी नई धार

कोच और सपोर्ट स्टाफ का सुनियोजित और क्रमबद्ध तरीके से विकास

स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने और प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग।

यूनियन बजट 2026-27 में सरकार ने बढ़ाया रक्षा खर्च

रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ का इजाफा

वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए ऐलान किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में युद्ध और रक्षा रणनीति की अहमियत और प्राथमिकता और बढ़ी है। जिसका असर हमें बजट में देखने को मिला। इस बजट में सरकार ने रक्षा खर्च बढ़ा दिया है। सरकार ने यूनियन बजट 2026-27 में रक्षा खर्च बढ़ा दिया है, इस सेक्टर के लिए 7,84,678 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

विमान और एयरो इंजन में इतना किया जाएगा खर्च

कैपिटल खर्च की बात करें तो विमान और एयरो इंजन के लिए 63,733 करोड़ रुपये और नौसेना बेड़े के लिए 25,023 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2025-26 के लिए रक्षा बजट 6,81,210 करोड़ रुपये तय किया गया था, जिसमें कैपिटल खर्च 1,80,000 करोड़ रुपये था, जिसे बाद में संशोधित अनुमानों के चरण में 1,86,454 करोड़ रुपये कर दिया गया था। भाषण में सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र की यूनिट्स द्वारा रख-रखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए इस्तेमाल होने वाले विमान पार्ट्स के निर्माण के लिए आयातित कच्चे माल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ करने की भी घोषणा की।

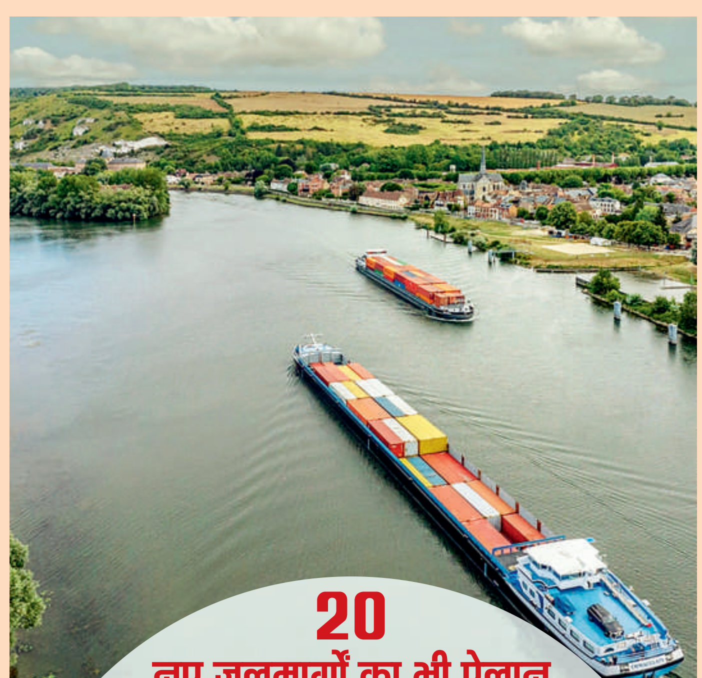

20 नए जलमार्गों का भी ऐलान

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में देश में 20 नए जलमार्गों का ऐलान किया है। इसमें दानकुनी से सूरत तक नया फ्रेट कॉरिडोर भी शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि कार्गो के पर्यावरण-अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए समर्पित माल गलियारे स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्गों को चालू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से होगी। इसके अतिरिक्त, अंतर्देशीय जलमार्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाराणसी और पटना में एक जहाज मरम्मत इकोसिस्टम भी स्थापित किया जाएगा। रेल और सड़क से जलमार्गों की ओर माल ढुलाई को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम शुरू करेगी। इसका लक्ष्य 2047 तक इंलैंड वॉटरवेज और कोस्टल शिपिंग की हिस्सेदारी को मौजूदा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करना है।

परमाणु परियोजनाओं के लिए कई चीजें ड्यूटी-फ्री

सितंबर 2035 तक कस्टम्स में रजिस्टर्ड सभी परमाणु परियोजनाओं के लिए न्यूक्लियर जनरेशन इक्विपमेंट, एब्जॉर्बर रॉड्स और प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स को ड्यूटी-फ्री कर दिया गया है। एविएशन सेक्टर में रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आयात किए जाने वाले एयरक्राफ्ट पार्ट्स, इंजन और एमआरओ इनपुट्स पर भी कस्टम ड्यूटी हटाई गई है।

न्यूक्लियर और एविएशन सेक्टर को बड़ी राहत

बजट में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि की स्पष्टता दी गई है। सितंबर 2035 तक कस्टम्स में रजिस्टर्ड सभी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए न्यूक्लियर जनरेशन इक्विपमेंट, एब्जॉर्बर रॉड्स और प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी शून्य कर दी गई है। एविएशन सेक्टर में रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आयात किए जाने वाले एयरक्राफ्ट पार्ट्स, इंजन और **MRO** से जुड़े कच्चे माल पर भी ड्यूटी हटा दी गई है।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा बुद्ध सर्किट

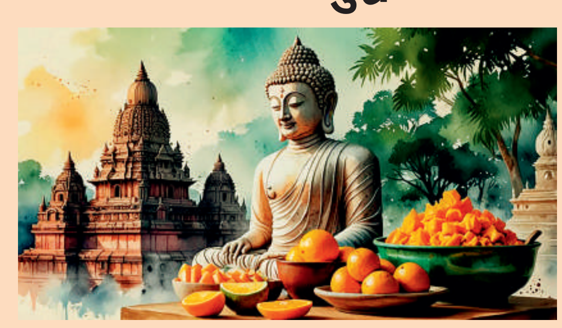

वित्तमंत्री सीतारमण ने इस बार बजट में पर्यटन पर काफी फोकस रखा गया है और मोदी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने पूर्वोत्तर के छह राज्यों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक कॉरिडोर का ऐलान किया है। कॉरिडोर का नाम रखा गया है- बौद्ध सर्किट जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर योजना के तहत मंदिरों और मठों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएंगे। सीतारमण ने कहा, 'सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए योजना शुरू करेगी ताकि मंदिरों और मठों का संरक्षण किया जा सके। सरकार पूर्वोत्तर के पांच राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों का विकास करेगी।

टूरिज्म के क्षेत्र में सरकार की बड़ी पहल

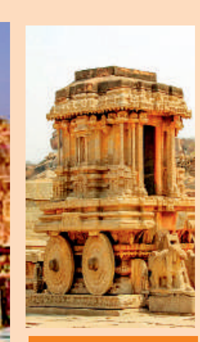

15 पुरातत्त्व स्थल, 20 टूरिस्ट साइट्स और इको-टूरिज्म को बढ़ावा

नार्थ ईस्ट के मंदिरों-मठों को बचाने पर खास जोर

इंटरप्रिटेशन सेंटर्स में इतिहास की जानकारी

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से लाई गई इस योजना के तहत पर्यटन स्थलों के पास इंटरप्रिटेशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी जहां उन जगहों के इतिहास और महत्व संबंधी जानकारियां दी जाएंगी।

पर्यटन में यह भी खास

वित्त मंत्री ने कहा, '20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों को ट्रेन करने के लिए एक पायलट योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 12 हफ्ते का स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग कोर्स कराया जाएगा।' मोदी सरकार के टूरिज्म प्लान में भारत के पुरातात्विक स्थलों को बढ़ावा देना भी शामिल है। निर्मला सीतारमण के मुताबिक, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत तरीके से विकसित किया जाएगा।

अब मिशन मोड में बढ़ाया जाएगा खेलो इंडिया

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की तैयारी! स्टेडियम से साइंस लैब पर होगा सुधार

कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर

बजट में खेलों के लिए सरकार ने बड़े ऐलान किए। खेलो इंडिया को अब मिशन मोड में बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य अगले दशक में भारत के खेल ढांचे और खिलाड़ियों के विकास को नई रफ्तार देना है। इस पहल के तहत स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर से लेकर स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी तक हर स्तर पर सुधार किया जाएगा, ताकि जमीनी स्तर से ही टैलेंट को पोषित किया जा सके। भारत की 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी को ध्यान में रखते हुए, यह मिशन ग्रासरूट से एलीट लेवल तक खिलाड़ियों और कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगा। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि यह मिशन इंटर-लिंकिंग तरीकों से एक इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को आसान बनाएगा। खेलो इंडिया प्रोग्राम 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य टैलेंट (प्रतिभा) पहचानने के लिए अलग-अलग आयु वर्ग में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं करवाना था। 'स्पोर्ट्स सेक्टर रोजगार, स्किलिंग और नौकरी से मिलते मौके लोकसभा में अपने बजट भाषण के दौरान निर्मण सीतारमण ने कहा, 'स्पोर्ट्स सेक्टर रोजगार, स्किलिंग और नौकरी के कई मौके देता है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के जरिये खेल प्रतिभा का सुनियोजित और क्रमबद्ध तरीके से बढ़ावा देने की जो शुरुआत हुई है, उसे आगे बढ़ाते हुए, मैं अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को बदलने के लिए एक खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखती हूं।'

मिलेंगी ये सुविधाएं

- ट्रेनिंग सेंटरों द्वारा समर्थित फाउंडेशनल, इंटरमीडिएट और एलीट स्तर वाले इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट पाथवे
- कोच और सपोर्ट स्टाफ का सुनियोजित और क्रमबद्ध तरीके से विकास।
- स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन।
- स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने और प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग।
- ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट।

आम बजट पर विशेषज्ञों का नजरिया

नीतिगत और संतुलित आर्थिक व्यवस्था वाला बजट, भावी विकास को देगा गति

प्रो. एसके जैन
कुलगुरु, बरकतउल्ला विवि, भोपाल

केंद्रीय बजट-2026 देश के भावी विकास के लिए नीतिगत और संतुलित आर्थिक व्यवस्था का बजट माना जा सकता है। इसकी एक खास विशेषता इसकी स्थिर नीतिगत और आर्थिक व्यवस्था है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिल सकता है। इससे कम लागत और अधिक भरोसेमंद वातावरण में विस्तार करने की क्षमता बढ़ेगी। पिछले वित्त वर्ष में शिक्षा मंत्रालय के लिए रुपए 1.28 लाख करोड़ से अधिक के आवंटन से यह प्रतीत होता है कि सरकार मानव पूंजी में निवेश कर रही है। ऐसे में विश्वविद्यालयों, डिजिटल एज्युकेशन और स्किल डेवलपमेंट में स्थिर निवेश भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। शिक्षा में यह निवेश एक तरह से आर्थिक नीति का हिस्सा कहा जा सकता है।

यह विकास और विश्वास का बजट, इसमें पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के संतुलन पर ध्यान दिया

ब्रजेश चौहान
पूर्व सदस्य, मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग

यह विकास और विश्वास का बजट है और विकसित भारत 2047 की नींव मजबूत करने वाला है। इसमें गरीबों, युवाओं, अन्नदाता किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। बजट का उद्देश्य सभी वर्गों के साथ न्याय करते हुए देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। बजट में गरीब, युवा, महिला और किसानों को राहत देने वाले कई सकारात्मक प्रावधान किए गए हैं। आयकरदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। टैक्सपेयरों को सजा के स्थान पर नाममात्र की पेनाल्टी का प्रावधान दर्शाता है कि केंद्र सरकार दण्ड व्यवस्था नहीं न्याय व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। यह बजट डर से मुक्त टैक्स व्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम है। आम करदाताओं और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए विदेश यात्रा और शिक्षा को किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने विदेश यात्रा पैकेज की बिक्री पर टीसीएस की दर को 5 से 20 प्रतिशत के स्लैब से घटाकर सीधे 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। यही राहत लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत शिक्षा और चिकित्सा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर भी दी गई है।

केंद्रीय बजट में इस बार सरकार ने अपने खर्च की पूरी तस्वीर सामने रख दी है। इस बजट में साफ दिख रहा है कि फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और आम आदमी से जुड़े सेक्टरों पर है। बजट के आंकड़ों के मुताबिक, सरकार का सबसे ज्यादा खर्च परिवहन और रक्षा जैसे बड़े क्षेत्रों में जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि सड़क, रेल, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में और रफ्तार पकड़ सकते हैं। सरकार का मानना है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित देश ही तेज आर्थिक विकास ही बुनियाद बनते हैं।

छोटे शहर अब 'बड़े' होंगे, खुला खजाना, थोक में मिलेगा रोजगार भी

सरकार का फोकस शहरी आर्थिक क्षेत्रों को विकसित करना

बजट में इस क्षेत्र के लिए 12.2 करोड़ रुपए रखे गए हैं

इस बार बजट में सरकार ने जन निवेश पर जोर देते हुए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को 11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया है। सरकार का मकसद है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। बजट में विशेष ध्यान टियर-2 और टियर-3 शहरों पर रखा गया है, जो धीरे-धीरे विकास के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। इस बार एक बड़ा कदम इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क डेवलपमेंट फंड की स्थापना का प्रस्ताव है। इसका मकसद बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को आंशिक गारंटी देना है ताकि बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निर्माण के दौरान जोखिम कम हो और निजी निवेश बढ़े। साथ ही, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (सीपीएसई) की रियल एस्टेट संपत्तियों को रीटस के जरिए तेजी से मोनेटाइज करने की योजना है। इससे खाली पड़ी संपत्तियों का सही उपयोग होगा, भूमि की दक्षता बढ़ेगी और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी उपलब्ध होगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बढ़ाया गया

त्रेहान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सारांश त्रेहान का कहना है, 'केंद्रीय बजट 2026 भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को काफी बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए पूंजीगत खर्च 12.20 लाख करोड़ रखा गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा है और यह शहरी और उभरते बाजारों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएगा। रीट्स आधारित एसेट रीसाइक्लिंग को तेजी से लागू करने और टियर-2 एवं टियर-3 शहरों के लिए समर्थन देने पर जोर, निवेशकों का भरोसा और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत मदद को दर्शाता है। बेहतर अफोर्डेबिलिटी और फाइनेंसिंग विकल्पों के साथ यह बजट मांग को बढ़ा सकता है और रियल एस्टेट सेक्टर को रोजगार, शहरीकरण और समावेशी विकास में स्थायी योगदान देने में मदद करेगा।'

विश्वास पैदा होगा

वीवीआईपी ग्रुप के एमडी विभोर त्यागी का कहना है, बजट से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विश्वास पैदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क डेवलपमेंट फंड और सीपीएसई संपत्ति मोनेटाइजेशन से विकास और पारदर्शिता बढ़ेगी।

बजट में खास

अर्थव्यवस्था और उद्योग

01 ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 'रेयर अर्थ कॉरिडोर' बनाए जाएंगे।

02 कंटेनर निर्माण के लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू होगी।

03 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को तकनीक अपग्रेड के जरिए पुनर्जीवित किया जाएगा।

04 भविष्य के एमएसएमई चैंपियंस के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड' बनेगा।

05 सरकारी कंपनियों द्वारा एमएसएमई से खरीद के लिए ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म अनिवार्य होगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर के 7 रणनीतिक क्षेत्रों को बढ़ावा

आर्थिक विकास को गति देने के लिए बजट में राजमार्गों, बंदरगाहों, रेलवे और बिजली परियोजनाओं सहित इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त प्रोत्साहन देने, 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और तेजी से लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सृजित करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक निवेश पर मजबूत जोर देते हुए राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखी है, और आगे कहा कि भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ना चाहिए, अधिक निर्यात करना चाहिए और विदेशी निवेश को भी आकर्षित करना चाहिए।

शहरी आर्थिक क्षेत्रों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव

पांच वर्षों में 5000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव

शहरवासियों को बुनियादी ढांचे से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी

केंद्रीय वित्त मंत्री ने शहरी विकास को मजबूत करने के लिए एक बड़े कदम की घोषणा की। इसके तहत शहरी आर्थिक क्षेत्रों (सीईआर) के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और प्रत्येक क्षेत्र के लिए पांच वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। इसका मकसद संबंधित योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना है। सीतारमण ने लोकसभा में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए शहरों को भारत के विकास, नवोन्मेष और अवसरों का इंजन बताया और कहा कि यह नई पहल दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के साथ-साथ मंदिर नगरों पर केंद्रित होगी, जिन्हें आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर शहर आर्थिक क्षेत्र का मानचित्रण करके शहरों की आर्थिक शक्ति को और अधिक बढ़ाना है। सीतारमण ने कहा, 'सुधार-सह-परिणाम आधारित वित्तपोषण व्यवस्था के साथ चुनौतीपूर्ण तरीके से उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रत्येक सीईआर के लिए पांच वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया गया है।' उन्होंने कहा कि पिछले दशक में, उनकी सरकार ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के व्यापक सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) जैसे नए वित्तपोषण साधन और एनआईआईएफ (राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष) और एनएबीएफआईडी (राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा और विकास वित्त पोषण बैंक) जैसी संस्थाएं शामिल हैं।

पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'पर्यावरण के अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मैं नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव रखती हूं, जो पूर्व में डांकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ेगा। अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, शुरूआत राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से ओडिशा में होगी, जो तालचर और अंगुल जैसे खनिज-समृद्ध क्षेत्रों और कलिंगानगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और डामरा के बंदरगाहों से जोड़ेगा. साथ ही, वाराणसी और पटना में इनलैंड वाटरवे के लिए जहाज मरम्मत का एक इकोसिस्टम भी स्थापित किया जाएगा.।

कनेक्टिविटी बेहतर होगी

गंगा रीयलिटी के जेएमडी विकास गर्ग कहते हैं, 'सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि से प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता और कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे निजी निवेश बढ़ेगा। रीट्स और इनविट के जरिए पूंजी जुटाने से संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा।'

रिटेल इकोनॉमी के लिए बड़े अवसर लाएगा

भुटानी के सीईओ आशीष भुटानी का कहना है, 'यह बजट रिटेल इकोनॉमी के लिए बड़े अवसर लाएगा। टैक्स में आसानी, एमएसएमई का समर्थन और लॉजिस्टिक्स व कनेक्टिविटी में निवेश से खरीदारों की क्षमता बढ़ेगी। इसका असर टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी महसूस होगा।'

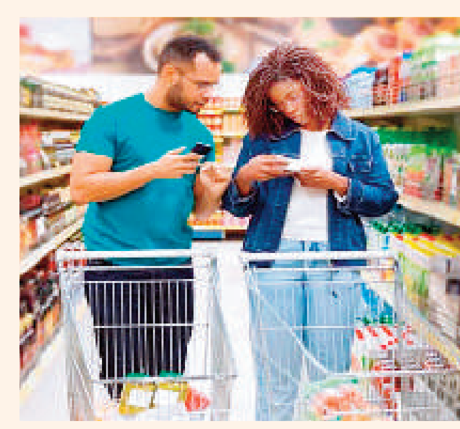

परिवहन पर सबसे ज्यादा खर्च

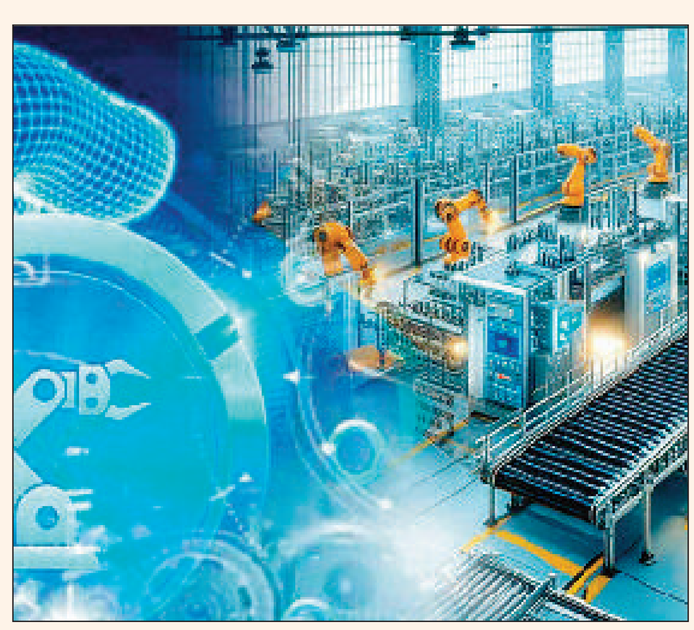

खर्च के आंकड़ों पर नजर डालें तो परिवहन सेक्टर सबसे ऊपर है, जहां करीब 5.98 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके ठीक बाद रक्षा बजट है, जिस पर 5.94 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे साफ है कि सरकार सीमाओं की सुरक्षा और सैन्य क्षमता को मजबूत करने पर कोई समझौता नहीं करना चाहती। वहीं, ग्रामीण विकास के लिए 2.73 लाख करोड़ रुपये और गृह मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह खर्च ग्रामीण इलाकों में सड़क, आवास, रोजगार और सुरक्षा से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

आम बजट पर विशेषज्ञ का नजरिया

प्रो.आरएस मीना
वाणिज्य संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

चुनौती जमीनी स्तर पर समय पर क्रियान्वयन

केंद्रीय बजट 2026 ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी दीर्घकालिक क्षमता को लेकर आश्वस्त है, फिर भी अल्पकालिक आर्थिक और सामाजिक वास्तविकताओं से बाधित है। परिवहन, रसद, ऊर्जा या शहरी विकास सहित अधिकतर क्षेत्र में अवसंरचना को एक बार फिर प्रमुखता दी गई है। यह तर्कसंगत है। सार्वजनिक निवेश न केवल अल्पकालिक रूप से रोजगार सृजित करता है, बल्कि दीर्घकालिक रूप से उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में भी सुधार करता है। हालांकि, असली परीक्षा क्रियान्वयन में होगी। भारत के पास महत्वाकांक्षी योजनाओं की कोई कमी नहीं है। चुनौती हमेशा से जमीनी स्तर पर समय पर क्रियान्वयन और गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त करने की रही है।

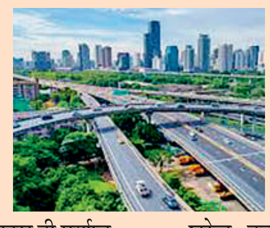

बजट इस बात की जागरूकता का संकेत देता है कि केवल विकास ही पर्याप्त नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में खर्च को बनाए रखने का स्पष्ट प्रयास किया गया है, विशेष रूप से ग्रामीण आजीविका, आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में। मध्यम वर्ग, जिसे अक्सर उपभोग और कराधान की रीढ़ कहा जाता है, शायद खुद को पूरी तरह से पुरस्कृत महसूस नहीं करे, लेकिन नवाचार और हरित परिवर्तन की दिशा में प्रयास बजट में दिख रहा है।

घरेलू उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन भारत की वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की आकांक्षा के अनुरूप हैं। हालांकि, इन पहलों के साथ-साथ कौशल विकास, व्यापार करने में सुगमता और नियामक स्पष्टता में गहन सुधार भी आवश्यक हैं। इनके बिना, केवल प्रोत्साहनों से कंपनियों के एक छोटे से वर्ग को ही लाभ मिलने का जोखिम है। केंद्रीय बजट 2026 भारत की आर्थिक दिशा में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाता है, लेकिन शायद यही इसका उद्देश्य है। यह एक विघटनकारी मार्ग के बजाय एक स्थिर, सुनियोजित मार्ग को सुदृढ़ करता है। कुछ लोगों को यह निराशाजनक लग सकता है। इस बजट की सफलता इसकी घोषणाओं पर कम और इसके कार्यान्वयन पर अधिक निर्भर करेगी।

बजट साधारण लेकिन उठाया गया सकारात्मक कदम

विकास के नए रास्ते खुलेंगे और दीर्घकालिक समर्थन मिलेगा, टीसीएस की दर थोड़ी कम हुई

वाणिज्य प्रतिनिधि ▶▶ भोपाल

केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग और व्यापारियों को दरकिनार किया गया है। व्यापारी और कारोबारी इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद लगाए थे लेकिन निराशा हाथ लगी। कॉरपोरेट घरानों को बढ़ावा दिया गया है, इसमें छोटे व्यापारियों को ध्यान नहीं दिया गया। बजट में एक अच्छा फैसला लिया गया है कि पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की बात कही गई है, इससे रोजगार का अवसर बढ़ेगा।

बजट अच्छा रहा, वैसे व्यापारियों को कोई पूछने वाला नहीं है फिर भी उनके लिए भी बेहतर है। इस बजट से महंगाई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। डिजिटल व ऑनलाइन मार्केट व्यापारियों की कमर तोड़ रही है। कारोबारियों ने कहाकि आम बजट में व्यापारियों और उद्यमियों को कोई खास लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। केवल महिलाओं को उद्यमी बनाने पर जोर दिया गया है। शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती की गई है। सीएनजी और बायोगैस को सस्ती की गई है। इससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। व्यवसायी आरके बामोरिया और अनुपम अग्रवाल ने कहाकि सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछली बार की ही तरह इस बार भी सालाना कमाई 4 लाख रुपए तक ही है। वहीं 4 से 8 लाख रुपए तक की कमाई पर सिर्फ 5 फीसदी टैक्स लगेगा। कारोबारियों ने कहाकि एमएसएमई सेक्टर पहले से ही कई मुश्किलों से गुजर रहा है। महंगाई, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा छोटे उद्योगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।

उद्योगपति योगेश गोयल ने कहा कि यह बजट आम उद्यमियों के लिए निराशा जनक है। एमएसएमई के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की गई। सरकार बार-बार एमएसएमई को देश की रीढ़ बताती है, लेकिन बजट में इसका असर नजर नहीं आता। भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष तेजकुलपाल सिंह पाली कहाकि छोटे उद्योगों के लिए इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। छोटे उद्यमी लगातार दबाव में हैं, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें सहारा देने के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया। कारोबारी ईश्वरदास संगतानी ने आशंका जताई कि अगर इसी तरह सिर्फ बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती रही, तो आने वाले समय में देश में केवल बड़ी-बड़ी कंपनियां ही रह जाएंगी। एमएसएमई सिर्फ एक ट्रेंड बनकर सीमित हो जाएंगे, जिसका सीधा असर रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

क्रेडाई ने किया सरकार द्वारा अवसंरचना पर निरंतर खर्च को प्रोत्साहित करने का स्वागत : विपिन

क्रेडाई ने सरकार द्वारा अवसंरचना पर निरंतर खर्च को प्रोत्साहित करने का स्वागत किया है। जो रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक बड़ा सकारात्मक कदम है। राजमार्गों, मेट्रो, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, रेलवे और शहरी अवसंरचना में निवेश से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, विकास के नए रास्ते खुलेंगे और दीर्घकालिक शहरी विकास को समर्थन मिलेगा। यह बात क्रेडाई के पूर्व अध्यक्ष विपिन गोयल ने कही। गोयल ने कहाकि क्रेडाई ने व्यापार करने में आसानी पर दिए गए जोर की भी सराहना करता है। त्वरित अनुमोदन, सरलीकृत प्रक्रियाएं और अधिक डिजिटलीकरण से परियोजना की समयसीमा और लागत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है, जिससे अंततः डेवलपर्स और घर खरीदारों दोनों को लाभ होगा। उन्होंने कहाकि हालांकि, किफायती आवास के लिए बजट में कोई ठोस प्रस्ताव न होने से क्रेडाई बेहद निराश है। क्रेडाई का मानना है कि किफायती आवास कोई कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि यह आर्थिक बुनियादी ढांचा है। यह रोजगार, उपभोग और सामाजिक स्थिरता का एक प्रमुख चालक है। क्रेडाई सरकार से आग्रह करता है कि समावेशी और टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए किफायती आवास पर तत्काल नीतिगत ध्यान दिया जाए।

विपिन गोयल, पूर्व अध्यक्ष, क्रेडाई

मध्यवर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने का कोई उपाय नहीं

केंद्र सरकार के बजट में मध्यम वर्ग के लिए कोई विशेष योजना की घोषणा नहीं की गई। सरकार ने मध्यवर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने के कोई उपाय नहीं किया। सरकार इस बजट में करदाता व्यापारियों के लिए किसी सोशल सिक्योरिटी योजना की घोषणा करेगी ऐसी उम्मीद थीं यह भी अपेक्षा पूरी नहीं हुई साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव न होने से भी कोई अतिरिक्त राहत नहीं मिली।

नवनीत अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल

व्यापारियों को सीमित राहत, प्रमुख अपेक्षाएं अधूरी रह गईं

बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए ऋण सुविधा बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश की घोषणा सकारात्मक कदम है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को कुछ गति मिल सकती है। लॉजिस्टिक्स, शहरी बुनियादी ढांचे और ट्रांसपोर्ट से जुड़े प्रावधानों से भोपाल जैसे शहरों में व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। हालांकि व्यापारियों की प्रमुख मांग जीएसटी प्रक्रिया के वास्तविक सरलीकरण, अनावश्यक नोटिसों और दंडात्मक कार्रवाई से राहत को लेकर थी, लेकिन बजट में इस दिशा में कोई ठोस घोषणा नहीं की गई।

धर्मेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष, कैट भोपाल

आम से खास तक के लिए कुछ न कुछ तोहफा मिला

बहुत ही सधा हुआ बजट है जिसमें आम से लेकर खास तक के लिए कुछ न कुछ तोहफा मिला। बुजुर्गों के कैंसर और मधुमेह की दवाई सस्ती होंगी। युवाओं को एमएसएमई के माध्यम से न्याय उद्योग खोलने में सहायता, बायो सीएनजी पर टैक्स में राहत का फायदा किसानों को होगा। घरेलू उद्योग के लिए , ग्रामीण महिलाओं के लिए शी मार्ट योजना कुल मिलाकर 2026/27 के बजट में सब के लिए कुछ न कुछ मिला।

अजय सिंह

अध्यक्ष,मध्यप्रदेश पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन

औद्योगिक विकास को गति मिलेगी

भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का बड़ा योगदान है, जो देश के जीडीपी में लगभग 30 फीसदी हैं। यह देश के कुल उत्पादन का लगभग एक तिहाई है। ये न केवल विनिर्माण (45 फीसदी उत्पादन) और निर्यात (40 फीसदी) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि 110 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार भी देता है। सरकार भी आत्मनिर्भर भारत और 10 हजार करोड़ के एमएसएमई ग्रोथ फंड जैसी पहल के साथ इस क्षेत्र को ग्लोबल चैंपियन बनाने पर बल दिया गया है।

सुनील जैन 501

अध्यक्ष, मध्यप्रदेश एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसो.

ज्वेलरी इंडस्ट्री को बजट में कोई प्रत्यक्ष राहत नहीं: संजीव गर्ग

केंद्रीय बजट 2026 में ज्वेलरी इंडस्ट्री सेक्टर को कोई विशेष या प्रत्यक्ष राहत पैकेज घोषित नहीं किया गया, जिससे इस क्षेत्र के व्यापारी, कारीगर एवं एमएसएमई इकाइयों में निराशा है। यह बात होलसेल सराफा अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश प्रांतीय सराफा एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संजीव कुमार गर्ग गांधी ने कहाकि यह उद्योग रोजगार सृजन, निर्यात और कर-राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है, फिर भी अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि बजट में सरकार का फोकस आर्थिक विकास, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्ट-अप, कृषि, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और आत्मनिर्भर भारत पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह दिशा दीर्घकालीन विकास के लिए सकारात्मक है। आयुर्वेद, योग, मेडिटेशन और वेलनेस सेक्टर को प्रोत्साहित करना भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति को बढ़ाएगा।

करदाताओं की अपेक्षा के अनुसार आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया : मृदुल

केंद्रीय बजट में करदाताओं की अपेक्षा के अनुसार आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है केवल आयकर रिटर्न रिवाइज करने की सीमा तीन माह बढ़ा दी गई है परंतु उसमें भी फीस का प्रावधान किया गया है। यह बात टैक्स लॉ बार एसोसिएशन भोपाल के अध्यक्ष मृदुल आर्य ने कही। उन्होंने बताया कि टीसीएस की दरों में थोड़ी कमी की गई है उससे जरूर आम जनता को कुछ राहत मिलेगी, बिना ऑडिट वाले करदाताओं को 31 जुलाई तक रिटर्न भरना थी उसमें दो श्रेणियां बना दी गई है फार्म एक और दो भरने वाले 31 जुलाई तक एवं अन्य 31 अगस्त तक रिटर्न भर सकते हैं। अन्य सुविधाएं जो दी गई है जैसे की अपील में स्टे या विदेश की संपत्ति की घोषणा सब में फीस या पेनल्टी का प्रोविजन रखा गया है, ऐसा लगता है कि सरकार कर के स्थान पर फीस से अपनी आय बढ़ाना चाहती है जबकि उसे करदाताओं को सुविधा देते हुए समय सीमा में वृद्धि करनी चाहिए थी।

केंद्रीय बजट समग्र स्वास्थ्य रणनीति के भीतर

बढ़ते महत्व को पुष्ट करता है। कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा प्रशिक्षण और संबद्ध सेवाओं पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ, आयुष औषधालयों और औषधि-परीक्षण प्रयोगशालाओं को उच्च मानकों तक अपग्रेड करने से आयुर्वेद और अन्य आयुष दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता में महत्वपूर्ण सुधार होगा जैसे-जैसे भारतीय तेजी से प्रमाणिक और विज्ञान-आधारित पारंपरिक देखभाल की ओर बढ़ रहे हैं, ये उपाय उपभोक्ता के विश्वास को मजबूत करेंगे और निवारक तथा कल्याण-आधारित स्वास्थ्य सेवा को व्यापक रूप से अपनाने में मदद करेंगे।

अजय शर्मा, निदेशक, श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा. लि

उद्योग और व्यापार के प्रति सकारात्मक बजट : जबलपुर चेंबर

जबलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बजट को उद्योग एवं व्यापार के प्रति सकारात्मक माना गया। जिसमें सरकार द्वारा नियमों के सरलीकरण द्वारा राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। इस बार जबलपुर चेंबर द्वारा बजट प्रतिक्रिया पर हलुवे का प्रावधान किया गया ताकि सरकार द्वारा कि जाने वाली हलुवे की रसम की अनुभूति हो सके। जबलपुर चेम्बर के अध्यक्ष प्रेम दुबे का कहना है कि लघु उद्योगों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान हमारे उद्योगों की मदद करेगा। चेंबर चेयरमैन कमल ग्रोवर द्वारा बजट को संतुलित बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में किए गए प्रावधानों से होटल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कर विशेषज्ञ सीए अनिल अग्रवाल द्वारा बताया गया कि इनकम टैक्स नियमों के सरलीकरण के क्षेत्र में काफी अच्छे प्रावधान किए गए और खासकर 12 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्चे का प्रावधान अर्थव्यवस्था को गति देगा। चेंबर सचिव पंकज महेश्वरी ने कहा कि एमएसएमई को ऋण सुविधा बढ़ाए जाने का कदम छोटे उद्योगों को राहत प्रदान करेगा। चेंबर कोषाध्यक्ष अजय बख्तावर ने बताया कि वर्तमान में सोने-चांदी के भाव अधिकतम उंचाई पर होने से ज्वेलरी ट्रेड को सोने चांदी पर आयात शुल्क न बढ़ने से सराफा व्यवसाय को राहत मिली है।

भोपाल चेंबर चुनाव प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटी में बंद

2236 में से 2000 मेंबरों ने किया मतदान आज होगी मतगणना, होंगे विजेता घोषित

वाणिज्य प्रतिनिधि ▶▶ भोपाल

व्यापारियों की शीर्ष संस्था भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) के त्रैवार्षिक चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 2236 में से 2000 से अधिक व्यापारियों ने वोट डाले हैं। इससे पहले चुनाव को लेकर व्यापारियों में खासा उत्साह रहा। वे लाइन में लगकर वोट डालने पहुंचे। अध्यक्ष पद के लिए गोविंद गोयल और तेजकुलपाल सिंह पाली के बीच सीधा मुकाबला है।

करीब 170 सदस्यों की टीम मतदान प्रक्रिया संपन्न कराया। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। पर्यवेक्षक डॉ. पीसी कोठारी, सीएम वैभव जैन समेत अन्य निर्वाचन अधिकारियों ने पॉलीटेक्निक कॉलेज चौराहा स्थित मानस भवन में वोटिंग कराई। यहां कुल 20 बूथ बनाए गए थे। 2 विशेष बूथ हैं, जो दिव्यांजन और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए हैं। ताकि, उन्हें वोट डालने में कोई दिक्कत न हो। वे इंट्री पाइंट पर ही वोट डाल सकेंगे। मेडिकल टीमें भी तैनात की गई हैं। कुल 2236 मतदाता हैं। इसमें से करीब 90 मतदाता पहले वोट डाल चुके थे। ये वो मतदाता है, जो रविवार को कहीं बाहर जाने वाले थे और मतदान वाले दिन यहां मौजूद नहीं है।

मत पेटियां श्यामला हिल्स थाने में कराई गईं जमा

चेंबर चुनाव में मतदान करने वाले चेंबर के मेंबरों को कोई भी एक परिचय पत्र लाना अनिवार्य रहा। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि फोटोयुक्त परिचय पत्र शामिल रहे । वोटिंग के बाद मत पेटियां श्यामला हिल्स थाने में जमा कराई गई।

सराफा व्यापारियों का प्रतिनिधमंडल मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिला

व्यापारियों ने आने वाली विभिन्न व्यावहारिक एवं कानूनी समस्याओं से कराया अवगत

वाणिज्य प्रतिनिधि ▶▶ भोपाल

होलसेल सराफा व्यापार एवं मध्य प्रदेश प्रांतीय सराफा एसोसिएशन के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भेंट की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सराफा व्यापारियों को भविष्य में आने वाली विभिन्न व्यावहारिक एवं कानूनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। प्रमुख रूप से धारा 411, व्यापारियों की आत्म-सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस, गिरवी से संबंधित नियम, तथा सराफा व्यापार से जुड़ी अन्य जमीनी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समस्त विषयों को गंभीरता से सुना एवं सराफा व्यापारियों की व्यावहारिक कठिनाइयों को समझते हुए आश्वासन दिया कि सराफा व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन सभी विषयों पर शीघ्र ही सकारात्मक एवं व्यावहारिक निर्णय लेकर उन्हें क्रियान्वित कराया जाएगा, जिससे व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इस प्रतिनिधिमंडल में संजीव कुमार गर्ग

गांधी होलसेल सराफा अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश प्रांतीय सराफा एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष, अखिलेश मित्तल (सचिव, भोपाल सराफा एसोसिएशन), विजय वर्मा , शविवेक अग्रवाल, गौरव अग्रवाल , आनंद सोनी आदि उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि राज्य सरकार द्वारा सराफा व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए शीघ्र ही ठोस कदम उठाए जाएंगे।

बिजनेस न्यूज

फिजिक्सवाला ने की मॉक प्री-बोर्ड्स की घोषणा

भोपाल। शिक्षा कंपनी फिजिक्सवाला(पीडब्ल्यू) ने कक्षा 10 के सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 में भाग लेने वाले छात्रों की मदद के लिए एक योजना शुरू की है। इसमें देश के सभी छात्र मुफ्त डाउट हल करने में विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। यह योजना सिर्फ पीडब्ल्यू के छात्रों के लिए नहीं, बल्कि देश के किसी भी कक्षा 10 के छात्र के लिए खुली है। इसका उद्देश्य परीक्षा के समय पढ़ाई का तनाव कम करना है। पीडब्ल्यू देशभर में विज्ञान और गणित के लिए ऑफलाइन प्रीबोर्ड भी करवाएगा ताकि छात्रों की तैयारी मजबूत हो सके। ये परीक्षा पीडब्ल्यू के विध्यापीठ, पाठशाला और ट्यूशन सेंटर्स में होंगी। इससे छात्रों को असल बोर्ड परीक्षा जैसा अनुभव मिलेगा और वे समय सीमा में परीक्षा की तैयारी बेहतर कर सकेंगे। छात्र अपने नज़दीकी सेंटर में 1 फरवरी 2026 को होने वाली विज्ञान परीक्षा और 8 फरवरी 2026 को होने वाली गणित परीक्षा के लिए पीडब्ल्यू ऐप के जरिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। यह योजना फिजिक्सवाला के कुल 192 टेक्नोलॉजी वाले विध्यापीठ और पाठशाला सेंटर के जरिए शुरू की जा रही है, जो 30 सितंबर 2025 तक भारत के 132 शहरों में उपलब्ध रहेगी।

विप्रो जीई ने सिग्ना प्राइम एलीट का अनावरण किया

भोपाल। विप्रो जीई हेल्थकेयर एक अग्रणी वैश्विक चिकित्सा प्रौद्योगिकी डायग्नोस्टिक्स और डिजिटल समाधान प्रवर्तक ने आज हैदराबाद में इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन 2026 के वार्षिक सम्मेलन में अपने नवीनतम एमआर इमेजिंग सिस्टम सिग्ना प्राइम एलीट के लांच की घोषणा की विप्रो जीई हेल्थकेयर की एमडीएम सुविधा कंपनी की पीएलआई फैक्ट्री में निर्मित, सिग्ना प्राइम एलीट इसके अग्रणी मेड इन इंडिया पोर्टफोलियो में नवीनतम है। यह एमआर सिस्टम तेज, अधिक आरामदायक स्कैन और बेहतर डायग्नोस्टिक आत्मविश्वास प्रदान करने के लिए रोगी-केंद्रित डिजाइन के साथ उन्नत इमेजिंग इंटेलिजेंस को जोड़ता है।

मॉन्ट्रा इलेक्ट्रिक ने भारत का पहला 'पीएम ई-ड्राइव' सर्टिफाइड इलेक्ट्रिक ट्रक किया डिलीवर

भोपाल। मुरूगप्पा ग्रुप के हिस्से मॉन्ट्रा इलेक्ट्रिक ने भारत की क्लीन मोबिलिटी यात्रा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कंपनी पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली हैवी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माता बन गई है। इस उपलब्धि के साथ मॉन्ट्रा इलेक्ट्रिक ने भारत की सबसे बड़ी सीमेंट एवं रैडी-मिक्स कॉन्क्रीट कंपनी अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड को देश का पहला पीएम ई-ड्राइव-सर्टिफाईड इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक, राइनो 5538, ईवी 6 एक्स 4 ट्रेक्टर ट्रेलर डिलीवर किया है। यह उपलब्धि इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को बढ़ावा देने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अरुण मुरुगप्पन, चेयरमैन-मॉन्ट्रा इलेक्ट्रिक (टीआई क्लीन मोबिलिटी), जलज गुप्ता, एमडी-मॉन्ट्रा इलेक्ट्रिक, साथिया राज, चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की मौजूदगी में मनाया गया। अरूण मुरूगप्पन द्वारा पहला पीएम ई-ड्राइव-सर्टिफाईड राइनो 5538, ईवी-अल्ट्रा टेक को सौंपा गया। रु 10,900 करोड़ रुपए की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ई-ट्रकों के लिए रु 500 करोड़ निर्धारित किए गए हैं, राइनो 5538 ईवी की बात करें तो उपभोक्ता को प्रति वाहन पर रु 9.6 लाख तक का सीधा फायदा होगा।

एक्सिस बैंक ने की मप्र में 3.20 लाख ग्रामीण परिवारों की आर्थिक क्षमता में वृद्धि

भोपाल। एक्सिस बैंक फाउंडेशन अपने सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम के जरिए मध्य प्रदेश में 45 से अधिक जिलों के 3.20 लाख से ज्यादा परिवारों को सहयोग दे रहा है। यह कार्यक्रम आदिवासी, वन और कृषि क्षेत्रों में लागू है और वर्षा पर निर्भर खेती, जलवायु बदलाव से होने वाले जोखिम और सामाजिक विविधता जैसी चुनौतियों का स्थानीय स्तर पर समाधान करता है। इसमें छोटे किसान, महिलाएं, आदिवासी समुदाय, भूमिहीन परिवार, ग्रामीण युवा और दिव्यांगजन शामिल हैं। कार्यक्रम आजीविका, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सामाजिक अधिकारों और स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने पर केंद्रित है। बैंक की एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी और सीईओ ध्रुवी शाह के अनसार हम जमीनी स्तर पर ज्ञान और संसाधनों को जोड़ते हैं, स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं और लोगों को अपने गांव में सुरक्षित भविष्य बनाने में सक्षम बनाते हैं।

टाटा मोटर्स ने की 71,066 यूनिट्स की बिक्री

मुंबई। जनवरी 2026 के दौरान घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड की कुल बिक्री 71,066 यूनिट्स रही, जबकि जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 48,316 यूनिट्स था। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने लिए इस साल की शुरुआत बेहद ही शानदार रही। जिसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों के आंकड़े शामिल हैं। यह बिक्री जनवरी 2025 के 48,316 यूनिट्स के मुकाबले 47.1 प्रतिशत ज्यादा रही. हाल के दिनों में टाटा मोटर्स ने बाजार में सिएरा, हैरियर ईवी, सफारी-हैरियर पेट्रोल जैसे कई नए मॉडलों को पेश किया है. जिसने कंपनी की बिक्री को तगड़ा बूम दिया है। कंपनी ने घरेलू बाजार में जनवरी में कुल 70,222 गाड़ियों की बिक्री की है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 46.1 प्रतिशत की बढ़त दिखाता है। टाटा मोटर्स ने जब सिएरा की बुकिंग शुरू की थी उस वक्त महज एक दिन में ही इस एसयूवी के 70,000 यूनिट्स की बुकिंग दर्ज की गई थी।

सैमसंग का एआई टीवी के लिए प्लस कैंपेन लांच

गुरुग्राम। सैमसंग ने अपने 'मेड फॉर इंडिया' प्लस कैंपेन की घोषणा की है। यह खास पहल भारतीय उपभोक्ताओं के लिए टीवी खरीदने के अनुभव को और भी फायदेमंद बनाती है। इस कैंपेन के तहत बड़ी स्क्रीन, स्मार्ट विजन एआई तकनीक, फ्री टीवी चैनल्स, एक्सटेंडेड वारंटी और आसान फाइनेंस विकल्प एक ही पैकेज में मिलेंगे। यह भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार समाधान देने की सैमसंग की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। कंपनी के सीनियर डायरेक्टर विपलेश डांग ने कहाकि 'मेड फॉर इंडिया' प्लस कैंपेन भारतीय उपभोक्ताओं की पसंद और उनकी उम्मीदों की हमारी गहरी समझ का नतीजा है। आज के खरीदार सिर्फ शानदार पिक्चर क्वालिटी ही नहीं, बल्कि टिकाऊपन, स्मार्ट अनुभव और भरोसेमंद सर्विस भी चाहते हैं।

मित्सु केम का मुनाफा 217 फीसदी बढ़ा

मुंबई। मित्सु केम प्लास्ट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2026 के तीसरी तिमाही के लिए अपने अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। इस दरमियान कंपनी की कुल आय 8,608.85 लाख, एबिटडा 954.45 लाख रुपए , शुद्ध लाभ 470.63 लाख रुपए रहा। मित्सु केम प्लास्ट लिमिटेड के चेयरमैन जगदीश देढिया ने कहाकि हम अपने परिचालन आधार को मजबूत करने और कंपनी को विकास के अगले चरण के लिए तैयार करने पर निरंतर केंद्रित रहे।

इंडोविंड एनर्जी का एबिटडा 29.4 फीसदी बढ़ा

चेन्नई। इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2026 के तीसरी तिमाही के लिए अपने अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों के साथ-साथ मुख्य पूंजी, फंडिंग और निवेश से जुड़े अपडेट्स की घोषणा की है। कंपनी का कुल राजस्व 6.19 करोड़ , शुद्ध लाभ 0.35 करोड़, सालाना आधार पर 656फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई। कंपनी के प्रमोटर बाला वेंकट कुट्टी ने कहाकि हमारे संचालन की मूलभूत मजबूती लगातार बढ़ती लाभप्रदता और बेहतर मार्जिन में परिलक्षित हो रही है, जो हमारी दक्षता, संपत्ति प्रदर्शन और व्यवस्थित निष्पादन पर निरंतर ध्यान देने का परिणाम है।

वीआईटी भोपाल विवि में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सहयोग से हेल्थ हैकथॉन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय ने जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटीअमेरिका के सहयोग से हेल्थ हैक 2026 सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार नामक एक अंतरराष्ट्रीय हैकाथॉन की घोषणा की है। यह हैकाथॉन 10 से 12 फरवरी 2026 के दौरान आयोजित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यावहारिक और तकनीक-आधारित समाधानों को गति देना है।

यह घोषणा फरवरी 2025 में आयोजित हेल्थ हैक 2025 की उल्लेखनीय सफलता के बाद की गई है। पिछले संस्करण में शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, तकनीकी विशेषज्ञों और छात्रों ने मिलकर डेटा-आधारित एवं एआई-सक्षम नवाचारों के माध्यम से वास्तविक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत किए थे। चांसलर डॉ. जी. विश्वनाथन, वाइस प्रेसिडेंट शंकर विश्वनाथन, ट्रस्टी श्रीमती रमणी बालासुंदरम, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती कादंबरी एस. विश्वनाथन, के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य भाषण, तकनीकी सत्र, कार्यशालाएँ और प्रतिस्पर्धी समस्या-समाधान गतिविधियाँ शामिल रहीं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप कई संभावनाशील स्वास्थ्य-तकनीक प्रोटोटाइप विकसित हुए, जिससे अनुप्रयुक्त स्वास्थ्य अनुसंधान तथा उद्योग-शिक्षा सहयोग के क्षेत्र में वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय की सशक्त पहचान और अधिक मजबूत हुई। हेल्थ हैक 2026 इन्हीं शोध-आधारित सहयोगी प्रयासों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले संस्करण में आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की सक्रिय भागीदारी को देखते हुए, हेल्थ हैक 2026 में भारत एवं विदेशों से डेटा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, स्वास्थ्य पेशेवरों, नवाचारकर्ताओं और छात्रों की और व्यापक सहभागिता की अपेक्षा है। प हेल्थ हैक 2026 वास्तविक और विस्तार योग्य (स्केलेबल) प्रोटोटाइप के विकास पर केंद्रित रहेगा। प्रतिभागियों को मज़बूत डेटासेट, एपीआई तथा उद्योग एवं अनुसंधान साझेदारों जैसे इंटेलेहेल्थ और गुप्ता-क्लिन्स्की इंडिया इंस्टीट्यूट से विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

चिंतन

आम बजट में भविष्य की तस्वीर दिखाई

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया आम बजट 2026 एक ऐसा आर्थिक दस्तावेज़ है, जो भारत को आने वाले वर्षों के लिए तैयार करने की स्पष्ट मंशा दिखाता है। यह बजट विकासोन्मुखी,दीर्घकालिक सोच, रणनीतिक मजबूती और वैश्विक चुनौतियों के प्रति सजगता का परिचायक है, लेकिन साथ ही यह आम आदमी की तात्कालिक अपेक्षाओं पर खरा उतरने में कमजोर भी नजर आता है। कहा जा सकता है कि यह बजट "कल" की तैयारी करता है, पर "आज" की परेशानियों को पूरी तरह संबोधित नहीं करता। वित्त मंत्री ने 85 मिनट के लंबे भाषण में अर्थव्यवस्था, भू-राजनीति, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर विस्तार से बात की, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव न होना यह संकेत देता है कि सरकार फिलहाल वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक निवेश को प्राथमिकता दे रही है। टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने जैसे सुधार स्वागत योग्य हैं, मगर बढ़ती महंगाई के दौर में आम करदाता को इससे सीमित ही राहत मिलेगी। बजट का सबसे मजबूत पक्ष रक्षा क्षेत्र है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पेश हुए पहले बजट में सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। रक्षा बजट को 6.81 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये करना और आधुनिकीकरण व हथियार खरीद पर पूंजीगत खर्च में करीब 15% की बढ़ोतरी यह दिखाती है कि सरकार सेना को तकनीकी और रणनीतिक रूप से और सक्षम बनाना चाहती है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम है, हालांकि सामाजिक क्षेत्रों में इसी अनुपात में खर्च न बढ़ना सवाल भी खड़े करता है। अर्थव्यवस्था को बाहरी दबावों से बचाने के प्रयास बजट में साफ झलकते हैं। वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, ट्रंप-युग की टैरिफ मानसिकता और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में तनाव के बीच निर्यात प्रोत्साहन पर जोर दिया है। कपड़ा, चमड़ा, फिशरीज और दालों के निर्यात को बढ़ावा देने के कदम ग्रामीण और अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक साबित हो सकते हैं। इससे रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बनेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में नए अस्पतालों की घोषणा, दवाओं को सस्ता करने की पहल और 17 कैंसर मेडिसिन को ड्यूटी फ्री करना आमजन के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। आयुर्वेदिक एम्स जैसी घोषणाएं भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक ढांचे से जोड़ने की कोशिश मानी जा सकती हैं। शिक्षा और युवाओं पर केंद्रित योजनाएं बजट का एक और उल्लेखनीय पहलू हैं। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने की योजना डिजिटल इंडिया और क्रिएटर इकोनॉमी की दिशा में कदम है। साथ ही करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की घोषणा सामाजिक समावेशन और महिला शिक्षा को बढ़ावा दे सकती है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बजट चुनावी लोकलुभावन घोषणाओं से दूर नजर आता है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों के बावजूद किसी सीधे चुनावी लाभ वाली घोषणा का अभाव बताता है कि सरकार फिलहाल दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है। कुल मिलाकर आम बजट 2026 एक विज़न डॉक्यूमेंट है जो भविष्य की तस्वीर दिखाता है। यह बजट लोगों को संतुष्ट कर सकता है जो मजबूत रक्षा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देते हैं।

विश्लेषण
डॉ.जयंतीलाल भंडारी

विकसित भारत के लिए सुधारों का बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की तस्वीर में यह उभरकर दिखाई दे रहा है कि यह आम आदमी के लिए राहत और विकसित भारत के लिए साहसिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट है। यद्यपि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक अप्रैल से नया आयकर अधिनियम लागू किया जाना सुनिश्चित करके आयकर संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया है और आयकर भरना आसान किया गया है। इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और यह बजट देश को वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला और 2047 तक विकसित भारत बनाने की नींव रखने वाला बजट सिद्ध होगा।

यकीनन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की तस्वीर में यह उभरकर दिखाई दे रहा है कि यह बजट आम आदमी के लिए राहत और विकसित भारत के लिए साहसिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत सुधारों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए तीन कर्तव्यों पर आधारित किया है। इनमें उत्पादकता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना, लोगों की आशंकाओं को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण और सबका साथ, सबके विकास के मद्देनजर ढांचागत सुधार के साथ प्रगति करना शामिल है।

इस बजट में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपये सुनिश्चित किए गए हैं। यद्यपि बजट के तहत इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू किया जाना सुनिश्चित करके आयकर संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और आयकर भरना आसान किया गया है। बजट के नए प्रावधानों से बुनियादी ढांचा, छोटे शहर, एमएसएमई, शिक्षा, पर्यटन और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में नई पीढ़ी के लिए रोजगार के व्यापक मौके बढ़ेंगे। खास बात यह भी है कि आगामी वर्ष के बजट के तहत वित्त मंत्री राहत और विकास के बीच सूझबूझ पूर्ण संतुलन बनाते हुए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 फीसदी के स्तर पर सीमित रखने और सात फीसदी से अधिक विकास दर पाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं। गौरतलब है कि नए बजट के तहत वित्त मंत्री ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में धीमेपन के बीच अगली पीढ़ी के सुधार, नीतिगत स्थिरता व दीर्घकालीन विकास की रणनीति के साथ घरेलू मांग की मजबूती पर्यावरण नवाचार, उद्यमिता बुनियादी ढांचा, कृषि विकास, गरीब, युवा, महिला और किसान वर्ग के लिए राहत के प्रभावी प्रावधानों के साथ मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र रक्षा, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) स्वदेशी प्रोत्साहन और हरित ऊर्जा पर बड़े ऐलान किए हैं। इनके साथ-साथ भारत को वैश्विक बायो फॉर्मा केंद्र बनाने, शहरी आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण, नए राष्ट्रीय जल मार्ग, सात हाई स्पीड कोरिडोर, व्यापार सुगमता, कंटेनर निर्माण, बुजुर्गों के लिए मजबूत इकोसिस्टम, टीयर-2 और टीयर-3 शहरों के विकास के लिए प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, वित्त मंत्री के समक्ष बजट तैयार करते समय चुनौतियां भी रही हैं। इन चुनौतियों में रुपये में लगातार गिरावट, अमेरिका का ऊंचा टैरिफ, मैन्युफैक्चरिंग व कृषि की धीमी रफ्तार शामिल हैं। निसंदेह वित्त मंत्री बजट के तहत गरीब, युवा, महिलाएं, किसानों के कल्याण के नए उपायों के साथ विकास योजनाओं पर भी अपने आवंटन को बढ़ाते हुए दिखाई दी हैं। बजट में रोजगार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा वेयरहाउसिंग संबंधी प्रोत्साहन, रियल एस्टेट सेक्टर और आवास सेक्टर को प्रोत्साहन, डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने तथा स्वच्छ ऊर्जा के लिए अधिक आवंटन करते हुए दिखाई दी हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि इस बजट में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश, रेलवे, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार और

क्षमता संवर्धन के साथ दीर्घावधि वृद्धि, वैश्विक क्षमता निर्माण और एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिशन मोड के सुधार उभरकर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बजट के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, उद्योग जगत की लाजिस्टिक्स लागत घटाने, रोजगार सृजित करने वाले मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करने संबंधी रणनीतियां भी दिखाई दी हैं। युवाओं के रोजगार बढ़ाने, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार बाजार की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढालने, प्रधानमंत्री कौशल मुद्रा योजना, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ाने के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, वित्तीय समावेशन को बेहतर करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी प्रभावी प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी हैं। सीतारमण बजट में खाद्य महंगाई पर काबू पाने के लिए भी आपूर्ति संबंधी नए कदमों के साथ आगे बढ़ी हैं। बजट में वित्त मंत्री ने रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य रखकर नए रोजगार अवसरों को निर्मित करने की रणनीति भी अपनाई है। विकसित भारत के लक्ष्य के मद्देनजर डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन के प्रावधान भी बजट में दिखाई दे रहे हैं। नए बजट में हर क्षेत्र में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) को अहमियत हेतु प्रावधान किए गए हैं, ताकि भारत एआई का वैश्विक हब बन सके। सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए भी बजट में अधिक धन का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने इस बजट में भारत को दुनिया के बाजार में और अधिक प्रभावी रूप से जुड़ने और भारत को निर्यात का नया हब बनाने के लिए नई रणनीति प्रस्तुत की है।

भारत को यूरोपीय संघ समेत विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के बाद दुनिया के बाजार में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के प्रोत्साहनमूलक प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी हैं। अमेरिका के द्वारा लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ से प्रभावित निर्यात क्षेत्रों को भी राहत देने के मद्देनजर वित्त मंत्री नए निर्यात प्रोत्साहनों की डगर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं।निश्चित रूप से वित्त मंत्री ने इस बजट में सीमा शुल्क के लिए जहाँ राहत दी है, वहीं सीमा शुल्क में सुधार भी किए है। यह बजट इसलिए भी खास रहा है, क्योंकि यह बजट पुराने टैक्स युग से नए टैक्स युग की दहलीज पर खड़ा बजट है। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से करीब 60 साल पुराने टैक्स कानून की जगह नया इनकम टैक्स कानून लागू किया है। इससे देश के करोड़ों आयकरदाता लाभांवित होंगे। साथ ही नई श्रम संहिताएं भी आगामी वित्तीय वर्ष में लागू होने से श्रम उत्पादकता बढ़ेगी और औद्योगिक विकास का नया अध्याय दिखाई देगा। निश्चित रूप से वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा एक फरवरी को प्रस्तुत आगामी वित्त वर्ष 2026-27 का प्रस्तुत बजट कोई साधारण वार्षिक बजट नहीं है, बल्कि यह बजट देश के आर्थिक परिदृश्य को ऐतिहासिक मोड़ देने वाला बजट है। इस बजट से जहां देश में साहसिक सुधारों का नया युग शुरू हो सकेगा, वहीं आम आदमी के लिए अधिक राहत और देश के लिए तेज विकास का नया परिदृश्य निर्मित होगा।

उम्मीद करें कि एक ओर वित्त मंत्री वर्ष 2026-27 के बजट के बजट के लक्ष्य के तहत राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3 फीसदी तक रखने में कामयाब होगी। उम्मीद करें कि इस अभूतपूर्व बजट से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और यह बजट देश को वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला और 2047 तक विकसित भारत बनाने की नींव रखने वाला बजट सिद्ध होगा।

(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

आम बजट
प्रमोद भार्गव

आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट

नए आम बजट से उम्मीद की जा रही थी कि यह आयकर की सारिणी में छूट और पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकलुभावन बजट होगा, लेकिन यह बजट इसके विपरीत आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट है। इसके स्थाई और रोजगार देने वाले परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा। इस बजट की उम्मीदों में तमाम आर्थिक उथल-पुथल और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद अगले वित्त वर्ष में भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की बुनियाद रख दी है। इस समय भारत उद्योग,प्रौद्योगिकी और दवाओं के कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है, किंतु यह बजट कालांतर में चीन को चुनौती बनने वाला है। इस बजट में दुर्लभ खनिजों के उत्खनन को बढ़ावा देने के द्वार खोले जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खनिज के साथ कृषि भी है। अतएव ईयू से जो संधि हुई है, उसके तहत भारत को स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, पेपर, ग्लास, तेल रिफाइनरी और खाद के निर्यात का लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से भारत भूमि को कुदरत ने अटूट प्राकृतिक संपदा दी हुई है। इस संपदा का उत्खनन और उसका उपयोग देश के लोगों के लिए हो, इस नजरिए से दुर्लभ खनिजों के उत्खनन के लिए बजट में ओडिशा, केरल और आंध्रप्रदेश के बीच गलियारा बनाए जाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग भी बनाए जाएंगे। साथ ही वस्त्र, खेलकूद सामग्री,जैविक दवाओं,कंटेनर, इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। रसायन पार्क विकसित होंगे। सेमीकंडक्टर मिशन दो की शुरुआत की जाएगी। चूंकि सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के उपाय निरंतर कर रही है, इस हेतु सेमीकंडक्टर की उपलब्धता जरूरी है।

इस दृष्टि से यह उत्पादन और निर्माण के ढांचागत विकास को स्थापित करने का महाबजट है। दुर्लभ खनिजों के उत्खनन की सुविधा हेतु संसद के मॉनसून सत्र में माइंस और मिनरल्स संशोधन विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। इस नए कानून से व्यवसायियों को लीज पर खनन करने के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लीथियम, कोबाल्ट, निकल, हीरा जैसे दुर्लभ खनिजों के उत्खनन की सुविधा भी मिल गई है। भारत इन खनिजों के लिए अब तक चीन पर निर्भर था, लेकिन चीन ने इनके निर्यात पर रोक लगा दी थी। यही वे खनिज हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी और अंतरिक्ष उपकरणों में काम आते हैं। हालांकि ट्रंप द्वारा लगाए गए अनर्गल टैरिफ के बाद चीन ने भारत को उपरोक्त खनिज देने का वादा किया हुआ है। ईयू से समझौते के बाद दुर्लभ खनिजों के आयात-निर्यात का दायरा विस्तृत हो गया है। इसीलिए भारत अब अपनी शर्तों पर विकसित देशों के साथ व्यापार भी करेगा। अब माइंस और मिनरल्स संशोधन विधेयक पारित हो जाने से उद्योगपति निवेश के लिए आगे आएंगे। मध्यप्रदेश की धरती हीरा और सोना तो उगलती ही है, तांबे और चूने का यहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कटनी में चूने के भंडार हैं। शडहोल और उमरिया में कोयला एवं बॉक्साइड, छिंदवाड़ा में कोयला, बैतूल में ग्रेफाइड और सतना में सिमेंट के भंडार भरे पड़े हैं। मध्यप्रदेश में ईंधन खनन के लिए 12 क्षेत्र चिन्हित किए हैं। कोयला आधारित 37 प्रतिशत मीथेन का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। जबलपुर में सोने के नए भंडार मिले हैं। ग्रेफाइट सहित 30 दुर्लभ खनिज तत्वों की खोज की गई है। इनके उत्खनन व प्रसंस्करण के बाद लीथियम और लौह अयस्क के लिए सीधी में एक क्षेत्र चिन्हित कर दिया गया है। इसके अलावा बजट में जैविक औषधीय दवाओं के उत्पादन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। बायोफार्मा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक हब बनाया जाएगा। सरकार आयुर्वेद दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देगी। इन दवाओं का निर्माण इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये रोग को जड़ से दूर करती हैं। सात द्रुत गति के रेल गलियारे बनेंगे। पटना और वाराणसी में जहाजों की मरम्मत के कारखाने खुलेंगे। छोटे नगरों में तीर्थस्थल विकसित होंगे। इस उपाय से छोटे नगरों में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। इससे स्थानीय लोगों को धर्म संबंधी रोजगार मिलेंगे। एक जिला,एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया गया है। साफ है यह बजट अन्य आम बजटों से एकदम अलग है। इसमें मतदाता को लुभाने और आयकरदाताओं को संतुष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह युवाओं की आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए उद्योग केंद्रित बजट है, जिसके स्थाई और फलदायी परिणाम धीमी गति से आएंगे। जो देश की अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूती देंगे, बल्कि देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

योग के सभी सूत्र सुदृढ़ जीवन की आधारशिला

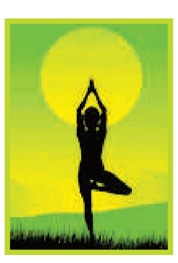

संकलित
दर्शन

योग प्राचीन काल से भारतीय आध्यात्मिक संचेतना का केंद्र रहा है। इसके आदिम सूत्रधार परमयोगी भगवान शिव हैं। योग शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता रहा है। समाधि अर्थ में इसका प्रयोग आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए किया जाता है, जब साधक अपनी साधना की चरमावस्था में परमात्मा से एकाकार होकर उसका साक्षात्कार कर लेता है। अग्निपुराण में भी मन एवं आत्मा तथा आत्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहा गया। सांख्यदर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष का भेद होने पर भी पुरुष का आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना योग कहलाता है। कठोपनिषद् के अनुसार, जब इंद्रियां मन के साथ और मन अविचल बुद्धि के साथ स्थिर हो जाता है तो यह अवस्था योग की होती है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने 'योगः कर्मसु कौशलम्' कहकर योग का जो स्वरूप अजरुन के समक्ष प्रस्तुत किया है वह सामान्य जन के सर्वाधिक निकट है। कोई भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए योग को सिद्ध कर सकता है। योगसूत्र के प्रणोता महर्षि पतंजलि संयमन अर्थ में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। उनके अनुसार यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा आदि आठ अंगों से संपन्न प्राणायाम की विविध क्रियाएं योग कहलाती हैं। इससे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। बुद्धि में स्थिरता आती है। चिंतन उत्कृष्ट होता है। मन में सद्विचारों का उदय होता है। नकारात्मक प्रवृत्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। परिणामतः आत्मिक और शारीरिक शक्तियों में वृद्धि होती है।

मन का भोजन हमारे विचार

संकलित
प्रेरणा

एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और अन्य लोगों को उपदेश दे रहे थे। सत्संग में काफी लोग बैठे हुए थे। भीड़ में से एक व्यक्ति उठा और उसने बुद्ध से पूछा कि तथागत मैं जब ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन ध्यान में नहीं लग पाता है। कृपया बताइए, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध के साथ ही सत्संग में बैठे हुए लोगों ने भी ये प्रश्न सुना, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि कृपया फिर से अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा कि एक बार और अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने एक बार और अपनी बात कह दी। बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार मन के लिए भोजन हैं। जब तक मन को विचारों का भोजन मिलता रहेगा, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। जब हम ध्यान करने बैठे, तब मन को विचारों का भोजन नहीं देना चाहिए, यानी सोच-विचार करना बंद कर देना चाहिए। तब ही हम ध्यान कर पाएंगे। जब मन विचारों से खाली हो जाएगा, तब ही हम ध्यान कर पाएंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से ध्यान के बारे में प्रश्न तीन बार पूछा था और बुद्ध ने भी तीन बार इस प्रश्न का उत्तर दिया। बुद्ध ने तीन बार उत्तर दिया तो लोगों ने पूछा कि आपने इस व्यक्ति से तीन बार प्रश्न पूछा और उत्तर भी तीन बार ही दिया, ऐसा क्यों? बुद्ध ने लोगों को समझाया कि मैं इन सज्जन से तीन बार प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं प्रश्न के लिए इनकी गंभीरता को परखना चाहता था। जब मुझे लगा कि ये अपने प्रश्न के लिए गंभीर हैं, तब मैंने उत्तर भी तीन बार दिया, ताकि मेरी बात इन्हें अच्छी तरह समझ आ जाए।

सटाका

आज की पाती

उपकरणों का सावधानी से प्रयोग करना जरूरी

विज्ञान ने हमें हर मौसम से बचने के लिए बहुत सी चीजें दी हैं। लेकिन अगर हम इनका सावधानी से प्रयोग न करें तो यह हमारे लिए कभी भी हानिकारक बन सकती हैं और अक्सर खबरें भी पढ़ने और सुनने को मिलती हैं कि इन चीजों के प्रयोग करते कई बार हादसा हो गया। सर्दियों में गैस गीजर, कोयले की अंगीठी और अन्य गर्मी प्रदान करने वाले उपकरण लोगों की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। सर्दियों के मौसम में नहाने के लिए लोग गैस से चलने वाले गीजर का भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके प्रयोग में जरा सी भी असावधानी किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। गैस गीजर को बाथरूम में लगाने के साथ-साथ एक खिडक़ी जरूर रखें। लोगों को चाहिए कि जहां गैस गीजर लगा हो वहां हवा बाहर निकलने के लिए जगह होनी चाहिए। - *संजय शर्मा, दुर्ग*

ट्रेंड

बालिका छात्रावास बड़ा निर्णय

बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक घोषणा ! केंद्र सरकार ने देश के हर जिले में बालिका छात्रावास के निर्माण का बड़ा निर्णय लिया है। यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता, सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करने वाला एक मील का पत्थर है।
-अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय महिला विकास मंत्री

अमल भी जरूरी

बजट में विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, वादों और आश्वासनों के सम्बन्ध में भविष्य में इनके परिणामों को लेकर यही लगता है कि इनके नाम तो बड़े-बड़े हैं, किन्तु जमीनी स्तर पर इनके दर्शन छोटे ना हो तो बेहतर होगा। केवल बाते न हों, इन पर सही नीयत से अमल भी जरूरी है।
- मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

निराशाजनक रहा बजट

बजट संबंधी दस्तावेज़ों का विस्तृत अध्ययन करना अभी बाकी है, फिर भी बजट को लेकर जो उम्मीदें की गई थीं, उन पर यह पूरी तरह खरा नहीं उतरता। यह पूरी तरह फीका और निराशाजनक रहा।
- जयराम रमेश, कांग्रेस महासचिव

विकासोन्मुखी बजट

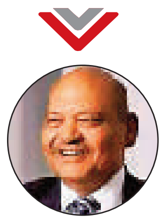

विकासोन्मुखी बजट, जिसमें सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाने और विनिर्माण को बढ़ावा देने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। यह बजट युवाओं को आजीविका सुधारने, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने वाला होगा।
- अनिल अग्रवाल, उद्यमी

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
पीबी-2, चतुर्थ तल, मानसरोवर कॉम्पलैक्स, वार्ड नं. 50, शिवाजी नगर, निकट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, होशंगाबाद रोड, भोपाल, (म.प्र.) 462016
aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

इजराइल की रफाह सीमा क्रॉसिंग खोलने की घोषणा

इजराइल ने फलस्तीनियों के सीमित आवागमन के मद्देनजर गाजा की मिस्र के साथ रफाह सीमा क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोलने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद रफाह सीमा क्रॉसिंग पर रविवार को चहल-पहल देखी गयी। रफाह सीमा क्रॉसिंग को दोबारा खोलना इजराइल-हमास संघर्षविराम के आगे बढ़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इजराइल ने रविवार को घोषणा की कि रफाह क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोल दिया गया है। गाजा को मानवीय सहायता के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली इज़राइली सैन्य एजेंसी सीओजीएटी ने एक बयान में कहा कि क्रॉसिंग को पूर्ण संचालन के लिए सक्रिय रूप से तैयार किया जा रहा है और तैयारियां पूरी होने के बाद गाजा के निवासी यहां से आवागमन शुरू कर सकेंगे। मिस्र के एक अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि फलस्तीनी सुरक्षा अधिकारी मिस्र वाले द्वार से होकर क्रॉसिंग में दाखिल हुए और फलस्तीनी द्वार की ओर बढ़े, जहां वे एक यूरोपीय संघ मिशन के साथ जुड़ेंगे, जो प्रवेश और निकास की निगरानी करेगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि एंबुलेंस भी मिस्र वाले द्वार से होकर गुजरीं।

ऑफ बीट

रात में पसीना आने के कई कारण हो सकते हैं

पसीना आना शरीर की शीतलन प्रणाली का एक सामान्य हिस्सा है, जो गर्मी छोड़ने और शरीर के इष्टतम तापमान को बनाए रखने में मदद करता है।

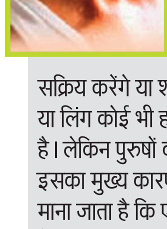

लेकिन नियमित रूप से रात में जागना, अत्यधिक पसीने से भीगना सही नहीं है। मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस, अंत:स्रावी तंत्र का हिस्सा है और शरीर के लिए तापमान नियंत्रण केंद्र है। इसमें तापमान सेंसर होते हैं जो केंद्रीय रूप से (अंगों में) और परिधीय रूप से त्वचा में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं (थर्मोरिसेप्टर्स) से जानकारी प्राप्त करते हैं। थर्मोरिसेप्टर्स शरीर के तापमान में बदलाव का पता लगाते हैं, हाइपोथैलेमस को वापस संकेत भेजते हैं। ये संकेत या तो शरीर को ठंडा करने के लिए पसीने को सक्रिय करेंगे या शरीर को गर्म करने के लिए कंपकंपी को सक्रिय करेंगे। उम्र या लिंग कोई भी हो, किसी को भी रात में पसीना आने का अनुभव हो सकता है। लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को रात में पसीना अधिक आता है, इसका मुख्य कारण रजोनिवृत्ति और संबंधित बदलते हार्मोन स्तर हैं। ऐसा माना जाता है कि एस्ट्रोजन के स्तर में बदलाव से नॉरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन के स्तर पर प्रभाव पड़ता है, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो हाइपोथैलेमस में तापमान विनियमन को प्रभावित करते हैं।

सरकार ने 78 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया

रक्षा बजट में भारी वृद्धि से 'आतंकी देशों' के होश होंगे ठिकाने

रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए भी 21 लाख करोड़ रुपए का किया प्रावधान

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

2026 के रक्षा बजट में कुल 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। रक्षा मंत्रालय के लिए वर्ष 2026-27 के लिए 78 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसके साथ ही रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए 21 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि असैनिक, प्रशिक्षण एवं अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक कलपुर्जों पर मूलभूत सीमाशुल्क में छूट दी जाएगी। रक्षा क्षेत्र की ईकाइयों द्वारा रख-रखाव, मरम्मत अथवा अन्य आवश्यकताओं में इस्तेमाल किए जाने वाले विमान के पुर्जों के निर्माण के लिए आयात किए जाने वाले कच्चे माल पर मूलभूत सीमाशुल्क में छूट दी जाएगी।

रक्षा बजट में 15 फीसदी की बढ़ोतरी

असैनिक, प्रशिक्षण एवं विमानों के निर्माण में कलपुर्जों पर मूलभूत सीमाशुल्क में छूट

आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़

रक्षा मंत्रालय

पिछले साल मई में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला बजट है। इस बजट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आईं कमियों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रक्षा बलों को कैपिटल आउटले बजट के तहत आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे।

तकनीक को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा

सरकार का लक्ष्य भारत की रक्षा शक्ति और तकनीक को और अधिक सुदृढ़ करना है। यह देश की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने को उठाया है। रक्षा क्षेत्र की यूनिट्स द्वारा मेंटेनेंस, रिपेयर या ओवरऑल जरूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट के पाट्‌र्स बनाने के लिए इंपोर्ट किए जाने वाले कच्चे माल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव है।

रक्षा क्षमता और आधुनिकीकरण पर रहा जोर

रक्षा मंत्रालय (सिविल) का बजट मामूली घटकर 28,554.61 करोड़ हो गया है, जिसमें 0.45 फीसदी की कमी दर्ज की गई। रक्षा सेवाओं (राजस्व) का बजट बढ़कर 3,65,478.98 करोड़ हो गया है, जो 17.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। रक्षा पूंजीगत व्यय में सबसे अधिक 21.84फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

भारत के सामने पाकिस्तान का बजट बौना

पाकिस्तान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा मद में 2,550 अरब पाकिस्तानी रुपए आवंटित किए हैं। भारतीय मुद्रा के हिसाब से यह महज 72,850 करोड़ होगा। भारत ने पिछले साल केवल एक हथियार के लिए करीब-करीब पूरे पाकके रक्षा बजट के बराबर खर्च किया था। पाकिस्तानी सरकार ने रक्षा बजट में 20फीसदी का इजाफा किया है।

पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 9.5 फीसदी का इजाफा

बजट 2024-25 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6,21,940 करोड़ का आवंटन किया गया था। इस तुलना से स्पष्ट है कि 2025-26 में रक्षा बजट में लगभग 9.5 फीसदी की वृद्धि की गई है, जो सेना के आधुनिकीकरण की निरंतरता को दर्शाता है। 2024 में, रक्षा मंत्रालय ने 1.26 लाख करोड़ का अब तक का सबसे उच्च स्वदेशी उत्पादन और 21,083 करोड़ का रक्षा निर्यात दर्ज किया था।

खबर संक्षेप

मणिपुर के 20 विधायकों की दिल्ली में मीटिंग

नई दिल्ली। मणिपुर के 20 से अधिक भाजपा विधायकों ने रविवार को राज्य इकाई के अध्यक्ष के साथ इंफाल से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। वे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बड़ी बैठक में शामिल होंगे। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष अधिराजमायुम शारदा देवी ने कहा कि सभी एनडीए विधायकों को बुलाया गया है। प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार का गठन होगा।

शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग, गिरफ्तार

मुंबई। यहां के जुहू इलाके में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई है। जिस समय यह फायरिंग हुई, उस वक्त शेट्टी घर के अंदर ही मौजूद थे। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फायरिंग करने वाला आरोपी केवल एक ही था।

ट्रंप की पत्नी मेलानिया की फिल्म रही फ्लाप

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री 'मेलानिया: 20 डेज टू हिस्ट्री' शुक्रवार को रिलीज हुई। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री लोगों का दिल जीतने में कामयाब नहीं हुई। मेलानिया की डॉक्यूमेंट्री में जनवरी 2025 में डोनल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से ठीक 20 दिन पहले की कहानी दिखाई गई है।

रांची के मां-बेटे की पुरी समुद्र में दर्दनाक मौत

रांची। ओडिशा के पुरी में छुट्टियां मनाने आए रांची के एक प्रतिष्ठित परिवार के लिए शनिवार काल बनकर आया।चक्रतीर्थ रोड स्थित पिंक हाउस क्षेत्र में समुद्र स्नान के दौरान मां को डूबता देख उसे बचाने कूदा इकलौता बेटा भी लहरों की भेंट चढ़ गया। इस हृदयविदारक घटना ने जहां रांची के आरएसएस परिवार में शोक की लहर दौड़ा दी है।

विजया 2 मासूम बच्चों संग ट्रेन के आगे कूदी

हैदराबाद। यहां रविवार की सुबह दिल दहला देने वाली घटना हुई। चेरलापल्ली रेलवे स्टेशन के पास 38 साल की पी. विजया ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ मालगाड़ी के आगे छलांग लगा दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शनिवार रात करीब 12:40 बजे की है, जब सनतनगर जा रही मालगाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। मामले की जांच की जा रही है।

बजट में भूटान, श्रीलंका व अफ्रीकी देशों को मदद के लिए राशि का ऐलान

बांग्लादेश के लिए सहायता में की कटौती, साथ ही चाबहार बंदरगाह पर आवंटन का कॉलम 'गायब'

पड़ोसी और अन्य सहयोगी देशों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के लिए बजट का ऐलान कर दिया है। इसमें भारत के पड़ोसी और अन्य सहयोगी देशों के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की गई है। भूटान से लेकर श्रीलंका और बांग्लादेश से लेकर अफ्रीकी देशों तक की मदद के लिए राशि का ऐलान किया गया है। हालांकि, बांग्लादेश के लिए सहायता राशि में कटौती की चर्चा है। पिठले कुठ समय से भारत के बाग्लादेश के रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे हैं। इस बजट में एक चौंकाने वाली बात यह रही कि चाबहार बंदरगाह के लिए सहयोग राशि वाली पंक्ति को 2026-27 के लिए खाली छोड़ा दिया गया। ऐसे में चाबहार बंदरगाह परियोजना में भारत की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसके लिए सरकार ने फिलहाल कोई राशि जारी नहीं की है। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि भारत इस परियोजना को फिलहार टंडे बस्ते में डाल दिया है। इस पर कोी बात नहीं की गई है।

पड़ोसी देशों के रिश्तों को परखा

चाबहार बंदरगाह परियोजना

इन देशों की मदद पिछले साल के मुकाबले परिवर्तित

लातिन अमेरिकी देशों के लिए आवंटन को दो गुना किया

मंगोलिया के बजट में 5 गुना वृद्धि देखी गई है। लातिन अमेरिकी देशों के लिए आवंटन को सीधे दोगुना कर दिया गया है। सरकार दक्षिण अमेरिका में अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने पर जोर दे रही है। भूटान कोसहायता राशि में मूल्य के मामले में सबसे बड़ी वृद्धि (138.56 करोड़) हुई है, हालांकि प्रतिशत के लिहाज से यह 6.44% है। अफ्रीकी देशों (225 करोड़) और सेशेल्स (19 करोड़) के बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

आपदा प्रबंधन के लिए भारत ने इस बार राशि में किया इजाफा

भारत ने विदेश में आपदा प्रबंधन के लिए सहायता के तौर पर 2025-26 के 64 करोड़ के मुकाबले 2026-27 में 80 करोड़ की राशि आवंटित की है। भारत ने बीते साल इस राशि के जरिए श्रीलंका की दित्वाह चक्रवात से निपटने में मदद की। म्यांमार और अफगानिस्तान की भूकंप के बाद हुई तबाही से निपटने में भी मदद की गई। सरकार ने इस राशि के जरिए कुछ देशों को राहत सामग्री भी पहुंचाई है।

बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार की मदद घटी

बांग्लादेश: प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी कटौती बांग्लादेश की सहायता राशि में की गई है, जिसे आधा (50 फीसदी) कर दिया गया है।

मालदीव और म्यांमार: इन दोनों देशों के बजट में 50-50 करोड़ रुपए की कमी की गई है।

विदेश की बाकी योजनाओं पर ऐसा रहा बजट

- केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय से जुड़े सचिवालयों के लिए 761.21 करोड़ का बजट तय किया।
- दूतावासों-मिशन्स के लिए 5059.30 करोड़ तय किए गए।
- पासपोर्ट और आव्रजन व्यवस्था के लिए 2435.13 करोड़ आवंटित किए गए।
- विदेश में रह रही भारतीय महिलाओं के कल्याण की योजनाओं के लिए पांच करोड़ दिए गए।
- मंत्रालय के अन्य खर्चों के लिए 1265 करोड़ बजट में रखे गए हैं।

चाबहार बंदरगाह के लिए राशि आवंटित नहीं की

बीते दिनों में कई हलकों में यह भी चर्चा हुई कि भारत आने वाले समय में अमेरिका के दबाव में चाबहार बंदरगाह योजना से बाहर भी हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले ही धमकी दी थी कि ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच धमकी दी थी कि उससे व्यापार करने वाले देशों पर 25 फीसदी के अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया जाएगा। भारत पर 50 फीसद टैरिफ लगाया जा चुका है। इसमें 25 फीसदी आयात शुल्क व्यापार के मसले पर, जबकि अतिरिक्त 25 फीसदी रूस से तेल खरीद को लेकर लागू है।

पीएम मोदी ने लुधियाना को दी सौगात

हलवारा एयरपोर्ट का लोकार्पण अगले माह से होगा संचालन

आदमपुर अब जाना जाएगा श्री गुरु रविदास एयरपोर्ट

एजेंसी ▶▶ लुधियाना

कई वर्षों के इंतजार के बाद लुधियाना के लोगों को नया एयरपोर्ट मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवार को लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन कर शहर को बड़ी कनेक्टिविटी की सौगात दी है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से लुधियाना और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच हवाई यात्रा अब और आसान हो जाएगी। मार्च से हलवारा एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू किया जाएगा। शुरुआती चरण में लुधियाना से दिल्ली और दिल्ली से लुधियाना के बीच सप्ताह में पांच दिन एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। एयरपोर्ट के चालू होने से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे लुधियाना की देश के अन्य बड़े शहरों से हवाई संपर्क की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

संत निरंजन दास के पैर छुए

प्रधानमंत्रीरविदासिया समाज के जालंधर स्थित सबसे बड़े धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्लां पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां संत निरंजन दास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें सम्मानित किया। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास एयरपोर्ट कर दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने इसके बाद लुधियाना के हलवारा स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि गुरु रविदास जी ने समाज को एकजुट किया है। उन्होंने कहा कि हमारी भाजपा सरकार ने संत निरंजन दास को सम्मानित किया है।

मेरा रिश्ता 'काशी' से जुड़ा

उन्होंने पंजाबी में कहा कि मैं पंजाब की धरती को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता गुरु रविदास जी की जन्मभूमि काशी से है। पीएम मोदी ने इस दौरान रविदास की वाणी से 3 श्लोक पढ़े। साथ ही काशी (वाराणसी), मध्यप्रदेश और पंजाब में संत रविदास की सेवा करने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर रखा गया है।

पत्रकारों से बातचीत में कहा-हमने पहले ही डील तय कर ली

भारत अब ईरान से नहीं, वेनेजुएला से खरीदेगा तेल, डील हो गई पक्की

अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने किया बड़ा दावा

एजेंसी ▶▶ वॉशिंगटन/ नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तेल खरीद को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा।

उन्होंने कहा कि भारत के साथ इस बारे में डील की गई है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने पहले ही वह डील कर ली है। डील का कॉन्सेप्ट तय हो गया है। ट्रंप का बयान अमेरिका के नई दिल्ली को यह संकेत देने के एक दिन बाद आया है कि वह रूसी कच्चे तेल के कम आयात की भरपाई के लिए जल्द ही वेनेजुएला से तेल खरीदना फिर से शुरू कर सकता है।

खामेनेई की सबसे खतरनाक धमकी

हमला किया तो पूरे मिडिल ईस्ट में होगी क्रांति

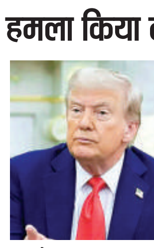

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार को एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर कोई भी सैन्य हमला मध्य पूर्व में 'क्षेत्रीय युद्ध' को जन्म देगा, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष फैल सकता है। यह बयान तब सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस्लामी गणराज्य पर सैन्य हमले की धमकी दी है।

अमेरिका जान ले यह क्षेत्रीय युद्ध होगा

ईरानी सरकारी टेलीविजन ने खामेनेई के हवाले से बताया कि अमेरिकियों को यह पता होना चाहिए कि अगर वे युद्ध शुरू करते हैं, तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। हम उकसाने वाले नहीं हैं और न ही हम किसी देश पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन ईरानी राष्ट्र किसी भी ऐसे व्यक्ति को करारा जवाब देगा जो उस पर हमला करेगा या उसे परेशान करेगा।

एनसीबी के विलय पर असमंजस की स्थिति बरकरार

शपथ ग्रहण पर राकांपा प्रमुख ने दिया स्पष्टीकरण

शरद पवार मुंबई पहुंचे तो बारामती लौट गईं डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार

एजेंसी ▶▶ मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर असमंजस की स्थिति है। इसी बीच, एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार रविवार सुबह बारामती से मुंबई के लिए रवाना हो गए, जबकि नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार देर रात बारामती लौट आईं। शरद पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के चार दिन बाद मुंबई के लिए रवाना हुए। सुनेत्रा ने शनिवार को मुंबई में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पुणे जिले के बारामती स्थित अपने आवास लौट आईं।

शपथ ग्रहण पर मुझसे बात नहीं हुई: शरद

सुनेत्रा के शपथ ग्रहण को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझसे कोई चर्चा नहीं हुई। यह फैसला पार्टी ने स्वयं लिया होगा। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने पहल की होगी और संभव है कि पार्टी के भीतर ही यह निर्णय लिया गया हो।

12 फरवरी को होने वाला था विलय

शरद ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि अजित पवार ने 12 फरवरी को एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की घोषणा करने की तारीख तय की थी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने पाकिस्तान की खोली पोल

नाकामी छिपाने 92 बलूच विद्रोहियों को मारने का किया दावा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। इन हमलों में 80 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं। वहीं पाकिस्तान ने दावा करते हुए कहा है कि उसके 18 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 92 बलूच विद्रोही मारे गए हैं। पाक ने अपने घर में लगी आग के लिए भारत पर भड़ास निकाली है। चीन के हस्तक्षेप, सीपीईसी प्रोजेक्ट और ग्वादर बंदरगाह के लिए बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन निवासियों की जिंदगी बदतर है। इसी के विरोध में बलूच विद्रोही संगठन अकसर पाकिस्तानी सेना, पंजाबी मूल के लोगों और यहां तक की चीनी नागरिकों पर भी निशाना साधते रहते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर पाक की पोल खोल दी है।

पाकिस्तान बोला- 18 सैनिक मारे गए

घर में आग और भारत पर भड़ास निकाल रहा पाक

बलूचिस्तान में सैनिकों के ढेर होने पर बोला पाक

इस बार बलूचों ने किया सबसे बड़ा अटैक

कई बार बलूच विद्रोही संगठनों ने खूनी हमले भी किए हैं। इस बार अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक अटैक किया है। पाकिस्तान इन हमलों की वजह तलाशने की बजाय भारत पर ही भड़ास निकाल रहा है। पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा यूनिट आईएसपीआर ने इसके लिए भारत को जिम्मेदार बताने की कोशिश की है। उसने कहा कि ये हमले भारत से मदद पाने वाले फितना-अल-हिंदुस्तान नाम के संगठन ने किए हैं। ये हमले क्वेटा, मस्तंग, नुशकी, दलबंदीन, खारन, पंजगुर, ग्वादर और पसनी में हुए हैं। एक साथ ही कई शहरों पर बलूच विद्रोहियों ने हमले किए हैं। पाकिस्तान जैसे संगठन की बात कर रहा है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।

भारत ने पाक के आरोपों को सिरे से खारिज किया

बलूचिस्तान में हिंसा पर पाक ने भारत पर झूठे आरोप मढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन रविवार को भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं । विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम पाक द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं, जो उसके अपने अंदरूनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की उसकी सामान्य चाल के अलावा और कुछ नहीं है। जायसवाल ने कहा कि पाक को बेबुनियाद दावे करने की जगह अपने लोगों की मांग को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल पाक के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भारत पर आरोप लगाया था।

बजट से पहले आमजन को झटका

कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में हो गया 49 रु. का इजाफा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय बजट से ठीक पहले आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 49 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 फरवरी से लागू हो गई है। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरों के मुताबिक, दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा कीमत अब बढ़कर 1,740.50 रुपए हो गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे लोगों के रसोई का बजट बिगड़ सकता है।

शुरू हुई रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी की तैयारी

मुंबई। काफी समय से साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर खबर चल रही है। ऐसी चर्चा थी कि फरवरी महीने में दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उदयपुर से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया है कि यहां पर रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी होने वाली है। यह शादी 2 फरवरी को होगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जो उदयपुर के सिटी प्लेस का है। इस वीडियो में दो लड़कियां बताती हैं कि यहां पर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की कल शादी होने वाली है।

लाइफStyle

नीलम

गोविंदा के साथ रोमांस की अफवाहों पर रखी राय

अभिनेता गोविंदा कई वजहों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अब वह अभिनेत्री नीलम के बयान के बाद चर्चा में आ गए हैं। 1980 और 1990 के दशक में गोविंदा ने नीलम कोठारी के साथ कई फिल्मों में काम किया।

एजेंसी ▶▶ मुंबई

दोनों ने अपनी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीता। अक्सर उनके रोमांस की अफवाहें उड़ीं। गोविंदा ने यह माना कि वह नीलम की तरफ आकर्षित थे। उन्होंने उनसे शादी करने के बारे में सोचा था। हालांकि, नीलम ने अब इस तरह की बातों को पूरी तरह से खारिज किया है। उषा काकडे प्रोडक्शन के साथ बातचीत में नीलम कोठारी से गोविंदा के साथ रोमांस के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा 'यह किसने कहा? गोविंदा जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मगर यह जो सवाल है, यह सच नहीं है। हमने कई हिट फिल्में की हैं। हमारे बीच कुछ नहीं था।' एक्ट्रेस ने 90 के दशक में अपनी केमिस्ट्री को लेकर मीडिया में मचे बवाल के बारे में कहा, 'मुझे लगता है कि उस वक्त लिंक-अप्स पर कोई सफाई देने वाला नहीं था। उन्हें जो मन करता था, वे छाप देते थे। मुझे लगता है कि उन दिनों हम प्रेस से डरते थे। अगर आप किसी के साथ लगातार 2-3 से ज्यादा फिल्में करते थे, तो यह मान लिया जाता था कि... आप दोनों साथ हैं।' 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में, गोविंदा और नीलम कोठारी ने लगभग एक दर्जन फिल्मों में काम किया। इसमें 'इल्जाम', 'खुदगर्ज', सिंदूर, फर्ज की जंग, बिल्लू बादशाह, ताकतवर और घराना जैसी फिल्में शामिल हैं।

हॉलीवुड मसाला

रैपर पर टूटा दुखों का पहाड़

लॉस एंजिल्स। हॉलीवुड के लोकप्रिय रैपर-सिंगर और एक्टर स्नूप डॉग की पोती का निधन हो गया है। स्नूप की महज दस महीने की पोती कोडी ड्रेक्स का निधन 26 जनवरी को हुआ। बेबी कोडी अस्पताल में भर्ती थी। घर लौटने के कुछ ही हफ्ते बाद बच्ची का निधन हो गया। बता दें कि कोडी, स्नूप डॉग की बेटी कोरी ब्रॉडस की बिटिया थीं। कोरी ब्रॉडस, स्नैप डॉग की सबसे छोटी संतान हैं और वे इकलौती बेटी हैं। कोरी की दस महीने की बेटी कोडी ड्रेक्स के निधन से परिवार शोक में डूबा है।

कैथरीन को याद किया एक्टर मैकाले ने ...

लॉस एंजिल्स। हॉलीवुड की चर्चित फिल्म 'होम अलोन' की एक्ट्रेस कैथरीन ओहारा ने निधन से हॉलीवुड में दुख की लहर है। उनके साथ अभिनय करने वाले कलाकार भी गमगीन हैं। 'होम अलोन' में चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल में दिखे मैकाले कल्किन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कैथरीन को याद किया है। फिल्म 'होम अलोन' में साल 1990 में रिलीज हुई थी। उस वक्त मैकाले कल्किन एक चाइल्ड आर्टिस्ट थे। अब वह 45 साल के हो चुके हैं। फिल्म 'होम अलोन' में उनके किरदार केविन की मां का रोल कैथरीन ने निभाया था। मैकाले, कैथरीन के काफी करीब थे। एक्ट्रेस के निधन की खबर सुनकर वह काफी दुखी हैं। शनिवार को मैकाले कल्किन ने एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए कैथरीन को याद किया है।

अरिजीत के फैसले पर जताई हैरानी...

मुंबई। अरिजीत सिंह ने अचानक प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के अपने फैसले से हर किसी को हैरान कर दिया। अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने भी अरिजीत सिंह के फैसले पर हैरानी जताई है। साथ ही उनका कहना है कि वो अब फिल्मों में अरिजीत के गानों को मिस करेंगी। अदिति ने कहा कि हे भगवान! मुझे अरिजीत की आवाज बहुत ही पसंद है। मुझे उनकी बहुत याद आएगी। उनकी आवाज की बहुत याद आएगी। लेकिन आप जानते हैं, मेरा मानना है कि एक कलाकार हमेशा कलाकार रहता है। एक रचनाकार हमेशा रचनाकार रहता है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ करने की शक्ति, इच्छाशक्ति, सपना, प्रेम हमेशा आपके भीतर रहता है। एक रचनाकार हमेशा सृजन करता रहेगा। इसलिए वह हमेशा गाते रहेंगे।

'टॉक्सिक' के टीजर का का किया बचाव

मुंबई। फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिकः ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के टीजर का सपोर्ट किया है। उन्होंने बताया कि टॉक्सिक के क्लिप के खिलाफ विरोध से पता चलता है कि दर्शक स्क्रीन पर पुरुष और महिला की सेक्सुअलिटी पर कैसे दोहरा रवैया अपनाते हैं। 17वें बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान 'फियरलेस फिल्ममेकिंग' नाम के एक सेशन में अनुराग कश्यप ने कहा, 'टॉक्सिक के टीजर के खिलाफ जो गुस्सा दिखाया जा रहा है, वह हमारे कल्चरल पाखंड को दिखाता है। जब मेल एक्टर स्क्रीन पर शर्टलेस दिखते हैं या मर्दानगी दिखाते हैं, तो कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन जब कोई महिला अपनी सेक्सुअलिटी को दिखाती है, तो उसे स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है।'

टीवी मसाला

टीवी की 'नागिन' चली बड़े पर्दे की राह कई सीरियल्स पर बनीं चर्चित फिल्में

मुंबई। एकता कपूर सीरियल 'नागिन' सीरीज को फिल्म के तौर पर भी पेश करने वाली है। ऐसी चर्चा सुनने को मिल रही है। जानिए, 'नागिन' सीरियल से पहले कौन-कौन से सीरियल पर फिल्म बन चुकी है। कुछ हिंदी टीवी सीरियल की कहानी बॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर होती है। लेकिन कुछ सीरियल अपने अलग तरह के कंटेंट की वजह से चर्चा में रहते हैं। इन दिनों 'नागिन 7' ने टीवी सीरियल की दुनिया में हलचल मचा रखी है। खबर है कि प्रोड्यूसर एकता कपूर अब इस सीरियल को फिल्म के तौर पर भी बनाने वाली है। लेकिन यह पहला सीरियल नहीं होगा, जिस पर फिल्म बन रही है। इससे पहले भी कई सीरियल ने यह राह पकड़ी है। जानिए, ऐसे ही कुछ चर्चित सीरियल्स के बारे में।

नागिन : हाल ही में एकता कपूर प्रोड्यूस सीरियल 'नागिन 7' टीवी पर टेलीकास्ट हुआ है। तीसरे हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में इसने टॉप पर जगह बनाई है। यह सीरियल दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। सीरियल में नागिन का लीड रोल प्रियंका चाहर चौधरी निभाई रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस टीवी सीरीज पर अब प्रोड्यूसर एकता कपूर फिल्म बनाने का सोच रही हैं। तो दर्शकों को टीवी की 'नागिन' बड़े पर्दे पर दिख सकती है।

खिचड़ी : सीरियल 'खिचड़ी' को दर्शकों ने टीवी पर खूब प्यार दिया था। यह कॉमेडी सीरियल जेडी मजेठिया ने प्रोड्यूस किया था। इस सीरियल पर एक फिल्म 'खिचड़ी द मूवी' साल 2010 में बनी थी। फिल्म में भी सीरियल की कास्ट नजर आई। इसमें सुप्रिया पाठक, राजीव मेहता, निमिषा वखारिया और जमनादास मजेठिया लीड रोल में दिखे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक-ठाक कलेक्शन किया था। साल 2023 में 'खिचड़ी 2' फिल्म भी रिलीज हुई थी। इन दोनों फिल्मों को फिल्म आतिश कपाड़िया ने निर्देशित किया था।

चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस : साल 2010 में पंकज कपूर अभिनीत फिल्म 'चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस' भी रिलीज हुई। यह फिल्म भी टीवी के पॉपुलर सटायर कॉमेडी शो 'ऑफिस ऑफिस' पर बनी थी, यह सीरियल 2001 में टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था। सीरियल और फिल्म में पंकज कपूर एक आम आदमी के रोल में नजर आए, जो सरकारी सिस्टम के जाल, भ्रष्टाचार के बीच फंस जाता है। फिल्म के निर्देशक राजीव मेहरा थे।

भाबी जी घर पर हैं : सीरियल 'भाबी जी घर पर हैं' भी टीवी पर कई साल से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। अब इस सीरियल के किरदार और कहानी को दर्शक बड़े पर्दे पर फिल्म के रूप में देखेंगे। सीरियल 'भाबी जी घर पर हैं' में आसिफ शेख, शुभांगी अत्रे, रोहताश गौर जैसे एक्टर्स नजर आते थे। यह सभी फिल्म का भी हिस्सा हैं। वहीं फिल्म में रवि किशन, मुकेश तिवारी जैसे उम्दा कलाकार भी फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म 'भाबी जी घर पर हैं' 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म को शंशाक बाली ने निर्देशित किया है।

गौरव खन्ना के तलाक की चर्चा पर आकांक्षा ने दी प्रतिक्रिया

मुंबई। गौरव खन्ना बिग बॉस 19 जीतने के बाद से लगातार चर्चाओं में बने हैं। कभी अपनी पार्टी तो कभी अपनी पत्नी का डांस और अब पत्नी की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर। अब हाल ही में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा की थी। जिसके बाद गौरव और आकांक्षा के तलाक के कयास लगाए जाने लगे थे। अब इन खबरों के बढ़ने के बाद आकांक्षा ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। बातचीत में आकांक्षा चमोला ने अपनी पोस्ट के बाद शादी में कलह को लेकर चलने वाली खबरों को खारिज किया। आकांक्षा ने कहा कि हमारे वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं है, और उस पोस्ट का गौरव से कोई लेना-देना नहीं था। मैं सोशल मीडिया पर निजी मामलों पर चर्चा नहीं करती। वह पोस्ट मेरी आने वाली सीरीज के प्रमोशन के लिए थी। इसका अलग-अलग अर्थ निकाला जा सकता था, लेकिन इसे बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। मेरा वैवाहिक जीवन स्थिर है और पोस्ट का निजी जीवन से कोई संबंध नहीं है।

हमारे बीच कोई तुलना नहीं : ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर आकांक्षा ने कहा कि मैं इस समय ट्रोलिंग की क्वीन बनी हुई हूं। मैं हमेशा से इस विषय पर खुलकर बोलती रही हूं। गौरव थोड़ा सतर्क हैं क्योंकि वह मेरी इमेज की रक्षा करना चाहते हैं। हमारे बीच उम्र का अंतर है और वह मेरी बात समझने के लिए काफी समझदार हैं। मैंने साफ तौर पर कहा है कि मैं मातृत्व को नहीं चुनती। यह मेरा निजी फैसला है और मुझे इसे किसी के सामने सही ठहराने की जरूरत नहीं है।

रहमान ने अपने बयान का किया बचाव और कहा, 'दुनिया के साथ यही दिक्कत है...'

मुंबई। एआर रहमान 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के नए शो में नजर आए। यहां उन्होंने फिल्म 'गांधी टॉक्स' के बारे में बात की। उन्होंने इंडस्ट्री में काम मिलने वाले अपने बयान की तरफ भी इशारा किया। संगीतकार एआर रहमान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने पर दिए गए अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। पिछले महीने उन्होंने यह कहकर सबका ध्यान खींचा था कि हाल के दिनों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री 'सांप्रदायिक' हो गई लगती है। बाद में उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरह से लिया गया। अब उन्होंने कहा कि कोई भी संदेश आगे बढ़ने पर बदल सकते हैं।

बयान पर क्या बोले एआर रहमान : एआर रहमान 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के नए एपिसोड में नजर आए। यहां उन्होंने कहा 'यह देखना दिलचस्प है कि जानकारी कैसे गलत समझी जाती है। अलग राज्य और अलग संस्कृति का असर पड़ता है। दुनिया के साथ यह दिक्कत है कि कोई भी संदेश बीच में ही खराब हो जाता है।'

'गांधी टॉक्स' पर बोले रहमान

एआर रहमान शो में अपनी नई फिल्म 'गांधी टॉक्स' के बारे में बात करने के लिए आए थे। इस फिल्म का निर्देशन किशोर बेलेकर ने किया है। इसमें विजय सेतुपति और अदिति राव हैदरी ने अहम किरदार निभाया है। फिल्म के बारे में बात करते हुए संगीतकार ने कहा कि बिना डायलॉग वाली फिल्म में काम करने में आजादी भी थी और दबाव भी था। उन्होंने कहा 'अगर किसी फिल्म में आवाज नहीं है तो यह संगीत के लिए जश्न है। आपके पास संगीत बनाने के लिए बहुत मौका है। हालांकि यह परेशान करने वाला भी है कि लोग आपको जज करेंगे।'

क्या बोले थे रहमान?

एआर रहमान ने हाल ही में बीबीसी एशियन नेटवर्क के साथ बातचीत में बताया था कि पिछले आठ वर्षों में उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कम काम मिला है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा 'शायद पिछले आठ वर्षों में पावर शिफ्ट हुआ है। अब पावर उन लोगों के पास है जो क्रिएटिव नहीं हैं। यह कोई सांप्रदायिक बात भी हो सकती है... लेकिन यह मेरे साथ नहीं हुआ।' उनके इस बयान पर कई सेलेब्स ने प्रतिक्रिया दी थी। इसके बाद रहमान ने सफाई दी थी।

इस बार अवॉर्ड फंक्शन को कॉमेडियन ट्रेवर नोआ कर रहे हैं होस्ट

अब तक कई भारतीयों को मिल चुका है ग्रैमी अवॉर्ड

जाकिर हुसैन को अलग-अलग कैटेगरी में चार बार मिला ग्रैमी

साल 1994 में विश्व मोहन भट्ट को बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक अल्बम के लिए अवॉर्ड मिला था। इसके अलावा भारत के दिग्गज तबला वादक जाकिर हुसैन को चार बार ग्रैमी अवॉर्ड मिला है। जाकिर हुसैन को पहली बार साल 2009 में बेस्ट कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक अल्बम के लिए ग्रैमी मिला था। इसके बाद जाकिर हुसैन को साल 2023 में राकेश चौरसिया के साथ बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी मिला। 2024 में जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया ने फिर ग्रैमी अवॉर्ड जीता। इस बार दोनों को बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल अल्बम के लिए ग्रैमी मिला था। 2024 में जाकिर हुसैन को फिर ग्रैमी मिला। इस बार वो शक्ति बैंड का हिस्सा थे।

मुंबई। 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स भारत में सोमवार को देखने को मिलेंगे। इस बार कई भारतीयों को नॉमिनेशन मिला है। लेकिन इससे पहले जानते हैं उन भारतीयों के बारे में जिन्होंने अब तक ग्रैमी अवॉर्ड जीता है। संगीत जगत के सबसे बड़े अवॉर्ड ग्रैमी अवॉर्ड का आयोजन 1 फरवरी को लांस एंजिल्स के क्रिप्टो कॉम एरिना में किया गया। इस अवॉर्ड में भारत की भी नजरें लगी हुई हैं। क्योंकि अनुष्का शंकर समेत भारत की ओर से संगीतकार सिद्धांत भाटिया, शक्ति और पियानो वादक एवं संगीतकार चारू सूरी को भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए नामित किया गया है। इनमें से कौन ये अवॉर्ड अपने नाम करेगा, इसका तो समय आने पर ही पता चलेगा।

इन्हें भी मिला है अवॉर्ड

इसके अलावा कई भारतीयों ने ग्रैमी अपने नाम किया है। पीए दीपक (2 बार) (2010 और 2022) एच श्रीधर (2010) गुलजार, एआर रहमान और तन्वी शाह (2010) रिकी केज (3 बार) (2015, 2019, 2023) फैलू (2022) वी सेलवागणेश, गणेश राजगोपालन, शंकर महादेवन और चंद्रिका टंडन के भी नाम शामिल हैं। इन सभी को साल 2024 में मिला था। इस बार 68वें ग्रैमी अवॉड्र्स का आयोजन 1 फरवरी रविवार को हुआ। यह अवॉर्ड फंक्शन रात 8 बजे से शुरू हुआ और 11.30 बजे (अमेरिका के समयानुसार) तक चलेगा। यह यूट्यूब और ग्रैमी अवॉड्र्स की वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम होंगे। वैसे यह अवॉर्ड फंक्शन सीबीएस (ब्रॉडकास्टर) पर भी टेलीकास्ट होंगे। हालांकि, भारत में ग्रैमी अवॉर्ड को सोमवार 2 फरवरी को देखा जा सकेगा। भारत में ये 2 फरवरी सुबह 6:30 बजे से जीयो हॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकता है। इस बार अवॉर्ड फंक्शन को कॉमेडियन ट्रेवर नोआ होस्ट कर रहे हैं। वह आखिरी बार ग्रैमी को होस्ट करने वाले हैं।

पंडित रविशंकर पहले भारतीय

ग्रैमी अवॉर्ड जीतने वाले भारतीयों की बात करें तो सबसे पहले साल 1968 में पंडित रविशंकर ने जीता था। इसके बाद उन्हें साल 1973, 2002 और 2013 में भी ये अवॉर्ड मिला है। 2013 में ही पंडित रविशंकर को लाइफटाइम अचीवमेंट भी मिला था।

हरिभूमि

भोपाल भूमि फ्रंट पेज

भोपाल, सोमवार 2 फरवरी 2026

आम बजट 2026

MSN माता श्री नेत्रालय
मल्टीस्पेशलिटी नेत्र संस्थान
माताश्री नेत्रालय विगत 42 वर्षों से नेत्र सेवा में तन्मयता से सेवारत...
नेत्र सेवा में विश्वास
डॉ. पी.एस. बिन्द्रा
M.B.B.S., M.D., D.O.M.S.
डॉ. प्रीति बिन्द्रा M.B.B.S., M.S., FCRS लेजर विशेषज्ञ
डॉ. चाहवीर बिन्द्रा M.B.B.S., M.S., FRVS रेटिना विशेषज्ञ
जी-2, मनोरा होम्स के पास (ओरा मॉल के पीछे) गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल
समय : सुबह 10.30-3 बजे तक शाम 4.30-6.30 बजे (रविवार अवकाश)
फोन : 0755-2562222, 2562233
मो.: 9826084896

गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी वर्ग को बजट दर बजट मिली जीवन में सौगातें

बसंत में बिखरे फागुन के 'रंग'

सरकार की योजनाएं आमजन तक पहुंच रही हैं तो जीवन स्तर में आ रहा सुधार

परिवारों ने टीवी पर लाइव देखा आम बजट, सरकार की सराहना की, कहा- इस बार का बजट उम्मीद और भरोसे से भरा रहा

प्रावधान

- केंद्र सरकार पशुपालन सेक्टर में होने वाली स्टार्टअप पर खास फोकस करेगी, जिससे रोजगार में बढ़ोतरी हो। मेडिकल, शिक्षा, उद्योग के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान

हरिभूमि न्यूज ▸▸ भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट पेश किया। बजट में सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास, स्वरोजगार पर जोर दिया गया है। सरकार का आम बजट लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला रहा है। सरकार की योजनाओं ने गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी वर्ग को सहयोग आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। सरकार की योजनाएं लोगों की जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाकर परिवर्तनकारी साबित हुई है।

पहले किराए के मकान में रहते थे, अब सरकार ने छत दी, अच्छा वातावरण मिला, जीवन स्तर में आया सुधार, बच्चे शिक्षित हो रहे

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों में रह रहे परिवारों के लिए इस बार का बजट उम्मीद और भरोसे से भरा रहा। शहर के कोकता ट्रांसपोर्ट नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने भवन में रहने वाले परिवारों ने घरों में बैठकर टीवी पर बजट का लाइव प्रसारण देखा और हरिभूमि से अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सरकार की योजनाओं से जीवन में बड़ा बदलाव आया है। पहले किराए के मकान में रहते थे। दूषित वातावरण के बीच जीवनयापन कर रहे थे। सरकार ने पक्के मकान बनाकर दिए। इससे जीवन स्तर में बदलाव आया। अच्छा वातावरण मिला और बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। सरकार का आम बजट सौगातों वाला है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ने सम्मान के साथ जीने का अवसर दिया

निम्न मध्यम वर्ग को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले आवासों का लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना में रहने वाले परिवारों का कहना है कि पक्की छत मिलने के बाद बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा पा रहा है। बच्चे नियमित स्कूल जा रहे हैं और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही स्वच्छ माहौल मिलने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी कमी आई है। उक्त परिवारों ने कहा कि सरकार की योजनाएं जब सीधे आमजन तक पहुंचती हैं, तभी असली विकास दिखाई देता है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका जीवंत उदाहरण है, जिसने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सम्मान के साथ जीने का अवसर दिया है। बजट को लेकर परिवारों ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को और मजबूती मिलेगी, ताकि प्रधानमंत्री आवास के साथ-साथ समग्र जीवन स्तर में भी निरंतर सुधार होता रहे। सरकार हर वर्ग का पूरा ख्याल रख रही है।

किराए के घर से मिला छुटकारा, आर्थिक बोझ घटा

सी-11-105 में रहने वाले राकेश झा ने बताया कि पहले वे किराए के मकान में रहते थे। बार-बार घर बदलने से न सिर्फ आर्थिक बोझ बढ़ता था, बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। अब पक्का घर मिलने से स्थिरता आई है, बच्चों का भविष्य सुरक्षित लग रहा है। सी-1-603 में रहने वाले ब्रिज मोहन सिंह और दीपचंद कुशवाहा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके जीवन स्तर को पूरी तरह बदल दिया है। हम अब साफ-सुथरे, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण में रह रहे हैं।

सोलर पैनल से होगी किसानों को बचत, बिजली पर निर्भरता होगी कम, किसानों के लिए राहत भरा रहेगा केंद्र सरकार का आम बजट

किसानों की आमदनी दोगुनी करने ठोस उपाए किए जाने की जरूरत है। किसान सिर्फ मजदूर के रूप में कभी विकास नहीं कर पाएगा। जब तक उसका स्किल इंप्रूव नहीं होता। किसानों को खेती के साथ अन्य कामों में भी आगे आना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस बजट में किसानों को सोलर पैनल में छूट दी है, जिससे किसानों को बचत के साथ बिजली पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। यह बात बैरसिया रोड स्थित चंदेरी में सात एकड़ जमीन के किसान अंबरीश मीणा ने कही। रविवार को वह अपने परिवार के साथ खेत पर काम के साथ केंद्र सरकार के बजट पर नजर रखे हुए थे। उन्हें उम्मीद है कि यह बजट किसानों के लिए राहत का बजट रहेगा।

अन्नदाता वर्गः चंदेरी के किसान अंबरीश मीणा के जीवन में बदलाव लाई सरकारी योजनाएं

आमदनी के लिए लगाई सब्जियां

किसान की पत्नी मनीषा मीणा ने बताया कि किसानी के काम में परिवार के सभी लोग मदद करते हैं। इस बार खेत में लोकबन गेहूं और चना की बोवनी की है। अगले मार्च के शुरुआती सप्ताह में फसल तैयार हो जाएगी, जिसकी कटाई कराना पड़ेगी। खेत के कुछ हिस्से में प्याज, लहसुन, आलू, हरी मिर्च और धनिया बोया है। यह घर के उपयोग के लिए लगाया गया है। जिससे इन चीजों को बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़े।

पशुपालन में रोजगार को बढ़ावा

इस बजट में पशुपालन पर खास फोकस रखा गया है। सरकार पशुपालन सेक्टर में होने वाली स्टार्टअप पर खास फोकस करेगी, जिससे रोजगार में बढ़ोतरी हो। इसके साथ पशुधन, डेयरी और मुर्गी पालन के प्रोडक्शन पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में एक जिला-एक उत्पाद योजना को मजबूत करेंगे। जिससे प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट बढ़ेंगे। मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा।

मौसम से फसल पर मार, कम होगा उत्पादन

किसान ने बताया कि इस बार गेहूं की फसल के हिसाब से मौसम नहीं रहा, जिससे गेहूं की फसल की पैदावार कम होने का अनुमान है। पहले लोकबन का एवरेज एक क्विंटल बोवनी में करीब बीस क्विंटल रहता था, लेकिन इस बार यह 16 से 20 क्विंटल रह सकता है। इसी तरह अन्य वैरायटी के गेहूं की पैदावार पर भी असर पड़ा है।

हास्य-व्यंग

सरकार ने दिल खोल के ऐसा बजट दिया...

अमीर का भी चेहरा खिला इस बजट में है, गरीब का भी कपड़ा सिला इस बजट में।
सरकार ने दिल खोल के ऐसा बजट दिया, हर वर्ग को अधिकार मिला इस बजट में।
सौगात यहां ऐसी मिली इस बजट में, मुरझाया हुआ चेहरा खिला इस बजट में।
था मलाल जो यहां पर दो दिलों के बीच, सब मिट गया है शिकवा-गिला इस बजट में।

-दिनकर कवि

उमेश ने मध्य प्रदेश सरकार से ऋण लेकर शुरू किया व्यापार, वार्षिक टर्नओवर तीन करोड़ रुपए पहुंचा, 18 लोगों को रोजगार भी दिया

उमेश अहिरवार बायोडिग्रेडेबल बैग के व्यवसाय से बने सफल उद्यमी

जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए सरकार तरह-तरह की योजनाएं बना रही है, ताकि इस दिशा में काम किए जा सके। पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान देने के लिए भोपाल के युवा उमेश अहिरवार ने एमएस पॉल्युशन कंट्रोल इंडस्ट्री शुरू की। वर्ष 2027 में शुरू की इस इंडस्ट्री के लिए उमेश ने सरकारी योजना का लाभ लिया। उमेश ने बताया कि उन्हें 79 लाख रुपए का ऋण मिला और 48 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ। उनका वार्षिक टर्नओवर 60 लाख रुपए से बढ़कर तीन करोड़ रुपए हो गया है। उमेश ने बताया कि इंडस्ट्री में उन्होंने 18 लोगों को रोजगार दिया है।

चाइना, इंडोनेशिया, दुबई में भी बायोडिग्रेडेबल बैग की डिमांड

उमेश ने बताया कि कैरी बैग्स की मुंबई, दिल्ली, बैंगलुरु, नागालैंड, गुवाहाटी, इंदौर सहित अन्य शहरों में डिमांड है। साथ ही बैग्स चाइना, इंडोनेशिया, दुबई निर्यात किए जाते है। उमेश ने बताया कि उनकी इंडस्ट्री में ईको फ्रेंडली कै री बैग्स तैयार किए जाते है। इन्हें बायोडिग्रेडेबल बैग कहा जाता है। यह देखने में प्लास्टिक बैग जैसे होते है। लेकिन यह प्लास्टिक नहीं है। उनके इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार और मप्र पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त है।

बीटेक और एमबीए करने के बाद नौकरी करने में भी नहीं लगा मन

उमेश ने बताया कि उन्होंने बीटेक और एमबीए करने के बाद तीन साल नौकरी की। पर नौकरी में उनका मन लगा। वे अक्सर पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षक जैसे विषयों पर चर्चाएं देखते-सुनते थे। वे भी पर्यावरण सुरक्षा के अपना योगदान देना चाहते थे। तभी एक दिन उनके फ्रेंड कुछ सामान लेकर आए। सामान जिस पैकेट में रखा था, वो देखने में प्लास्टिक जैसा था, जिस पर लिखा था आईएम नॉट प्लास्टिक। यहीं से उन्हें आइडिया आया और उन्होंने खुद की इंडस्ट्री शुरू की। वे कहते हैं कि मप्र शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से उनका व्यवसाय शुरू करने का सपना पूरा हुआ। आज वह आत्मनिर्भर है और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं।

सरकार की सहायता से आत्मनिर्भर बनीं जयश्री पंडित

सरकार की एमएसएमई योजना का लाभ लेकर शुरू किया कपूर मैन्युफैक्चरिंग का काम

एमएसएमई के क्षेत्र के लिए बजट में सरकार ने की घोषणाएं, आमदनी में होगी बढ़ोतरी

कोलार निवासी जयश्री पंडित ने बताया कि मैं सरकार की एमएसएमई योजनाओं से जुड़ी हुई हूं, जिसमें मैं कपूर की मैन्युफैक्चरिंग करती हूं और इसके जरिए में अर्निंग करती हूं। इसमें मेरे साथ काम करने वाले तीन और लोग जुड़े हैं, जो मार्केटिंग भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग का कार्य भी करते हैं, जिसमें हमें साल का करीब 20 लाख का टर्नओवर हो जाता है। अब तो सरकार ने एमएसएमई के क्षेत्र में और भी बढ़ोतरी की है, तो हम हमारा अंदाजा है कि सरकार की बजट प्रस्तुति से हम लोगों को और भी फायदा होगा। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सरकार को और भी प्रयास करने चाहिए, जिससे हम जैसी महिलाएं इस क्षेत्र से जुड़े और स्वयं का उद्धम स्टार्ट कर पाए और आत्मनिर्भर बनकर परिवार, प्रदेश और देश की आर्थिक समृद्धि में ज्यादा योगदान दे पाए।

आम बजट पर वरिष्ठ पत्रकारों की राय

आम बजट में सशक्त और समृद्ध भारत की ओर एक मजबूत कदम की झलक

रमेश शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए बजट में यद्यपि उपभोक्ता को व्यक्तिगत और सीधा लाभ तो कम है, लेकिन यह बजट भारत के आर्थिक आधार को मजबूत करते हुए आधुनिकीकरण की ओर यात्रा को तेज किया गया है। यह बजट तात्कालिक लाभ के लिए तो कम, लेकिन विकसित भारत राष्ट्र की लंबी यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। बजट के अधिकांश प्रावधान दूरगामी हैं। जैसे छोटे नगरों का विकास, सात नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, पांच हजार इलेक्ट्रॉनिक्स बसें चलाना, स्वदेशी जहाज का निर्माण आदि ऐसी योजनाएं हैं, जो एक वर्ष में पूरी नहीं होगी। कम से कम पांच साल का समय लगेगा। लेकिन यह सशक्त और समृद्ध भारत की ओर एक मजबूत कदम हैं। भारत को विकसित राष्ट्रों की दिशा में अग्रणी बनाने के लिए एआई को तकनीक और प्रशासनिक क्षेत्र से जोड़ने की घोषणा की गई है। इससे कार्यों में गुणवत्ता बढ़ेगी। इस बजट में जिन प्रमुख बातों पर जोर दिया गया है। उनमें स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना प्राथमिकता है। सिगरेट, शराब आदि की कीमतों में वृद्धि अच्छा कदम है। बहुत संभव सरकार शराब बंदी की ओर बढ़ रही हो। आशा है बजट पारित होते समय आयकर छूट की सीमा और कुछ अन्य रियायतों की घोषणा की जा सके।

विजन 2047 को केंद्रित कर बजट प्रावधान आने वाले वर्षों की रचना का रोडमैप तैयार

सुरेश शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत ही अच्छा और ठोस बजट पेश किया। बजट में लोकलुभावन वायदे नहीं, विकास का ठोस आधार दिया है। इस आम बजट की खास बात यह है कि इसमें जहां लोगों को खुश करने का प्रयास किया गया है। वहां भी लोकलुभावन वायदे नहीं किए गए। अपितु विकास का ठोस आधार दिया गया है। बंगाल और केरल में चुनाव हैं, लेकिन वहां रेल कॉरिडोर देकर लुभावन नहीं प्रभावी काम दिया गया है। यह बजट अधोसंरचना को मजबूती देने वाली योजनाओं से भरपूर है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जिन योजनाओं को बजट का हिस्सा बनाया है, उससे यातायात की सुगमता मिलेगी, जिससे हर क्षेत्र में उछाल आएगा। सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, मेडिकल हब बनाने के प्रयास, कृषि और ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण, शिक्षा के साथ रोजगार या स्वरोजगार तथा कर सरलीकरण व वित्तीय प्रबंधन पर जोर दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने किसान कल्याण, उर्वरक सब्सिडी, सिंचाई तथा दलहन में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन दिया है। रक्षा क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया गया है। विजन 2047 को केंद्रित करके बजट प्रावधान और आने वाले वर्षों की रचना का रोड़मैप तैयार है।

आम बजट में देश के इतिहास में पहली बार रक्षा के लिए इतनी बढ़ी बढ़ोतरी

एलएन शीतल
वरिष्ठ पत्रकार

वर्तमान समय में पाकिस्तान और चीन के साथ आए दिन होने वाले तनाव को देखते हुए देश के इतिहास में पहली बार रक्षा बजट में पंद्रह फीसद तक की बढ़ोतरी की गई है। यह देश की सुरक्षा के लिए बहुत अहमद कदम है। अन्य देश जिनमें बांग्लादेश और अफगानिस्ता शामिल हैं, उनको दी जाने मदद भी कंट्रोल के दायरे में रखी गई है। जिससे इन देशों में भारत की अहमियत को बल मिलेगा। रविवार को केंद्र सरकार के पेश बजट में देश की रक्षा का खास ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि रक्षा बजट में तीनों सेनाओं के लिए कुल 7.84 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। यह 2025-26 के मुकाबले करीब 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। यानी कुल 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। उन्होंने कहा कि इस बजट के दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। आज के समय में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मानव जीवन को खतरे पैदार करने वाली चीजों को महंगा किया गया है, जिससे लोग इन चीजों से बचेंगे। जबकि आयुर्वेद के आधार पर पहली बार एम्स में इलाज शुरु करने की पहल भी देश की पारंपरिक पद्धति से इलाज कराना आसान हो जाएगा। यह पहल भी देश के हित में है।

केंद्रीय बजट 2026 पर क्रेडाई भोपाल की प्रतिक्रिया...

अफोर्डेबल हाउसिंग की हिस्सेदारी 18 फीसदी से घटकर 12 फीसदी होने की आशंका

क्रेडाई भोपाल केंद्रीय बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के निरंतर फोकस का स्वागत करता है। हाईवे, मेट्रो, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, रेलवे और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, नए ग्रोथ कॉरिडोर खुलेंगे और रियल एस्टेट सेक्टर को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी। इसका सीधा सकारात्मक असर भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन पर पड़ेगा, जहां आवास, रोजगार और सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह बात क्रेडाई भोपाल अध्यक्ष, 'कमाल का भोपाल' अभियान के फांउडर मनोज मीक ने कही। मीक के अनुसार क्रेडाई बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर दिए गए जोर की भी सराहना करते हैं। क्रेडाई का मानना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग कोई वेलफेयर स्कीम नहीं, बल्कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। यदि इसकी सप्लाई कमजोर होती है, तो मेट्रोपॉलिटन रीजन में किराये बढ़ेंगे, रोज़ाना का सफर लंबा होगा और अनियोजित बस्तियों का विस्तार होगा। क्रेडाई भोपाल की अपेक्षा है कि सरकार भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए एक स्पष्ट नीति ढांचा बनाए जिसमें ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो-आधारित विकास, अफोर्डेबल हाउसिंग और कैपिटल रिडेवलपमेंट को एक साथ जोड़ा जाए ताकि राजधानी क्षेत्र का विकास समावेशी, संतुलित और टिकाऊ बन सके।

मनोज मीक
अध्यक्ष,
क्रेडाई भोपाल

वित्त विधेयक 2026 : प्रत्यक्ष कर व्यवस्था और वैश्विक निवेश का नया युग

वित्त विधेयक 2026 प्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक और दूरगामी सुधार प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना, दंडात्मक प्रावधानों को तर्कसंगत करना तथा वैश्विक व्यवसायों को भारत में अपने संचालन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पुरानी व्यवस्था में एमएटी की दर 15 फीसदी से घटाकर 14 फीसदी करने का प्रस्ताव है। ऑप्शन की बिक्री पर एसटीटी 0.1 फीसदी से बढ़ाकर 0.15फीसदी होगा, जो फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.02 फीसदी से बढ़ाकर 0.05 फीसदी होगा। बायबैक से प्राप्त राशि अब पूंजीगत लाभ के रूप में करयोग्य होगी। प्रमोटर्स पर प्रभावी कर भार लगभग 30 फीसदी होगा। इसके अलावा निर्दिष्ट भारतीय डेटा सेंटर्स से सेवाएं लेने वाली विदेशी कंपनियों को 31 मार्च 2047 तक कर छूट। कस्टम बॉन्डेड एरिया में भारतीय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को पूंजीगत वस्तुएं उपलब्ध कराने वाली विदेशी कंपनियों को वित्त वर्ष 2030-31 तक छूट। लिथियम, नियोबियम एवं पोटाश को 10 वर्ष की डिफर्ड डिडक्शन सुविधा वाले खनिजों की सूची में शामिल किया गया।

सीए अर्पित राय
अध्यक्ष,
आईसीएआई
भोपाल शाखा

प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

बजट में टियर-2 एवं टियर-3 शहरों पर विशेष फोकस से मध्यप्रदेश में उद्योग, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, स्टार्ट-अप्स और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। एमएसएमई-अनुकूल नीतियां प्रदेश के उद्यमियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाएंगी। अवसंरचना के क्षेत्र में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया है, जिससे युवाओं के लिए नए रोजगार बनेंगे। यह बजट 2026 भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करता है।

दीपक शर्मा
अध्यक्ष,
फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

युवाओं व उद्योगों पर केंद्रित

यह बजट विकसित भारत की दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए सुधारों और विनिर्माण, अवसंरचना तथा नवाचार में निवेश को जोड़ता है। युवाओं के लिए इस बजट में रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता पर विशेष जोर दिया गया है। कौशल विकास कार्यक्रमों, अप्रेंटिसशिप और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए नई घोषणाएं की गई हैं, वहीं पर्यटन और सेवाओं के विस्तार से नए रोजगार अवसर पैदा होंगे।

आरजी द्विवेदी
सलाहकार,
पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मध्यप्रदेश

रोजगार सृजन को बढ़ावा

एनआईसीआईए उद्योग जगत केंद्रीय बजट में एमएसएमई, रोजगार सृजन एवं कौशल विकास पर दिए गए सशक्त फोकस का स्वागत करता है। ऋण उपलब्धता को सुदृढ़ करने तथा सहायता तंत्र को मजबूत करने से विशेष रूप से मध्य प्रदेश में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को उल्लेखनीय प्रोत्साहन मिलेगा, जहां एमएसएमई उद्योग 4 की एक महत्वपूर्ण आधारशिला हैं।

सिद्धार्थ चतुर्वेदी
उपाध्यक्ष,
सीआईआई मध्य प्रदेश

क्षेत्रीय विकास को गति

केंद्रीय बजट 2026 विकास की महत्वाकांक्षा और वित्तीय अनुशासन का संतुलित संयोजन प्रस्तुत करते हुए उद्योग जगत को एक स्पष्ट और आश्वस्त संकेत देता है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, अवसंरचना निर्माण तथा संपर्कता पर निरंतर दिया गया बल निजी निवेश, रोजगार सृजन और देशभर में क्षेत्रीय विकास को मजबूत गति प्रदान करेगा, जिससे व्यापार सुगम बनेगा और विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

राजेंद्र पटेल
अध्यक्ष,
सीआईआई
भोपाल जोन

आर्थिक विकास पर ध्यान

केंद्रीय बजट में अवसंरचना पर बढ़े हुए व्यय, एमएसएमई एवं विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन तथा कर प्रणाली के सरलीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही, कृषि, कौशल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देकर समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने का प्रयासकिया गया है।

पंकज गोयल
अध्यक्ष,
सीआईआई
मालवा जोन

स्मार्ट सिटी के 'बी नेस्ट' के नव उद्यमियों से हरिभूमि की बातचीत

स्टार्ट-अप से जुड़े उद्यमियों ने कहा- भविष्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा आम बजट

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

भेल स्थित स्मार्ट सिटी 'बी नेस्ट' परिषर में स्टार्ट-अप सेंटर में उद्यमी गो ईजी होम केयर सर्विस के सीईओ हर्षवर्धन मिश्रा ने बजट पर हरिभूमि से चर्चा करते हुए कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाला है और डिजिटल सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि डेटा बेस सेंटर का स्वदेशी नेटवर्क विकसित होने से फ्रॉड और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा, जिससे डिजिटल ट्रांजेक्शन सिस्टम अधिक सुरक्षित बनेगा। इससे न केवल उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि स्टार्टअप्स और सर्विस सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी।

हर्षवर्धन मिश्रा ने बजट को एमएसएमई सेक्टर के लिए बेहद लाभकारी बताते हुए कहा कि छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता, तकनीकी संसाधन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे रोजगार सृजन को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल इकॉनमी, और आम नागरिक- तीनों को संतुलित रूप से लाभ देने का प्रयास दिखाई देता है। उनके अनुसार यह बजट सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव रखने वाला है। यह आम लोगों, उद्यमियों और युवा स्टार्ट अप्स-तीनों के लिए सकारात्मक और भरोसेमंद बजट है।

भेल के स्मार्ट सिटी ऑफिस में सीईओ यश वर्मा।

स्टार्ट-अप सेक्टर के लिए आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम

स्टार्ट-अप सेक्टर से जुड़े उद्यमियों ने केंद्रीय बजट को तकनीक और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला बताया है। स्मार्ट सिटी 'बी नेस्ट' के सोशल क्राफ्ट के सीईओ यश वर्मा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'हैप्पी बजट' करार दिया। यश वर्मा ने कहा कि इस बजट में सरकार ने खुद का डिजिटल और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की स्पष्ट दिशा दिखाई है, जिससे आने वाले समय में देश को तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर चिप निर्माण को बढ़ावा मिलने से अब भारत को अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जो स्टार्ट-अप और टेक इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक स्टार्ट-अप्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के लिए बाहरी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे लागत अधिक आती थी। बजट में स्वदेशी एआई सिस्टम और टेक प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिलने से स्टार्ट-अप्स को कम लागत में आधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी और इनोवेशन को गति मिलेगी। यश वर्मा के अनुसार यह बजट आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूत करता है। सरकार के खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने से स्टार्ट-अप्स को स्थायित्व, सुरक्षा और ग्रोथ-तीनों का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह बजट युवा उद्यमियों, टेक-स्टार्टअप्स और डिजिटल इंडिया के विज़न को आगे बढ़ाने वाला है और आने वाले वर्षों में रोजगार और नवाचार के नए अवसर पैदा करेगा।

आयुर्वेदिक एम्स खुलने से आयुर्वेदिक रिसर्च को मिलेगा बढ़ावाः डॉ. राकेश पाण्डेय

भोपाल। देश में तीन नए आयुर्वेदिक एम्स की स्थापना, हाई क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक्सपॉर्ट, युवाओं को कैरियर पॉथवे के लिए स्कीम, आयुर्वेदिक दवाओं के टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब्स, जामनगर में डब्लूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स व आयुष सेंटर्स, डॉयग्नोस्टिक पोस्ट केयर व रीहैब सेंटर्स बनना आदि निश्चित रूप से आयुर्वेद व आयुष की गति में विकास करेगा। परंतु जिस प्रकार से आयुर्वेद-आयुष कॉलेजों व अस्पतालों के निर्माण हो रहे हैं उस गति से सरकारी रोजगार की व्यवस्थित योजनाओं में बढ़ोतरी के साथ रोजगार की कोई घोषणा नहीं की गई है। हां नए तीन आयुर्वेदिक एम्स खुलने से आयुर्वेदिक रिसर्च को जरूर बढ़ावा मिलेगा। आयुर्वेदिक एम्स भोपाल, वाराणसी व बेंगलुरु में खोले जाएं तो बेहतर रहेगा। आयुष फार्मेसियों को अपग्रेड करना हितकारी कदम है। आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राकेश पाण्डेय ने प्रतिक्रिया देते हुए डॉयबिटीज व कैंसर दवाएं सस्ती होना लाभकारी होगा। इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापन हितकारी कदम है। इससे आयुष सेक्टर मजबूत होगा।

युवाओं को नौकरी देने वाला बजट

सभी घोषणाएं धरातल पर आती हैं तो संजीवनी साबित होगा

विजय गौर, अध्यक्ष
गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

यह भारत के विकास व उद्योगों की जरुरत को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया दूरगामी बजट है। बजट में एमएसएमई को फायदे के लिए बहुत सी घोषणाएं की गई हैं। जैसे की 10 हजार करोड़ का एसएमई ग्रोथ इक्विटी फंड बनाने की घोषणा हुई है। इसके अलावा कई अन्य घोषणाएं भी हुई हैं। अगर सभी घोषणाएं धरातल पर आती हैं तो संजीवनी साबित होगा। यह बजट युवाओं को केवल नौकरी चाहने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की सोच को दर्शाता है। सरकार ने हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने के लिये घोषणा की है वह छात्राओं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की उन छात्राओ की मददगार होगी, जिन्हें पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ता है।

बजट में रणनीतिक घोषणाएं की

10 लाख प्रति कंसाइनमेंट की लिमिट को खत्म किया

आस्था वैश्य
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
भोपाल

भारत संभावनाओं का देश रहा है। वर्तमान में वैश्विक अनिश्चितताओं की स्थिति में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई, केअर गिविंग तथा एनीमेशन एवं कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र मेंयुवा कौशल प्रशिक्षण, एनर्जी, के क्षेत्र में कई रणनीतिक घोषणाएं की गई है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम का विकास, ईस्ट में दानकुनी से सूरत तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। देश को एक मेडिकल टूरिज्म हब की रूप में विकसित करने के लिए रीजनल सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए 10 लाख प्रति कंसाइनमेंट की लिमिट को खत्म किया गया है।

विकसित भारत की दिशा में होगा महत्वपूर्ण

केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम बताया है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत ‹\@›2047 के दृष्टिकोण को नई गति देगा। बजट में समग्र राष्ट्र दृष्टिकोण और पंच प्राण के सिद्धांत को मूर्त रूप दिया गया है। बजट का उद्देश्य समग्र और सर्वस्पर्शी विकास को सुनिश्चित करना है।

राजेन्द्र शुक्ल
उप मुख्यमंत्री

बेटियों से लेकर शहरों तक विकास की सौगात

केंद्रीय बजट में मप्र को मिली सौगातें राज्य के शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, शहरी विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेंगी। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल निर्माण की घोषणा से विशेषकर जनजातीय और ग्रामीण अंचलों की छात्राओं को सुरक्षित आवास मिलेगा, जिससे वे बिना किसी बाधा के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। यह निर्णय बेटियों के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

गोविंद सिंह राजपूत
खाद्य मंत्री

जनता को समर्पित और विकासोन्मुख बजट

केंद्रीय बजट जनता को समर्पित, विकासोन्मुख और समावेशी है। यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग, सभी को राहत देने वाला है। बजट में मध्यप्रदेश को मिली सौगातें रोजगार के नए द्वार खोलेंगी। शहरों के विकास के लिए किए गए बजट प्रावधान से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन जैसे शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा।

प्रद्युम्न सिंह तोमर
ऊर्जा मंत्री

भारत 2047 में कैसा होगा या होना चाहिए पर फोकस

आज का बजट को मैं एक भारत सरकार का विजन डॉक्यूमेंट के रूप में देख रहा हूं, जिसमे भारत 2047 में कैसा होगा या होना चाहिए इस पर फोकस किया गया। वित्त मंत्री ने भारत के नागरिकों को बजट केवल स्वयं के परिपेक्ष में देखने की जगह भारत कैसा भविष्य में हो यह समझाने की कोशिश की हैं। समग्र विकसित भारत में आप क्या आहुति दे सकते हैं।

मनोज मोदी
सह अध्यक्ष,
पीएचडीसीसी आई (मध्य प्रदेश), भोपाल

एकीकृत अवसंरचना पर निरंतर एवं सशक्त फोकस

सीआईआई केंद्रीय बजट 2026 का स्वागत करता है, जिसमें लॉजिस्टिक्स दक्षता और एकीकृत अवसंरचना पर निरंतर एवं सशक्त फोकस देखने को मिलता है। आर्थिक विकास का विकेंद्रीकरण संभव होगा। रसायन क्षेत्र के लिए 1.62 लाख करोड़ का आवंटन आयात पर निर्भरता कम करने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

अनिमेष जैन
पूर्व अध्यक्ष,
सीआईआई
मध्य प्रदेश

एक्सपर्ट की राय

एमएसएमई को शक्ति देने वाला बजट, बड़े उद्योगों के माध्यम से विकसित होगा भारत

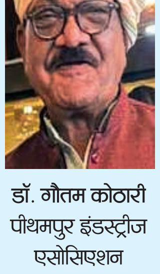

डॉ. गौतम कोठारी
पीथमपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
अध्यक्ष

बड़े उद्योगों को 'गति' और एमएसएमई को 'शक्ति' देने वाला यह बजट भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को वैश्विक सप्लाई चेन का अनिवार्य हिस्सा बनाने की मंशा रखता है। यह बजट एमएसएमई को सशक्त बनाकर ग्रासरूट स्तर पर विकास सुनिश्चित करता है, जबकि बड़े उद्योगों को इनोवेशन और स्केलिंग के अवसर देता है। औद्योगिक अधोसंरचना का मजबूत फोकस दोनों को जोड़ता है, जो लंबे समय में रोजगार, निर्यात और जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा देगा। हालांकि, कार्यान्वयन की चुनौतियां रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर यह भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। एमएसएमई के लिए यह बजट सर्वाइवल से स्केलिंग की ओर एक बड़ा कदम है। 10,000 करोड़ के नए विकास कोष की घोषणा छोटे उद्यमों को इक्विटी सहायता प्रदान करेगी, जिससे उन्हें चैंपियन' बनने में मदद मिलेगी।

दूरगामी रणनीति के तहत बजट को तैयार किया, स्वागत योग्य है

राजीव अग्रवाल
अध्यक्ष, मंडीदीप इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

दूरगामी रणनीति के तहत बजट को तैयार किया गया है। बजट स्वागत योग्य है, लेकिन बहुत सी अपेक्षाएं थी, जैसे की इनकम टैक्स में छूट व एमएसएमई के लिए स्पेशल छूट की घोषणा की उम्मीद थी, जो की नहीं हुई। इंपोर्ट व एक्सपोर्ट की सहूलियत को बढ़ाया है। हमारा आठ देशों के साथ एफडीए हुआ है। इससे विदेश व्यापार बढ़ेगा। विदेश व्यापार की बाधाओं को बजट में खत्म करने का प्रयास किया गया है। कच्चा माल मंगाने में छूट दी गई है। टूरिज्म पर फोकस है। मैं मानता हूं कि साल दो साल में इकोनामी में सकारात्मक असर पड़ेगा। एमएमएसई की तकनीक को अपग्रेड करने के लिए अलग से प्रावधान लाना चाहिए था।

अब नए नियमों के अनुसार पैन बेस्ड टैक्स डिडक्शन संभव होगा

एमएसएमई जो कि देश के कुल औद्योगिक क्षेत्र का 99 फीसदी प्रतिनिधित्व करती हैं के 2000 इंडस्ट्री क्लस्टर्स एवं छोटे उद्योग सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए 10 हजार करोड़ के एमएसएमई ग्रोथ फंड का प्रावधान किया गया है, जो कि भारतीय उद्योगों को मजबूत करने की दिशा में सराहनीय कदम है। इससे भारतीय उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना मजबूत स्थान बनाएंगे आयकर में मिसरिपोर्टिंग ऑफ इनकम में जहां पहले 200 फीसदी पेनॉल्टी लगती थी, जिसको अब 100 फीसदी पेनॉल्टी पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है। यह स्वागत योग्य कदम है। इससे सर्च एवं सर्वे के केसेस में बड़ी राहत मिलेगी। आयकर रिटर्न नॉन बिजनेस टैक्स पेयर के लिए दाखिल किए जाने वाले ईटीआर फॉर्म 1 एवं 2 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तथा नॉन ऑडिट बिजनेस एवं ट्रस्ट के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त नियत की गई है। इससे करदाताओं एवं टैक्स प्रोफेशनल्स को आईटीआर दाखिल करने की अलग-अलग दिनांक होने से सुविधा होगी। अब नए नियमों के अनुसार पैन बेस्ड टैक्स डिडक्शन संभव होगा।

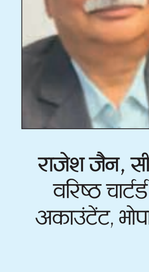

राजेश जैन, सीए
वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट, भोपाल

रोजगार सृजन के साथ वित्तीय समावेशन दोनों में तेजी वाला बजट

केंद्रीय बजट 2026-27 युवा शक्ति को भारत की विकास गाथा के केंद्र में रखता है, जिसमें गरीबों, वंचितों और पिछड़े लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने का एक मजबूत संकल्प है। जैसे-जैसे अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक युवा भारतीय वर्कफोर्स में शामिल होंगे, वैसे ही सपोर्टेड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से स्थायी आजीविका बनाने का एक समानांतर अवसर भी मिलेगा। युवाओं को स्किल, फॉर्मल फॉलिनेंशियल प्रोडक्ट्स तक पहुंच और स्थानीय रूप से प्रासंगिक आय के अवसरों के साथ सशक्त बनाने से रोजगार सृजन और वित्तीय समावेशन दोनों में तेजी आएगी।

माही भजनी, सामाजिक कार्यकर्ता

महिला, छात्र, किसान सभी के हित का रखा ध्यान

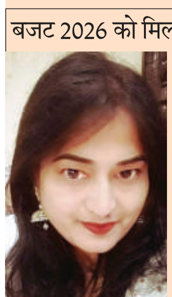

बजट 2026 को मिला-जुला बताया है, जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए लाभ हैं। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का बजट आवंटन, महिलाओं के लिए फायदेमंद हैं। किसानों के लिए की गई घोषणाएं जैसे नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसी फसलों को बढ़ावा देना, सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं महिलाओं के लिए गैस के दामों में कमी और किचन उपकरणों की खरीद पर टैक्स छूट भी बढ़िया है। इस बजट से रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा ऋण पर ब्याज दर कम करना भी हर क्षेत्र के लिए फायदे का सौदा है। कुल मिलाकर बजट में महिला, छात्र, किसान सभी का हित शामिल है।

अंशु गुप्ता, अध्यक्ष, मध्य-प्रदेश महिला उद्यमी संघ

कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना से एनीमेशन, गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा

स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास और रोजगार देने वाला बजट है, इसमें दस हजार करोड़ के बायो फार्मा हब विकसित करना, भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की महत्वपूर्ण योजना शामिल करना, जिसका लाभ भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों को मिलेगा। मेडिकल केयर टेकर प्रशिक्षण योजना से युवाओं के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। भारत के छोटे शहरों की विकास योजना से मप्र के कई शहरों को आधुनिक होने का अवसर मिलेगा। मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना से एनीमेशन और गेमिंग क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।

विभांशु जोशी, पूर्व सदस्य, मध्यप्रदेश बाल आयोग

खर्च भी बढ़ेगा, विकास भी होगा और अनुशासन भी बना रहेगा

केंद्रीय बजट 2026 पूरी तरह से विकास पर फोकस्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार सरकार की स्पष्ट प्राथमिकता में हैं। वित्त मंत्री ने बजट में साफ कर दिया है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना सरकार का पहला एजेंडा है। यह बजट संदेश देता है—खर्च भी बढ़ेगा, विकास भी होगा और अनुशासन भी बना रहेगा। बजट 2026 में मध्यम वर्ग और एमएसएमई को राहत, वहीं इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बूस्ट दिया गया है। सरकार ने इस बजट के जरिए निवेशकों को भरोसा और बाजार को स्थिरता का स्पष्ट संकेत दिया है। यह बजट रुकने का नहीं, दौड़ने का बजट है—रोजगार, विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में।

हर्ष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्थिक सलाहकार, भोपाल

विकास और राजकोषीय अनुशासन साथ-साथ चलेंगे

केंद्रीय बजट 2026 सरकार के विकास आधारित केंद्रित एजेंडे को पूरी मजबूती के साथ सामने लाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ संदेश दिया है कि सरकार का फोकस अब केवल घोषणाओं पर नहीं, बल्कि तेज क्रियान्वयन और ठोस परिणामों पर है। मध्यम वर्ग के लिए राहत और निवेशकों के लिए भरोसे का संदेश देते हुए यह बजट यह भी स्पष्ट करता है कि विकास और राजकोषीय अनुशासन साथ-साथ चलेंगे। कुल मिलाकर, बजट 2026 रुकने का नहीं, बल्कि तेजी से आगे बढ़ने का बजट है।

सुचिता गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्थिक सलाहकार, भोपाल

स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर, एवीजीसी लैब कार्यक्रम प्रगतिशील कदम

स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर और एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) लैब कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव एक प्रगतिशील कदम है, जो यह दर्शाता है कि डिजिटल कंटेंट अब बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को कितनी गहराई से प्रभावित कर रहा है। एनीमेशन, गेमिंग और विजुअल स्टोरीटेलिंग से संरचित परिचय न केवल रचनात्मकता को बढ़ावा देगा, बल्कि एकाग्रता, सहयोग और स्क्रीन के सजग उपयोग जैसे आवश्यक कौशल भी विकसित करेगा। ये भविष्य के लिए तैयार करने वाली क्षमताएं हैं, जो बच्चों की पूरी शैक्षणिक यात्रा में सहायक होंगी और उभरते रचनात्मक करियर के लिए नए अवसर खोलेंगी।

डॉ. पल्लवी राव सी. चतुर्वेदी, फाउंडर, गेट सेट पैरेंट, कार्यकारी उपाध्यक्ष आइसेक्ट समूह

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल से ग्रामोद्योगों के होने के साथ महिलाओं को मिलेगा मार्केट

बजट में महिलाओं के लिए शी मार्ट प्लेटफार्म बनाने की घोषणा और देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की घोषणा एक सकारात्मक कोशिश है, लेकिन सीधे महिला केंद्रित सामाजिक सुरक्षा या जीवन सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिखता। बजट में रील बनाने, कंटेट क्रियेशन जैसी डिजीटल तकनीक से शिक्षित करने की बात तो अच्छी है, लेकिन महिला स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए स्पष्ट प्रावधानों होना चाहिए थे। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं, जैसे-सामर्थ्य, मिशन शक्ति और पीएम मातृत्व वंदना योजना में वृद्धि बहुत ही प्रतीकात्मक है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का कदम गांव और ग्रामोद्योगों के सशक्तिकरण के साथ खादी, हथकरघा और हस्त शिल्प के कार्यों और बाजार को मजबूती मिलेगी।

कुमुद सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, भोपाल

बजट को लेकर शहर के बाजार विशेषज्ञों ने किया परिचर्चा का आयोजन

केंद्रीय बजट दूरदर्शी, व्यावहारिक एवं विकासोन्मुखः सीआईआई

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) मध्य प्रदेश ने केंद्रीय बजट के लाइव प्रसारण एवं बजट उपरांत विश्लेषण सत्र का आयोजन किया, जिसमें उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, पेशेवरों एवं मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सत्र की अध्यक्षता सिद्धार्थ चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष, सीआईआई मध्य प्रदेश ने की। कार्यक्रम में अनिमेष जैन, पूर्व अध्यक्ष, सीआईआई मध्य प्रदेश राजीव अंगरा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वर्धमान ग्रुप आदित्य मोदी, काउंसिल सदस्य,सीआईआइ भोपाल जोनल काउंसिलः जयवर्धन जोशी, सीआईआई यंग इंडियंस प्रतिनिधि तथा सीए सतपाल सिंह खनूजा सहित उद्योग जगत एवं मीडिया के अनेक प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता रही।

पारंपरिक क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से समर्थन करता है बजट

केंद्रीय बजट स्पष्ट रूप से पारंपरिक क्षेत्रों का समर्थन करता है, साथ ही पूंजी को अगली पीढ़ी के उद्योगों की ओर निर्देशित करता है, जिसमें सेवा क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है। कुल मिलाकर, ये उपाय ऐसे बजट को रेखांकित करते हैं जो रोजगार-समर्थक है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक और उभरते दोनों क्षेत्रों में स्थायी रोजगार सृजित करना है।

वीर एस आडवाणी उपाध्यक्ष, सीआईआई पश्चिमी क्षेत्र, अध्यक्ष एवं एमडी ब्लू स्टार

केंद्रीय बजट स्पष्ट रूप से दिशात्मक और दूरदर्शी

केंद्रीय बजट दिशात्मक और दूरदर्शी है। विभिन्न क्षेत्रों में सूक्ष्म स्तर पर किए गए कार्य का विवरण सुविचारित नीतिगत इरादे को दर्शाता है, जबकि एआई और सेमीकंडक्टर पर जोर आर्थिक परिवर्तन के अगले चरण के लिए तत्परता का संकेत देता है। कुल मिलाकर, बजट 'विकसित भारत' की दीर्घकालिक दृष्टि के अनुरूप है।

ऋषि कुमार बागला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीजी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स

बजट को लेकर क्या कहते हैं युवा

रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे लड़कियां पा सकेंगी उच्च शिक्षा

इस बजट में अच्छी बात यह है कि इसमें रेलवे, डिफेंस और हेल्थ सेक्टर में कैंसर, शुगर समेत मेजर दवाइयों पर राहत मिली है। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में कोई राहत नहीं है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से बजट में कुछ खास नहीं है। इस बजट से उम्मीद थीं कि महंगाई का कंट्रोल करने के लिए कुछ नया कदम उठाएगी। बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, साथ ही ट्रांसपोर्ट सस्ता होना चाहिए था। इस बजट में युथ सेगमेंट में ज्यादा कुछ नहीं मिला है। बस थोड़ी राहत मिली है रोज़गार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। लड़कियां उच्च शिक्षा और रोजगार पा सकेंगी।

राधेश्याम अहीरे, स्टूडेंट, यूपीएससी

गर्ल्स हॉस्टल बनने से लड़कियां उच्च शिक्षा, रोजगार पा सकेंगी

बजट 2026 में थोड़े बहुत ही बदलाव हैं। जैसे एमएसएमई सेक्टर को अधिक बढ़ावा मिला, खेलकूद की वस्तुएं वो सस्ती की गईं। शुगर और कैंसर की दवाई सस्ती हो गई। इससे जनता को थोड़ी राहत है। बजट से उम्मीद थी जायदा से ज्यादा सीधी नौकरियां भर्ती की जाएंगी, रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, शिक्षा क्षेत्र को ज्यादा प्रोग्रेस किया जाएगा। पेट्रोल, डीजल, गैस सस्ती हो जाएगी। यूथ सेगमेंट को ज्यादा कुछ नहीं मिला, बस थोड़ी सी राहत दी गई कि रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने से जायदा से जायदा लड़कियां उच्च शिक्षा ओर रोजगार पा सकेंगी। ये कदम युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा करियर के अवसर प्रदान बढ़ाने की तरफ़ है।

अंतिमा सिंह, एमए इकोनॉमिक्स

बजट बेहतर शिक्षा, करियर के अवसर प्रदान करने की तरफ़

महंगाई और खर्चों में राहत, तकनीकी और डिजिटल कौशल में निवेश बजट में युवाओं के लिए प्रावधान होना चाहिए। यूथ सेगमेंट को ज्यादा कुछ नहीं मिला, बस थोड़ी सी राहत दी गई कि रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने से ज्यादा से ज्यादा लड़कियां उच्च शिक्षा ओर रोजगार पा सकेंगी। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का यह कदम युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा करियर के अवसर प्रदान बढ़ाने की तरफ़ है। युवाओं के लिए सबसे जरूरी स्टार्टअप और छोटे बिजनेस सच में आसान हों, परीक्षा और कॉम्पटीशन में सुधार होना चाहिए था। इसके साथ ही युवाओं की यह भी इच्छा है कि सभी नौकरियों का समय पर कैलेंडर आए, समय पर परीक्षाएं हो और परिणाम समय पर आएं। सभी एग्जाम के पारदर्शिता होनी चाहिए सभी क्षेत्रों में पर्याप्त नौकरियां निकलें।

रूपा शिंदे, छात्रा

नौकरी और स्किल डेवलपमेंट के साथ उच्च तकनीक और शोध क्षेत्र का ध्यान रखा

बजट में नौकरी और स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा, रोजगार, नई तकनीक और क्रिएटिविटी सेक्टर को प्रोत्साहन, उच्च तकनीक और शोध क्षेत्र का धयान रखा गया है। अच्छी नौकरी और रोजगार के नए अवसर, शिक्षा से नौकरी, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और छोटे बिजनेस आसान होंगे। डिजिटल और क्रिएटिव करियर के लिए बड़े अवसर होने चाहिए थे। कॉन्टेक्ट क्रेटर लैब्स नए कौशल सीखने भविष्य की तैयारी टेक्निकल और सर्विस सेक्टर के कार्यक्रम पर फोकस रहा।

पंकज खरे, स्टूडेंट, यूपीएससी

बजट को लेकर क्या कहती हैं महिला नेत्रियां

छात्रावास और शी-मार्ट से महिला आत्मनिर्भरता को मिलेगा बल

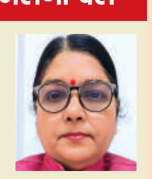

इस बजट में तीन उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है प्रोग्रेसिविटी, प्रतिस्पर्धा और आकांक्षा जहां बजट में प्रोग्रेसिविटी और प्रतिस्पर्धा दोनों को बढ़ाने जैसी सौगात है इन दोनों में तेजी आएगी तो वहीं जन सामान्य की आकांक्षा को भी पूरा करना सरकार का उद्देश्य है। नए कॉरिडोरसे दूसरे देशों के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, हमारा विकास होगा। टेक्सटाइल पार्क, कैंसर दवा सस्ती होना और नए अस्पताल खोलना उम्दा कदम है। वहीं हर जिले में छात्रावास बेटियों की शिक्षा के लिए उठाया गया उम्दा कदम है तो शी-मार्ट खुलने से महिलाओं को मार्केट मिलेगा और जिससे वंचित महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी।

राजो मालवीय, प्रदेश मंत्री, भाजपा

महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्गों के लिए समावेशी दृष्टिकोण

यह बजट महिलाओं, बच्चों, किशोरियों और वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। बजट महिला सशक्तिकरण, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देना सरकार की संवेदनशील एवं दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। आंगनवाड़ी, पोषण अभियान, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा बाल संरक्षण से जुड़ी पहलों को मजबूती मिलने से सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इससे न केवल महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव भी मजबूत होगी। यह बजट 'सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास' के संकल्प को साकार करेगा।

निर्मला भूरिया, मंत्री, महिला एवं बाल विकास

उद्योगपतियों के लिए राहत, तो जनता के लिए निराशा

यह बजट चुनावी जुमलों की पोल खोलने वाला दस्तावेज है। केंद्र सरकार ने जानबूझकर मध्यप्रदेश की अनदेखी की है, क्योंकि यहां की जनता ने भाजपा की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। यह बजट उद्योगपतियों और चंद खास वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है, जबकि किसान कर्ज, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है। महिलाओं और युवाओं के लिए केवल घोषणाएं हैं, जमीन पर उतारने की कोई मंशा नहीं दिखती। यह बजट आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है, जो मप्र की जनता के हितों के साथ खुला अन्याय है। इसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासी, दलित, ओबीसी और सर्व समाज के लिए ठोस दृष्टि का अभाव है। यह बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह विफल रहा है।

संगीता शर्मा, प्रवक्ता, मप्र कांग्रेस

विकसित भारत की दिशा में बढ़ते कदम

केंद्रीय आम बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समृद्ध भारत के विजन को परिलक्षित करने वाला है। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति में बढ़ता हुआ कदम है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और सूक्ष्म - लघु उद्योग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। खेती में एआई का प्रयोग बढ़ाया जाएगा।

नारायण सिंह कुशवाह
मंत्री, सामाजिक न्याय दिव्यांग जन कल्याण खाद्य एवं प्रसंस्करण

पूरा जोर उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने पर

बजट अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। पूरा जोर उत्पादन बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने पर है। कारीडोर निर्माण, छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास हेतु दो, दस हजार करोड़ के प्रावधान, हाई स्पीड रेल कारीडोर नए विकसित भारत की तस्वीर गढ़ेंगे।

गोकुल सोनी
सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी एवं साहित्यकार

टैक्स से सरकार की आय में वृद्धि होगी...

आम करदाताओं को अब इनकम टैक्स छिपाने या गड़बड़ी मिलने पर जेल की सजा नहीं होगी, बल्कि सिर्फ 30% जुर्माना भरकर मामला निपटाया जा सकेगा। यानि अपराध करो, जुर्माना भरो, केस बंद। इससे अपराध कम होने के बजाय और बढ़ेंगे। हालांकि सरकार की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।

एमके सक्सेना
पूर्व संयोजक राजपत्रित कर्मचारी संघ

व्यापारियों के लिए भरोसे और सुविधा का बजट

बजट का प्रमुख फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सस्ता और सुलभ ऋण, तथा व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर रहा है। इन्फ्रा व लॉजिस्टिक्स पर निवेश बढ़ाने से लागत कम होने की उम्मीद है। इससे छोटे, मध्यम व्यापारियों का भरोसा मजबूत होगा। रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

विवेक साहू
अध्यक्ष किराना संघ भोपाल

बजट में हो 8वें वेतन आयोग का प्रावधान

मप्र कर्मचारी मंच ने पीएम एवं वित्त मंत्री को पत्र लिखकर केंद्रीय बजट में संशोधन कर 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की है। भारत सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने की सिफारिश लागू करने का निर्णय लिया है, लेकिन बजट 2026 में आठवां वेतन आयोग लागू करने के वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया।

अशोक पांडे
प्रदेशाध्यक्ष, मप्र कर्मचारी मंच

शिक्षा, उद्यमिता में संबंध स्थापित करता बजट

यह बजट सभी के लिए फायदेमंद है, जिसमें जहां एक ओर महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं शिक्षा, उद्यमिता और सामाजिक आत्मविश्वास के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने वाला बजट साबित होगा। कुल मिलाकर इस बजट में उपयोगी आयटम्स के दामों पर नियंत्रण रखना सरकार की उम्दा पहल है।

ऐश्वर्या खरे
टीवी अदाकार

फिल्मी हस्तियों के श्रीमुख से...

हर उम्मीदों पर खरा उतरने वाला, हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाया बजट

रजा मुराद
फिल्म अभिनेता

यह बजट उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने वाला बजट है, जिसमें मुख्य रूप से कैंसर के इलाज की दवाइयों को सस्ता करना लाखों कैंसर पैशेंट्स को राहत देने वाली बात है, वहीं सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी पर थी कस्टम ड्यूटी कम करने से जहां आम लोगों को फायदा होगा तो वहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बढ़िया कदम है। इसके अलावा एमएसएमई, रोजगार सृजन, कौशल विकास की बातों से लगता है सरकार ने हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया है, जिसका फायदा हर तबके को मिलेगा। यह बजट संदेश देता है—खर्च भी बढ़ेगा, विकास भी होगा और अनुशासन भी बना रहेगा। मेडिकल केयर टेकर प्रशिक्षण योजना से युवाओं के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ हो, शिक्षा हो, सरकार ने ईमानदारी से हर एक विषय पर ध्यान दिया है।

युवाओं के लिए इंटरटेनमेंट के साथ साथ रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे

रूमी जाफरी
लेखक व निर्देशक

इस बजट में रील बनाने, कंटेट क्रियेशन पर जोर देना बेहद ही उम्दा कदम है, इससे युवाओं के लिए इंटरटेनमेंट के साथ-साथ रोजगार का भी जरिया बढ़ेगा। कैंसर और डायबिटीज की दवा सस्ती करना और तीन नए अस्पताल खोलना भी स्वास्थ्य की दिशा में सरकार की चिंता को दर्शाता है क्योंकि हर घर में आपको डायबिटिक मरीज मिल ही जाएगा, इसके साथ टेक्सटाइल पार्क बनाना, शी-मीर्ट बनाना, हर जिले में छात्रावास का प्रावधान महिलाओं को शिक्षित करने के साथ आत्मनिर्भर बनाने वाला कदम है। कुल मिलाकर इस बजट में सरकार ने हर एक तबके, हर एक वर्ग का ध्यान रखा है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का कदम गांव और ग्रामोद्योगों के सशक्तिकरण के साथ खादी, हथकरघा और हस्त शिल्प के कार्यों और बाजार को मजबूती मिलेगी। वहीं इन्हें बाजार भी आसानी से उपलब्ध हो सकेगा, जिससे इनकी आय के साधन बढ़ेंगे और इनकी आर्थिक उन्नाति भी होगी।

मतदान में एक हजार 917 सदस्यों ने किया मताधिकार का उपयोग

चैंबर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष और कार्यकारणी के चुनाव के लिए हुई रिकॉर्ड वोटिंग, मतपेटियों में बंद प्रत्याशियों का भविष्य

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

राजधानी भोपाल के व्यापारियों की शीर्ष और प्रतिष्ठित संस्था चेंबर ऑफ कॉमर्स में नए अध्यक्ष गोयल या पाली में से कौन होगा। इसका फैसला मतपेटियों में बंद हो गया। सोमवार को मतगणना के बाद में अध्यक्ष और नवीन कार्यकारणी की घोषणा की जाएगी घोषणा हो जाएगी।

मानस भवन में सुबह से ही व्यापारी मतदाताओं का पहुंचना हो गया था। उल्लेखनीय हे भोपाल के चैंबर में मतदाता सदस्य दो हजार 236 है। चुनावी सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार लगना शुरू हो गई। उन्नति पैनल और प्रगतिशील पैनल दोनों पक्षों के लोग अपने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में नारे भी लगा रहे थे।

चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव का दृश्य क्रमांक-1

चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव का दृश्य क्रमांक-2

एक हजार 917 मतदाताओं ने किया अपने मत का प्रयोग

मुख्य चुनाव अधिकारी पीसी कोठारी एडवोकेट ने बताया कि एक हजार 917 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। साथ ही 39 टेंडर वोट और 50 पोस्टल वोट, पहली बार टेंडर वोटिंग के साथ मत पत्र में प्रत्याशियों के चित्र भी थे, निष्पक्ष और सफल मतदान के लिए चुनाव अधिकारी कोठारी के साथ 170 लोगों की टीम पूरी तरह मुस्तैद थी सुविधा और समय की बचत के लिए 20 मतदान केंद्र बनाए गए थे।

खबर संक्षेप

विदाई समारोहः छात्रों ने दीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

भोपाल। शांति सरोवर हाई स्कूल, सतनामी नगर सोनागिरी में सत्र 2024-25 के प्रतिभाशाली छात्रों के सम्मान एवं सत्र 2025-26 के बोर्ड विद्यार्थियों की विदाई का समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की संस्थापिका स्वर्गीय शांति देवी तिवारी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की पूजा-अर्चना से हुआ। मुख्य अतिथि डायरेक्टर व प्रोड्यूसर मंजू गौतम ने कहा कि विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन और संस्कारों की प्रशंसा की तथा छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर ज्ञानदेव मिश्र, आशीष तिवारी, सुदीप जैसवाल एवं महेंद्र मिश्र मौजूद थे। छात्रों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया।

हाट बाजार में पानी सप्लाई के लिए बिछेगी पाइप लाइन

भोपाल। शहर के टीटी नगर स्थित स्मार्ट सिटी के हाट बाजार में पानी सप्लाई के लिए नगर निगम पाइप लाइन बिछाएगा। इससे बाजार में पानी सप्लाई की जा सकेगी। इस काम पर करीब एक करोड रुपए खर्च होंगे। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के अनुसार नगर निगम पाइप द्वारा पानी लाइन बिछाने का काम किया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी किए गए हैं।

निपानिया जाट में संत शिरोमणि के 649वें जन्मोत्सव पर आयोजित किए गए विशेष कार्यक्रम

राजधानी में रही संत रविदास जयंती की धूम, कहीं भंडारे तो कहीं विवाह सम्मेलन

अमृतवाणी का पाठ कराया गया

अमृतवाणी का पाठ करते राधेकृष्ण दास महाराज।

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

संत शिरोमणि गुरू रविदास की जयंती शहर भर में धूमधाम से मनाई गई। इसी के तहत भोपाल के निपानिया जाट में संत शिरोमणि गुरु रविदास के 649वें जन्मोत्सव पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष माधव सिंह ने बताया कि इस मौके पर पटेल मुन्नीलाल जाट, पूर्व सरपंच गजराज सिंह जाट एवं सरपंच हिम्मत सिंह जाट विशेष रूप से मौजूद थे। समाज के गुरु श्री राधे कृष्ण दास महाराज द्वारा अमृतवाणी का पाठ कराया गया।

जयंती पर हुआ भंडारा

संत रविदास जयंती पर बरखेड़ा पठानी में महाआरती व पूजा-अर्चना की। इस मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया।

संत रविदास जयंती पर सेवा भारती द्वारा लगाए प्रशिक्षण

संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के पावन अवसर पर सेवा भारती भोपाल विभाग द्वारा समस्त सेवा बस्ती समितियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम करोद स्थित एक मॉल में आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं संत रविदास जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

माघ पूर्णिमा पर दान-पुण्य, मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग....

भोपाल। माघ पूर्णिमा पर रविवार को सुबह शीतलदास की बगिया, खटलापुरा व काली मंदिर आदि घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान के साथ दान-पुण्य किया। लोगों ने मंदिरों में जाकर देव दर्शन किए। कई स्थानों पर भगवान विष्णु की पूजा और सत्यनारायण कथा के आयोजन भी किए गए। लक्ष्मीनारायण (बिड़ला) मंदिर, गुफा मंदिर, नेवरी मंदिर, गिन्नौरी मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मां चामुंडा दरबार के पुजारी गुरूजी पंडित रामजीवन दुबे ने बताया कि माघी पूर्णिमा के दौरान कई लोगों ने बड़े तलाब सहित नर्मदापुराम नर्मदा नदी के घाटों पर पहुंचकर स्नान, दान किया। तो वहीं माघी पूर्णिमा अनेक स्थानों पर होली का डांडा स्थापित किया गया। सत्यनारायण की कथा कराई गई माघ पूर्णिमा के अवसर श्रद्धालुओं ने व्रत रखा,तो कई लोगों ने घरों पर मंदिर में पहुंचकर सत्यनारायण की कथा कराई, घर परिवार की सुख शांति व समृद्धि की भगवान सत्यनारायण से कामना की।

होली डांडा रोपण के साथ धमार होली प्रारंभ

माघ पूर्णिमा के साथ श्रीजी मंदिर में प्रभु श्रीनाथजी को सफेद चाकदार बागा के साथ सिर पर मोर पंख और सोने के आभूषण से श्रृंगार किया गया। मंदिर के मुखिया श्रीकांत शर्मा ने बताया कि होली डांडा रोपण से पुष्टिमार्ग में होली में वृद्धि हो जाती है। रविवार को चंदन चोवा अबीर लाल एवं पीली गुलाल से होली खिलाई गई और पिचकारी से रंग उड़ाया गया । संध्या काल में प्रभु श्रीनाथजी की गौशाला में होली के डंडे की स्थापना की गई । जिसमें कुमकुम तिलक कर गुलाल से होली की डंडे की पूजन कर बूंदी का भोग लगाया।

ट्रैक-गाड़ियों की संरक्षा गुणवत्ता होगी सुदृढ़

अनुरक्षण कार्यों के अंतर्गत भोपाल मंडल में तीव्र गति से निष्पादित हो रहे रेलवे ट्रैक

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

भोपाल मंडल में मल्टी-ट्रैकिंग एवं अधोसंरचना विकास कार्यों के साथ-साथ अनुरक्षण गतिविधियों के अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर विभिन्न नवीनीकरण कार्य तीव्र गति से निष्पादित किए जा रहे हैं। मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी के मार्गदर्शन में इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों से ट्रैक अनुरक्षण से जुड़े संरक्षा-आधारित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। भोपाल मंडल में ट्रैक नवीनीकरण के अंतर्गत कम्पलीट ट्रैक रिन्यूअल (सी.टी.आर.), थ्रू रेल रिन्यूअल (टी.आर.आर.), थ्रू स्लीपर रिन्यूअल (टी.एस.आर.), थ्रू टर्नआउट रिन्यूअल (टी.टी.आर.) तथा डीप स्क्रीनिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य सम्मिलित हैं, जिन्हें आवश्यक ट्रैफिक ब्लॉक लेकर उच्च संरक्षा मानकों के अनुरूप निष्पादित किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के नौ माह (अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025) के दौरान भोपाल मंडल में अनुरक्षण कार्यों के अंतर्गत 100.741 ट्रैक किलोमीटर में कम्पलीट ट्रैक रिन्यूअल (सी.टी.आर.), 121.23 ट्रैक किलोमीटर में थ्रू रेल रिन्यूअल (टी.आर.आर.), 80.245 ट्रैक किलोमीटर में थ्रू स्लीपर रिन्यूअल (टी.एस.आर.) तथा 80.250 समतुल्य यूनिट्स में थ्रू टर्नआउट रिन्यूअल (टी.टी.आर.) का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त 55 टर्नआउट्स में डीप स्क्रीनिंग एवं 168.391 ट्रैक किलोमीटर में प्लेन ट्रैक की डीप स्क्रीनिंग का कार्य भी निष्पादित किया गया है।

भोपाल में आज कुछ जगह पड़ेंगी बौछारें

जनवरी-फरवरी का सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा रविवार

कुछ जिलों में शाम को अचानक बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ गिरे ओले

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

राजधानी में रविवार को फरवरी के पहले दिन जनवरी और फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा। दिन का पारा लगातार ढाई डिग्री बढ़कर 29.2 डिग्री रहा, जबकि इससे पहले जनवरी में अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक पहुंचा है। बादलों के असर से शहर में रात के तापमान में भी लगातार दूसरे दिन बढ़त रही। पारा 3 डिग्री बढ़कर 15 डिग्री पर रहा। दिन-रात का पारा नॉर्मल से 3 से 3.5 डिग्री तक अधिक है। मौसम केंद्र के अनुसार राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना आदि जिलों में सोमवार तक बारिश होगी। मौसम विशेषज्ञ एके शुक्ला के अनुसार हरियाणा और राजस्थान के ऊपर एक सकुर्लेशन है। साथ ही यहां से एक ट्रफ गुजरात तक बनी हुई है। इससे मप्र में मौसम बदला हुआ है। यह क्रम दो दिन रहेगा।

यहां बारिश के साथ ओले गिरे

दोपहर बाद ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना सहित कुछ जिलों में बारिश हुई, जबकि मंदसौर, नीमच में कुछ जगह ओले गिरे। मौसम केंद्र ने सोमवार को अशोकनगर, शिवपुरी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी आदि जिलों में कुछ जगह बौछारें पड़ेंगी, जबकि अधिकांश जगह घने से मध्यम कोहरा रहेगा।

सिस्टम के कारण मध्य हिस्से में नमी बढ़ी

विशेषज्ञ शुक्ला के अनुसार प्रदेश के आसपास सक्रिय सिस्टम के कारण मध्य हिस्से में नमी बढ़ी है। इससे भोपाल सहित कुछ जगह बादल और कुछ जगह हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है।

इलाज कराकर लौट रही थी मासूम बच्ची

कार की टक्कर से 6 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

ईटखेड़ी थाना क्षेत्र स्थित परेवाखेड़ा के पास बायपास पर शनिवार रात तेज रफ्तार कार ने छह साल की बच्ची को चपेट में ले ले लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कार का चालक ही बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ग्राम परेवाखेड़ा पतलोन निवासी इकबाल अली प्राइवेट काम करते हैं। तीन-चार दिन से उनकी छह साल की बेटी आसिया अली वायरल फीवर से पीड़ति थी। शनिवार रात करीब नौ बजे इकबाल अली बेटी को इलाज के लिए बायपास स्थित एक क्लीनिक पर लेकर गए थे। क्लीनिक में डॉक्टर ने जांच के बाद कुछ दवाएं दी थीं। इकबाल अपनी बेटी आसिया को दवा दिलाने के बाद पैदल घर लौट रहे थे। इस बीच बायपास मार्ग पर आसिया पिता का हाथ छुड़ाकर चलने लगी। तभी तेज रफ्तार कार के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बच्ची को चपेट में ले लिया। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार जब्त कर ली है।

मामले में शामिल सभी दोषी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मांग

गोकशी मामलाः शीतलदास की बगिया में उग्र प्रदर्शन नगर निगम का किया पिंडदान, कराया सामूहिक मुंडन

जल्द कार्रवाई नहीं होने पर किया जाएगा उग्र आंदोलन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

धरना-प्रदर्शन करते आंदोलनकारी।

शहर के बडे तालाब स्थित शीतल दास की बगिया में रविवार को हिंदू संगठन ने शहर में 26.5 टन गोमांस मिलने के मामले को लेकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान करीब 30 युवाओं ने सामूहिक मुंडन करवाया और नगर निगम का प्रतिकात्मक पिंडदान भी किया। प्रदर्शनकारी गोकशी मामले में शामिल सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जय मां भवानी हिंदू संगठन के अध्यक्ष भानु हिंदू ने कहा कि इस प्रकरण में असलम और शोएब के साथ उन सरकारी और नगर निगम कर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी भूमिका सामने आने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

अधिकारियों का तर्क, एफएसएल भेजी गई है पिस्टल, जांच के बाद दर्ज होगा केस

बीती रात अवैध पिस्टल से गोली चलने के कारण हो गई थी बच्चे की मौत

मौके से अवैध पिस्टल, कारतूस बरामद होने के बावजूद भी पिस्टल के मालिक पर एफआईआर अब तक दर्ज न होने से उठा सिस्टम पर सवाल!

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

गौतम नगर थाना क्षेत्र स्थित छोला रोड जेपी नगर में शुक्रवार-शनिवार की रात अवैध पिस्टल से फायर होने से हुई बच्चे की मौत के मामले में अब तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। घटनास्थल से पिस्टल और कारतूस बरामद होने के बावजूद पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया। सवाल इस बात का है कि मौके से अवैध पिस्टल, कारतूस बरामद होने के बाद भी पिस्टल के मालिक पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। एसीपी राकेश सिंह बघेल का कहना है कि जांच चल रही है। जबकि थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि पिस्टल एफएसएल भेजी गई है।

मृतक इब्राहिम

जांच पूरी होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जेपी नगर निवासी 12 वर्षीय इब्राहिम की शुक्रवार-शनिवार की रात गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस को उसके पिता रिजवान ने अपने बताया कि अवैध पिस्टल उसके जीजा वाहिद नूर की थी। पुलिस ने घटना स्थल से दो पिस्टल जब्त की थीं। एक पिस्टल खराब बताई जा रही है।

वांटेड वाहिद नूर सीरियल किलर खामरा गिरोह से जुड़ा था

जहांगीराबाद का रहने वाला वाहिद नूर कुख्यात अपराधी है। वह चर्चित अपराधी रहे इरफान बच्चा का करीबी रहा है। इरफान बच्चा की मौत के बाद वह अन्य गुंडे-बदमाशों के संपर्क में रहने लगा। वर्ष 2019 में 32 ट्रक ड्राइवर-कंडक्टर की हत्या करने वाले सीरियल किलर आदेश खामरा के गिरोह से जुड़ गया। खामरा के लूटे ट्रक उसमें लोड सामान को बेचने का काम वाहिद नूर करता था। इसका खुलासा होते ही वाहिद भूमिगत हो गया। तब से अब तक वह नहीं पकड़ा गया। उस पर 50

आश्रय देकर परिवार ने किया अपराध

पुलिस ने वाहिद नूर को कई सालों से तलाश किया। वह कई गंभीर अपराधों में वांटेड है। इसकी जानकारी रिजवान समेत उसके परिवार के सभी सदस्यों को है। बावजूद इसके, वह रिजवान के घर को अपना ठिकाना बनाए हुए था। रिजवान के परिवार के सदस्यों ने पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं दी, जिससे अपराधी को सुरक्षित आश्रय मिला। कानून के अनुसार, किसी भी अपराधी को पनाह देना भी अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में पुलिस ने रिजवान के परिवार पर भी कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई है।

जांच जारी है...

इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। गठित टीम वाहिद नूर और आदेश खामरा गिरोह के बारे में जानकारी जुटा रही है। अवैध पिस्टल सहित बहनोई वाहिद के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।

राकेश सिंह बघेल
एसीपी भोपाल

15 प्रतिशत रिटर्न देने का दिया प्रलोभन

वोडाफोन कंपनी के पूर्व कर्मचारी से 40 लाख की ठगी युवती समेत बिहार के तीन आरोपियों पर दर्ज हुआ केस

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

मिसरोद पुलिस ने वोडाफोन कंपनी के पूर्व अधिकारी की शिकायत पर युवती समेत तीन लोगों पर धोखाधड़ी व अमानत में खयानत की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों ने अपनी फर्जी कंपनी में उन्हें 15 प्रतिशत रिटर्न देने और निवेश की राशि सुरक्षित होने का प्रलोभन देकर 40 लाख रुपए निवेश करा लिए।

राशि निवेश कराने के बाद उसी फर्जी कंपनी में उन्हें डायरेक्टर भी बना दिया। करीब डेढ़ साल बाद आरोपियों ने उन्हें नौकरी से हटा दिया। न तो उन्हें 15 फीसदी रिटर्न दिया और न ही निवेश किए गए 40 लाख रुपए उन्हें लौटाए गए। अपने रुपए मांगने पर आरोपियों ने उन्हें कोराना काल में घाटा होने का झांसा दिया। बाद में फरार हो गए। ठगी की शिकायत फरियादी ने मिसरोद पुलिस थाने और वरिष्ठ अधिकारियों को की थी। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि भोपाल निवासी रितेश कुमार सिंह (45) वर्ष 2019-2020 में वोडाफोन कंपनी में अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। कोरोना काल में उनकी पोस्टिंग गुजरात कर दी गई। परिजन ने उन्हें गुजरात जाने नहीं दिया। लिहाजा उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्हें ग्रेजुएटी के 20 लाख रुपए मिले। उनके अपने पास भी घर के 24 लाख रुपए थे। इस प्रकार उनके पास कुल 44 लाख रुपए की जमापूंजी इकट्ठा हो गई। वह अच्छी नौकरी की तलाश में थे। इस बीच सी-21 मॉल मिसरोद में उनकी मुलाकात अमितेश कुमार सिन्हा, कुमारी प्रिया और सन्नी से हुई। तीनों ने रितेश कुमार को बताया कि उनकी पांच अलग-अलग कंपनियां हैं। यदि वह उनकी उपलब्ध निधि नामक कंपनी में रकम निवेश करोगे तो 15 प्रतिशत का रिटर्न मिलेगा और आपकी जमापूंजी सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा कंपनी में आपको अच्छी नौकरी भी दी जाएगी। यह सुनकर रितेश कुमार सिंह अपनी रकम निवेश करने के लिए राजी हो गए। तीनों आरोपियों ने रितेश कुमार को उपलब्ध फिनटर्स नामक फर्जी कंपनी का अकाउंट नंबर दिया। रितेश ने उसमें अपनी जमापूंजी के 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब उन्हें पता चला कि उनसे उपलब्ध निधि कंपनी में निवेश करने के लिए कहा गया था, जबकि उपलब्ध फिनटर्स कंपनी में पैसा जमा कराया गया है। इस पर आरोपियों ने कहा कि आप निश्चित रहे यह भी हमारी कंपनी है।

पहले डायरेक्टर बनाया फिर नौकरी से निकाला

तीनों आरोपियों ने रितेश कुमार को उपलब्ध फिनटर्स कंपनी में रकम निवेश कराने के बाद उसकी कंपनी का डायरेक्टर भी बना दिया। निवेश या डायरेक्टर बनाने का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। साथ ही बैंकिंग के सभी प्रकार लेनदेन का अधिकार आरोपी अमितेश कुमार सिन्हा और कुमारी प्रिया ने अपने पास रखा। करीब डेढ़ साल तक नौकरी पर रखने के बाद आरोपियों ने रितेश कुमार को नौकरी से निकाल दिया। इस बीच वह 60 से 70 हजार रुपए वेतन देते रहे लेकिन एक बार भी 15 फीसदी रिटर्न नहीं दिया। आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से रितेश कुमार के निवेश किए 40 लाख रुपए दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर करा लिया और कुछ रकम व्यक्तिगत खाते में भी लेकर खर्च कर ली।

विकसित भारत के संकल्प की ओर ले जाता आम बजटः पटवा

हरिभूमि न्यूज ⏭ औबेदुल्लागंज

नप कार्यालय औबेदुल्लागंज में विधायक सुरेंद्र पटवा ने बजट का प्रसारण देखा। पटवा ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट का बजट आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनकी क्षमताओं का विकास कर मजबूत बुनियाद डालेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नपा अध्यक्ष लक्ष्मी चौकसे एवं उपाध्यक्ष नमिता बागिश अग्रवाल एवं मंडल अध्यक्ष डॉ भूपेंद्र नागर, पार्षद दीपू परमार, राजेंद्र गुड्डु साहू, पार्षद सरोज नागर, पार्षद सुजीत यादव, हेमलता मनोज चौरसिया पुरुषोत्तम शर्मा पार्षद सुनील सेरिया पार्षद नरेश भारती सेठी जीतू नंदवंशी राहुल प्रजापति विधायक प्रतिनिधि सोनू चौकसे माखन परमार लोकेश परमार मुख्य नगर पालिका अधिकारी किरण राहंगडाले मुकेश कुमार जैन उपयंत्री नगर परिषद अधिकारी कर्मचारियों का समस्त स्टाफ एवं अधिक संख्या में जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे।

खबर संक्षेप

कांग्रेस ने किया संत रविदास के आदर्शो को नमन

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना के निर्देशानुसार रविवार को सर्वधर्म कॉलोनी बी सेक्टर दामखेड़ा में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती मनाई गई। कोलार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों को नमन किया। इस अवसर पर मुजाहिद सिद्दीकी, अमित मीना, मनोज मिश्रा, पुष्पेंद्र सिंह, ओमप्रकाश अहिरवार, विजय वर्मा, महक राणा, रश्मि मनी, मुन्ना बाई, उषा ताई, योगेश पसरते, संतोष वंशकार, सोनू जैन, आश्विन अहिरवार समेत दामखेड़ा के रहवासी शामिल हुए।

दाहोद में जल शोधन प्लांट का किया निरीक्षण

औबेदुल्लागंज। रविवार को कलेक्टर जिला रायसेन प्राप्त निर्देश के परिपालन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी किरण राहंगडाले एवं मुकेश कुमार जैन उपयंत्री के द्वारा दाहोद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पर आज जल शोधन प्लांट का निरीक्षण किया गया तथा दाहोद प्लांट पर कार्यरत समस्त कर्मचारी दल को आदेशित कर जल शोधन संयंत्र क्लोरिफ्लोकुलेटर की साफ सफाई तथा मेंटेनेंस का कार्य कराया जा रहा आज 1 और 2 फरवरी को दाहोद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से जल सप्लाई का कार्य बंद रहेगा एवं वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 15 वार्ड में जल सप्लाई का कार्य नहीं किया जाएगा।

महावीर कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन

ओबेदुल्लागंज। महावीर कॉलोनी औबेदुल्लागंज में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में आचार्य पं. मनोज शास्त्री महाराज ने कर्म का महत्व बताया कि धर्म कभी भी भगवान से विमुख होकर नहीं करना चाहिए। महाराज ने कथा के माध्यम से बताया कि आज सभी सनातनी पाश्चात्य सभ्यताओं को अपना कर अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं जिसका परिणाम यह है कि आज हमारी संतान माता-पिता की सेवा से विमुख होते जा रहे हैं और महाराज के द्वारा गाये भजनों पर सभी श्रोतागण झूमने लगे। आचार्य पं. मनोज शास्त्री महाराज ने परीक्षित के श्राप की कथा एवं प्रकृति के निर्माण की कथा सुनाई।

ईंटखेड़ी पुलिस की कार्रवाई, साइबर ठग गिरोह का बड़ा खुलासा

दान के नाम पर साइबर ठगीः ट्रस्ट अध्यक्ष और सहायक को होटल बुलाकर की मारपीट

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

ईटखेड़ी पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने उत्तर प्रदेश के ट्रस्ट अध्यक्ष को दान देने के बहाने भोपाल बुलाया और होटल में रुकवाया था। तीन दिन तक होटल में रुकवाने के बाद उन्हें दानदाता से मिलवाने का झांसा देते रहे। जब ट्रस्ट अध्यक्ष ने जाने की बात कही तो आरोपियों ने अध्यक्ष और उसके साथी के साथ मारपीट करते हुए अड़ीबाजी शुरू कर दी। उनसे दस हजार रुपए मांगे गए। साथ ही उनके अकाउंट की जानकारी भी मांगी गई। पूरी घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने होटल से ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि मारुति पैलेस होटल, ईटखेड़ी में कुछ संदिग्ध दो कमरों में ठहरे हुए हैं। सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस होटल चेक करने पहुंची। इस दौरान पुलिस को कुछ गड़बढ़ नजर आई। पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ की। साथ ही फरियादी ओमप्रकाश वर्मा (62) ग्राम परसन का पुरा, थाना इब्राहिमपुर, जिला आंबेडकर नगर से पूछताछ की गई। ओमप्रकाश वर्मा ने बताया कि वह राष्ट्र रक्षा मंच (ट्रस्ट) के अध्यक्ष है। 16 जनवरी को उनके मोबाइल पर कॉल आया। कॉलर ने खुद को जी-8 कंपनी का मैनेजर बताया। उसने कहा कि आपके फेसबुक अकाउंट से पता चला कि आप ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। हमारे पास दानदाता है और वह ट्रस्ट में दान देना चाहता है।

तीन दिन तक होटल में रुकवाने के बाद दानदाता से मिलवाने का देते रहे झांसा

मुखबिर की सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस चेक करने पहुंची होटल

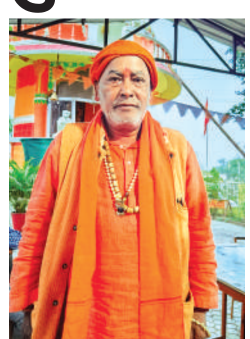

ओमप्रकाश, पीड़ित

कोलार और ईटखेड़ी में होटल में रुकवाया

26 जनवरी को ओमप्रकाश अपने साथी सुखदेव वर्मा के साथ भोपाल पहुंचे। वे स्टेशन के पास बजरिया के लॉज में रुके थे। यह पता चलते ही आरोपी उन्हें दानदाता से मिलवाने के बहाने 27 जनवरी को एक होटल ले गए। वहां 30 जनवरी तक रुकवाया। इसी दिन आरोपी ओमप्रकाश और सुखदेव को लेकर मारुति पैलेस होटल ईंटखेड़ी पहुंचे। वहां दो कमरे किराए पर लिए। आरोपी भी उनके साथ रुके थे। उन्होंने कहा था कि 31 जनवरी की सुबह दानदाता आएगा। 31 जनवरी की सुबह जब दानदाता नहीं आया। ओमप्रकाश और सुखदेव ने होटल छोड़ने की बात कही। इस पर आरोपियों द्वारा गालीगलौज करते हुए खुद को सायबर ठग बताया गया। आरोपियों ने उनसे 10 हजार रुपए मांगे और ट्रस्ट के नाम से यूनियन बैंक खाते की जानकारी जबरन मांगी। जानकारी नहीं देने पर आरोपियों ने ओमप्रकाश और सुखदेव से होटल के कमरे में बंधक बनाकर मारपीट करते रहे। इसके बाद उनके अन्य साथी सत्यम, तनिष्क एवं चरनप्रीत सरदार भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने खाते बेचने एवं संचालित करने की बात कहते हुए फरियादी के बैंक खाते की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी बीच पुलिस की टीम पहुंच गई और ओमप्रकाश सहित सुखदेव को आरोपियों के चंगुल से छुड़वाया गया।

इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने उक्त मामले में मनीष पटेल ईडब्ल्यूएस, दृष्टि सिटी, कोलार, जितेन्द्र पटेल ग्राम मनगवा, महराजपुर, छतरपुर, सत्यम उर्फ शरद बरगले तीन मंदिर, इटारसी, तनिष्क अवस्थी इटारसी, और चरनप्रीत सिंह रुचि लाइफ, जाटखेड़ी मिसरोद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के दस्तावेज चेक किए। इस दौरान पता चला कि आरोपी मनीष पटेल के पेन कार्ड के आधार पर दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में कुल 31 सायबर फ्रॉड शिकायतें दर्ज हुई है। उक्त संबंध में जानकारी राज्य सायबर सेल एवं जिला सायबर सेल को भेजी गई है।

चरणप्रीत

सत्यम

तनिष्क

मनीष

200 किमी के सीसीटीवी फुटेज देख आरोपी को पकड़ा

ट्रेन में चोरी के शातिर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

रेलवे पुलिस (जीआरपी) भोपाल द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करते हुए ट्रेन एवं टेक पास चोरी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से विभिन्न मामलों में चोरी किया गया लगभग सात लाख रुपये मूल्य का सोने का माल बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ऑनलाइन सट्टेबाजी एवं गेमिंग में आर्थिक नुकसान होने के बाद धन अर्जित करने के उद्देश्य से भोपाल क्षेत्र में ट्रेन यात्रियों को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। आरोपी द्वारा सोने के मंगलसूत्र एवं चेन सहित अन्य आभूषणों की चोरी की गई थी, जिनमें दो लेडीज अंगूठियां भी शामिल हैं। 20 जनवरी को फरियादी श्रद्धा अग्रवाल उम्र 52 वर्ष, निवासी बाजपुरा, स्टेशन भोपाल पर प्लेटफॉर्म नंबर-1 से मुंबई की यात्रा के दौरान स्लीपर बर्थ पर सोते समय आरोपी द्वारा उनका लेडीज पर्स चोरी कर लिया गया, जिसमें सोने की चेन, मंगलसूत्र, लेडीज अंगूठी तथा नगद राशि लगभग 35,000/- थी। इस मामले में अपराध क्रमांक 89/26 धारा 305(सी) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मामला की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल एवं उप पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल के मार्गदर्शन में विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्यों एवं लगभग 200 किलोमीटर के सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

कोहेफिजा थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस कर रही जांच

सास ने बहू पर लगाया पर्स चोरी का आरोप, संदेह के आधार केस दर्ज

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

कोहेफिजा थाना क्षेत्र स्थित सुल्तानिया अस्पताल में बेटी का ऑपरेशन करानी पहुंची 70 साल की बुजुर्ग महिला का पर्स चोरी हो गया। पर्स में करीब एक लाख रुपए के जेवर थे। बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू पर चोरी का आरोप लगाया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर बहू के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 70 साल की श्यामाबाई अहिरवार खुशीपुरा, स्टेशन बजरिया में रहती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि गत 13 जनवरी को वह अपनी बेटी का ऑपरेशन कराने सुल्तानिया अस्पताल पहुंची थी। श्यामाबाई अहिरवार का कहना है कि उन्होंने जेवर उतारकर पर्स में रख दिए थे। इस दौरान पर्स अपने ब्लाउस में रख लिया। मौका मिलते ही उनकी बहू रितु अहिरवार ने उनके ब्लाउस में रखा पर्स चुरा लिया। पुलिस ने बप्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामला पारीवारिक विवाद से जुड़ा नजर आ रहा है।

सेवा निवृत्ति पर विदाई एवं सम्मान समारोह आयोजित

शिक्षक खान ने जिस शाला में ग्रहण की शिक्षा, उसी से हुए सेवानिवृत्त

हरिभूमि न्यूज ⏭ नजीराबाद

शनिवार को शासकीय बालक प्राथमिक शाला नजीराबाद में पदस्थ शिक्षक महफूज खान उर्फ चांद भाई के सेवानिवृत्ति पर बैरसिया बीआरसी बालेन्द्र सिंह, बीएसी योगेश सक्सेना, नजीराबाद संकुल प्राचार्य गजराज सिंह गुर्जर सहित अन्य साथियों ने पुष्पमाला एवं शॉल, श्रीफल प्रदान कर भाव भीनी विदाई दी। इस अवसर पर बैरसिया बीआरसी बालेंद्र सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षक महफूज खान ने शिक्षा विभाग में लगातार 31 वर्षों तक अपनी सेवाएं दीं और बच्चों की चिंता करते हुए सही मार्ग और ज्ञान दिया। शिक्षक जुगल सक्सेना ने कहा कि महफूज खान ने विद्यालय में अध्यनरत छात्र एवं साथी शिक्षकों के लिए एक मिसाल पेश की है, क्योंकि उन्होंने जिस विद्यालय में स्वयं प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की आज उसी विद्यालय से बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हुए सेवा निवृत्त हुए हैं। इस दौरान मौजूद लोग भावुक दिखाई दिए।

संत शिरोमणि रविदास महाराज की धूमधाम से जयंती मनाई

हरिभूमि न्यूज ⏭ औबेदुल्लागंज

गुरुद्वारे में रविवार सुबह 11 से संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती पर विशाल कार्यक्रम आरंभ हुआ। इसमें प्रसिद्ध कथाकार जगजीत सिंह जीते भैया ने महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हमें महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर, जीवन सफल बनाए। रविदास जी के उपदेश, मन चंगा तो कठौती में गंगा जिससे परिवार और देश में शांति बनी रहे वही बच्चे नई-नई पोशाकें पहने अति उत्साहित नजर आए, सतवन्त, अमरजीत, गुरनाम ने भजन प्रस्तुत किए, गुरु घर के वजीर भगवान सिंह ने अरदास की, उपरांत प्रसाद, लंगर बांटा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित सुरजीत सिंह बिल्लै सुरजीत सिंह गिल गुरपाल, किशोर सिंह, इंद्र सिंह,मोहन बंजारा, हरदीप आदि मौजूद रहे।

जमीनी लीडरशिप तैयार करने भाजपा की कवायद

नेतृत्व विकास क्षेत्र में औबेदुल्लागंज ब्लॉक को गोल्ड रैंकिंग, ब्लॉक समन्वयक सम्मानित

हरिभूमि न्यूज ⏭ औबेदुल्लागंज

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं मप्र जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, परिषद के निदेशक डॉ. बकुल लाड एवं परिषद के उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज को विकास सेक्टर में जमीनी लीडरशिप तैयार करने की परियोजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु गोल्ड श्रेणी में रखा गया है। गणतंत्र दिवस पर प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पंवार ने ब्लॉक समन्वयक निशा बहेकार को कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश शर्मा, जिला समन्वयक कल्याण सिंह राजपूत की उपस्थिति में प्रमाण पत्र दिया गया। इधर तहसील के एसडीएम चन्द्रशेखर श्रीवास्तव, सीइओ नितेश कटारे, सीएमओ किरण राहांगड़ाले, बीएमओ धर्मेन्द गौर, महिला बाल विकास, आजीविका समूह सहित सभी विभागों के अधिकारियों एवं सहपाठियों ने शुभकामनाएं दी है। मालूम हो कि मप्र सरकार मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास पाठयक्रम का संचालन कर रही है जिसमें विकास सेक्टर हेतु कुशल नेतृत्वकर्ता तैयार किए जा रहे हैं जिसमें सेक्टर अनुसार परामर्शदाताओं के सहयोग से हर सेक्टर के युवाओं को कवर तय समय में किया गया एवं प्रवेश दिलाया गया।

मंडीदीप उद्योग जगत ने बजट पर दी प्रतिक्रियाएं

केंद्रीय बजट 2026 नीति में निरंतरता, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा फोकस तो दूसरी ओर फार्मा इंडस्ट्री को संजीवनी

नितेश पटेल ⏭ मंडीदीप

1 फरवरी को केंद्र के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026–2027 का आम बजट कल सांसद भवन में पेश किया जिसमें औद्योगिक अधोसंरचना को बढ़ावा देने के लिए एक गति मिलेगी तो वही फार्मा इंडस्ट्री को संजीवनी के तौर पर बेहतर गति मिल सकेगी, माना जाता है कि पिछले बजट के अनुसार इस बजट में देश में जो ट्रंप के टैरिफ को कड़ा टक्कर देने में इसे मजबूती मिलेगी।

एसोसिएशन ऑफ आल इंडस्ट्रीज मंडीदीप के पूर्व अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) 12.2 लाख करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, स्टील, ईपीसी, कैपिटल गुड्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए दीर्घकालिक अवसर और रोजगार सृजन सुनिश्चित करेगा, जो इंडस्ट्रीज को बेहतर गति प्रदान करेगा।

ये बजट देश के लिए बेहतर और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा

बजट 2026 एक मजबूत आधार प्रस्तुत करता है लेकिन उद्योग अब बोल्ड रिफॉर्म्स, तेज मंजूरी प्रक्रियाओं और सरकार-उद्योग के सहयोग से देश को गति देने का काम कर रहा है। ये बजट देश के लिए बेहतर और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा।

विकाश मुंद्रा, अध्यक्ष
एसोसिएशन ऑफ आल इंडस्ट्रीज मंडीदीप

फार्मा सेक्टर के लिए सकारात्मक और भविष्योन्मुख है बजट

रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और दवा नियामक प्रणाली को मजबूत करने से नई दवाओं के विकास और अनुमोदन में तेजी आएगी। कैंसर और रेयर डिजीज की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट मरीजों को राहत देगी। कुल मिलाकर, यह बजट फार्मा उद्योग को नवाचार, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में आगे बढ़ाने वाला है।

राजीव पुरी, वरिष्ठ महाप्रबंधक,
लुपिन फार्मा इंडस्ट्री मंडीदीप

ग्रीन मॉडल को नुकसान शरारती तत्वों ने उखाड़ी बस स्टॉप की आर्टिफिशियल ग्रीनरी

भोपाल। राजधानी भोपाल में मार्च-अप्रैल से शुरू होने जा रही ई-बस सेवा के लिए ग्रीन कांसेप्ट पर विकसित किए जा रहे बस स्टॉप शरारती तत्वों के निशाने पर आ गए हैं। कई स्थानों पर बस स्टॉप पर लगाई गई आर्टिफिशियल ग्रीनरी और ग्रीन नेट को उखाड़ दिया गया है। इससे शहर के ग्रीन मॉडल को नुकसान पहुंचा है। पंचशील नगर क्षेत्र में बनाए गए ग्रीन कांसेप्ट बस स्टॉप की आर्टिफिशियल ग्रीनरी को पूरी तरह उखाड़ दिए जाने का मामला सामने आया है। जबकि भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (बीसीएलएल) द्वारा इन बस स्टॉप को फूल-पत्तियों और हरियाली से सुसज्जित कर उनके बीच आकर्षक लाइटिंग लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है। लगातार सामने आ रहे नुकसान के मामलों के बाद बीसीएलएल ने पुराने बस स्टॉप के रिनोवेशन का कार्य तेज कर दिया है। वहीं प्रयोग के तौर पर शहर के चुनिंदा इलाकों में ग्रीन कांसेप्ट के बस स्टॉप विकसित किए जा रहे हैं। योजना के तहत करीब 100 बस स्टॉप को हरियाली, सजावटी पौधों और आधुनिक लाइटिंग से लैस किया जाना है।

कांट्रेक्टर से कहकर दोबारा दुरुस्त करवाएंगे

बीसीएलएल के डायरेक्टर मनोज राठौर का कहना है कि कांट्रेक्टर से कहकर बस स्टॉप को दोबारा दुरुस्त करवाया जाएगा। आम लोगों की जिम्मेदारी है कि वे इन्हें नुकसान न पहुंचाएं।

रणजी ट्रॉफी: विदर्भ और आंध्र ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, झारखंड ने ओडिशा को हराया

एजेंसी ▶▶| नागपुर

गत चैंपियन विदर्भ ने उत्तर प्रदेश को चार विकेट से हराकर ग्रुप ए से आंध्र के साथ एलीट रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विदर्भ की टीम ग्रुप ए में आंध्र के बाद दूसरे स्थान पर रही। दोनों टीम ने सात मैच में समान 31 अंक हासिल किए लेकिन आंध्र की टीम बेहतर नेट रन रेट के कारण शीर्ष पर रही। उत्तर प्रदेश के 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विदर्भ की टीम ने चौथे और अंतिम दिन चार विकेट पर 91 रन से आगे खेलते हुए छह विकेट गंवाकर 58.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज अमन मोखाडे 150 गेंद में 83 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके मारे। दानिश मालेवार ने भी 54 रन की पारी खेली। उत्तर प्रदेश की तरफ से बाएं हाथ के स्पिनर शिवम शर्मा ने 55 रन देकर चार विकेट चटकाए। सोविमा में अपने अंतिम मैच में नगालैंड के खिलाफ ड्रॉ खेल आंध्र की टीम शीर्ष पर रही। नगालैंड ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 85 रन से आगे खेलते हुए 342 रन बनाए। चेतन बिष्ट ने 100 जबकि नगाहो चिषी ने 79 रन की पारी खेली। आंध्र को 173 रन का लक्ष्य मिला लेकिन टीम 8.3 ओवर में चार विकेट पर 64 रन बनाने के बाद मैच ड्रॉ कराने को राजी हो गई क्योंकि उसे तालिका के शीर्ष पर जगह दिलाने के लिए ड्रॉ काफी था।

तमिलनाडु और बड़ौदा का मैच ड्रॉ

ग्रुप ए के एक अन्य मैच में नॉकआउट की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके तमिलनाडु और बड़ौदा का मैच नीरस ड्रॉ रहा। तमिलनाडु ने अंतिम दिन सात विकेट पर 411 रन से आगे खेलते हुए 449 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज विमल कुमार 182 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। इसके जवाब में पहली पारी में 375 रन बनाने वाले बड़ौदा ने दूसरी पारी में शिवालिक शर्मा (नाबाद 59) और ज्योत्सनिल सिंह (नाबाद 55) के अर्धशतक से बिना विकेट खोए 124 रन बनाए। ग्रुप ए में ही जमशेदपुर में मेजबान झारखंड ने ओडिशा को चार विकेट से हराया। ओडिशा ने दूसरी पारी की शुरुआत आठ विकेट पर 202 रन से करते हुए मैच के अंतिम दिन 226 रन बनाए। झारखंड को 246 रन का लक्ष्य मिला, जो उसने 71.3 ओवर में छह विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज शरणदीप सिंह (64) और रोबिन मिन्ज (63) ने अर्धशतक जड़े जबकि अनुकूल रॉय (45) ने भी उम्दा पारी खेली।

जम्मू-कश्मीर ने मुंबई के साथ बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह

मुंबई। कप्तान आयुष दोसेजा की नाबाद 159 रन की पारी की बदौलत दिल्ली ने रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप डी में तालिका में शीर्ष पर काबिज मुंबई के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ करा लिया। इसी ग्रुप से जम्मू-कश्मीर ने भी 42 बार की चैंपियन मुंबई के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दोसेजा ने एमसीए-बीकेसी ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में 230 गेंदों में 11 चौकों और दो छक्कों की मदद से 159 रन बनाए और मुंबई को जीत से दूर रखा। दोनों टीमों ने चाय के विश्राम से करीब आधा घंटा पहले मुकाबला बराबरी पर समाप्त करने पर सहमति जता दी। दिल्ली ने दूसरी पारी छह विकेट पर 407 रन बनाकर घोषित की। उस समय उसकी कुल बढ़त 311 रन की थी। दिल्ली ने पहली पारी में 96 रन से पिछड़ने के बाद पिछले दो दिनों में मुंबई को कड़ी चुनौती दी। मुंबई ने सात मैचों में चार जीत और दो ड्रॉ से ग्रुप डी में 33 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया।

छत्तीसगढ़ और हैदराबाद का मैच ड्रा

छत्तीसगढ़ की टीम मेजबान हैदराबाद के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में आठ विकेट पर 411 रन बनाकर 63 रन की बढ़त हासिल कर मैच ड्रॉ करने में सफल रही। हैदराबाद ने पहली पारी में 631 रन बनाने के बाद छत्तीसगढ़ को 283 रन पर आउट कर 348 रन की बड़ी बढ़त कायम की थी। पुडुचेरी ने इस बीच राजस्थान को पांच विकेट से शिकस्त दी। टीम ने आर श्रीराम के 57 और अजय रोहेरा के नाबाद 49 रन की पारी से जीत के लिए मिले 172 रन के लक्ष्य को पांच विकेट गंवा कर हासिल कर लिया।

खबर संक्षेप

महिला अंडर-17 टीम के सामने बांग्लादेश की चुनौती

पोखरा। भारतीय टीम सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के अपने दूसरे मुकाबले में सोमवार को जब पोखरा रंगशाला स्टेडियम में मजबूत बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश एक मैच शेष रहते फाइनल में जगह पक्की करने की होगी। इस साल के आखिर में चीन में होने वाले एएफसी अंडर-17 महिला एशियाई कप की तैयारियों में लगी पामेला कॉन्टी की टीम ने अपने अभियान की शुरुआत मेजबान नेपाल के खिलाफ कड़े मुकाबले में 1-0 की जीत के साथ की थी। भारतीय टीम अगर इस मैच को जीतने में सफल रही तो फाइनल के लिए उसका दावा लगभग पक्का हो जाएगा। भारत को इससे पहले मेजबान नेपाल से कड़ी चुनौती मिली लेकिन पर्ल फर्नांडिस ने 49वें मिनट में गोल कर मैच में बड़ा अंतर पैदा किया।

जूनियर पुरुष स्कीट टी2 ट्रायल में पंजाब के निशानेबाज शीर्ष पर

नई दिल्ली। पंजाब के हरवीराज सिंह, हरजीज सिंह अटवाल और गुरफतेह सिंह संधू ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल कर शॉटगन राष्ट्रीय चयन ट्रायल्स एक और दो में जूनियर पुरुष स्कीट टी2 के फाइनल में क्लीन स्वीप किया। अनंतजीत सिंह

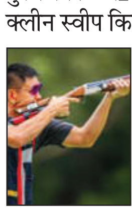

नरूका ने पुरुष वर्ग के ट्रायल दो फाइनल में 36 में से 36 का परफेक्ट स्कोर कर ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया को एक अंक से पछाड़ते हुए खिताब जीता। यशस्वी राठौड़ ने महिला ट्रायल्स दो में सिर्फ एक निशाना चूकते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। क्वालीफिकेशन में 120 अंक के साथ शीर्ष पर रहने वाले अनंतजीत ने फाइनल में सटीक प्रदर्शन किया। ज्योतिरादित्य ने भी 34वें टारगेट तक परफेक्ट स्कोर बनाए रखा, लेकिन 35वें निशाने में चूकने के कारण 36 में से 35 अंक ही हासिल कर सके। अभय सिंह सेखों ने 30 निशाने के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

खिलाड़ियों को करना होगा दिनचर्या में बदलाव : सैंटनर

तिरुवनंतपुरम। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि उनकी टीम टी20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उपमहाद्वीप में अपने पिछले अनुभव और विभिन्न परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की अपनी

क्षमता पर भरोसा करेगी। न्यूजीलैंड ने सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से पहले भारत के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। सैंटनर ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने हाल आईपीएल में या अपने करियर के दौरान चेन्नई में मैच खेले हैं। उन्होंने कहा, 'दिन का खेल थोड़ा अलग होने वाला है। खिलाड़ियों को अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। उन्हें थोड़ा जल्दी जागने की कोशिश करनी होगी। लेकिन फिर भी यह हमारे लिए एक नई चुनौती है।

22 साल के अल्कारेज ने एक सेट गंवाने के बाद की वापसी, जोकोविच को दी शिकस्त

अल्कारेज ने कम्पलीट किया कॅरियर स्लैम, तोड़ा जोकोविच का सपना, जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन

एजेंसी ▶▶| मेलबर्न

कार्लोस अल्कारेज रविवार को फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब अपने नाम करके कॅरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंडस्लैम- ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लेता है तो उसे कॅरियर ग्रैंडस्लैम पूरा करना कहते हैं।

रिकॉर्ड 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश कर रहे जोकोविच की मेलबर्न पार्क में फाइनल में यह पहली हार है। इससे पहले उन्होंने यहां अपने सभी 10 फाइनल में जीत दर्ज की थी। शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी अल्कारेज ने रविवार को पहला सेट गंवाया लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से जीत हासिल की। 22 साल के स्पेन के खिलाड़ी ने 38 साल के जोकोविच पर दबाव बनाए रखा।

कोच को गले लगाने दौड़े कार्लोस

जीत पक्की करने के बाद अल्कारेज ने हाथ से रैकेट छोड़ दिया और वह पीठ के बल जमीन पर गिर गए और अपने हाथ सिर पर रख लिए। जोकोविच से हाथ मिलाने के लिए नेट पर जाने से पहले वह कुछ सेकेंड वहीं रुके। दोनों खिलाड़ियों ने कुछ बातें कीं और जोकोविच स्पेन के खिलाड़ी को बधाई देते हुए मुस्कुराए। इसके बाद नया चैंपियन कोर्ट के एकतरफ लगी कुर्सियों पर बैठे अपने कोच को गले लगाने के लिए दौड़ा और बाद में स्टैंड में अपने पिता और टीम के दूसरे सदस्यों को भी गले लगा।

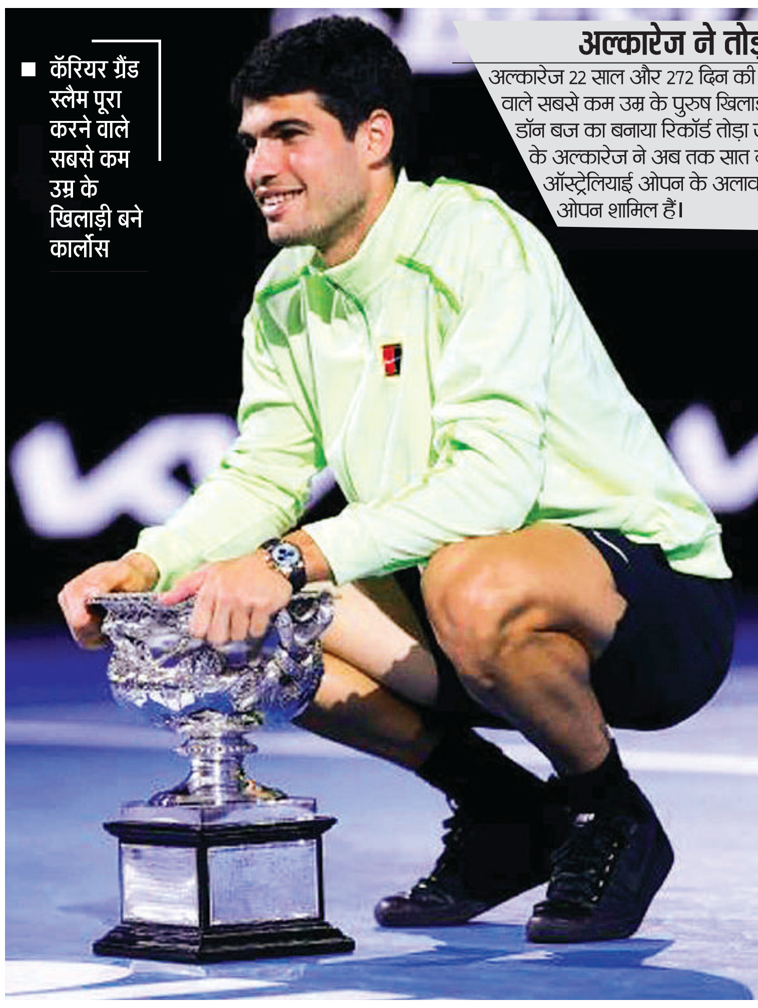

■ कॅरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने कार्लोस

अल्कारेज ने तोड़ा डॉन बज का रिकॉर्ड

अल्कारेज 22 साल और 272 दिन की उम्र में चारों ग्रैंडस्लैम का एकल खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बने। उन्होंने 1938 की फ्रेंच चैंपियनशिप में डॉन बज का बनाया रिकॉर्ड तोड़ा जब वह 22 साल और 363 दिन के थे। स्पेन के अल्कारेज ने अब तक सात ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई ओपन के अलावा दो-दो विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन शामिल हैं।

जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम पर अल्कारेज ने लगाई रोक

दोनों खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पांच सेट में कड़ी जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों की तलाश में तीन घंटे से अधिक समय तक दोनों ने जबरदस्त फिटनेस, खेल और स्टेमिना का नजारा दिखाया। कोई भी खिलाड़ी बड़े अंकों पर हार मानने को तैयार नहीं था। स्पेन के खिलाड़ी ने 16 ब्रेक प्वाइंट में से पांच का फायदा उठाया जबकि जोकोविच छह ब्रेक प्वाइंट में से सिर्फ दो को ही अंक में बदल सके। जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम एकल खिताब जीतने के अभियान पर एक बार फिर अल्कारेज और यानिक सिनर में से एक ने रोक लगाई। इन दोनों ने मिलकर पिछले नौ ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं। जोकोविच ने सेमीफाइनल में सिनर को हराया था और ओपन युगल में ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनने की राह पर थे लेकिन अल्कारेज ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

आयरलैंड ने किया विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई

थाईलैंड को 62 रन से हराया

एजेंसी ▶▶| कीर्तिपुर

आयरलैंड ने ग्लोबल क्वालीफायर के सुपर सिक्स स्टेज में थाईलैंड को 62 रन से हराकर आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी जगह पक्की कर ली है। यह टूर्नामेंट इस साल जून-जुलाई के बीच खेला जाना है।

आयरलैंड ने इस स्टेज में खेले गए पांच मुकाबलों में से तीन में जीत हासिल की। इसी के साथ बांग्लादेश और नीदरलैंड के बाद क्वालीफायर से चुनी जाने वाली तीसरी टीम बन गई। आयरलैंड 2023 के बाद अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार को खेले गए इस मुकाबले में आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लेते हुए 8 विकेट खोकर 121 रन बनाए। इस टीम की तरफ से टॉप-3 बल्लेबाजों ने सर्वाधिक रन बनाए। एमी हंटर ने 24 रन और कप्तान गैबी लुईस ने 25 रन बनाए, जबकि ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने टीम के खाते में 24 रन का योगदान दिया। विपक्षी खेमे से सुलेपॉर्न लेओमी ने 24 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि सुनीदा चतुरोंगरताना ने 2 विकेट निकाले। एक सफलता ओनीचा कामचौम्फू के हाथ लगी।

59 रन पर सिमटी थाईलैंड

इसके जवाब में थाईलैंड की टीम 16.1 ओवरों में महज 59 रन पर सिमट गई। यह टीम 8 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से नन्नापत कोंचारोएनकाई (15) ने कप्तान नारुएमोल चायवाई (22) के साथ तीसरे विकेट के लिए 26 रन जुटाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस जोड़ी के टूटते ही थाईलैंड ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आलम ये रहा कि इस टीम के 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके। आयरलैंड की तरफ से अर्लीन केली ने महज 7 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि लारा मैकब्राइड ने 3 सफलताएं प्राप्त कीं।

स्क्वैश ऑन फायर

सबरीना को 3-1 से हराकर फाइनल में पहुंचीं अनाहत

एजेंसी ▶▶| वाशिंगटन

अनाहत सिंह ने वाशिंगटन में स्क्वैश ऑन फायर ओपन में अमेरिका की सबरीना सोभी को 3-1 से मात दी। इसी के साथ अनाहत ने पीएसए ब्रॉन्ज-लेवल इवेंट के अपने पहले फाइनल में जगह बना ली है। अनाहत सिंह ने सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 23 सबरीना को 11-9, 11-3, 9-11, 11-5 से शिकस्त दी। खिताबी मुकाबले में 17 वर्षीय अनाहत का सामना टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 10 इंग्लैंड की जॉर्जीना कैनेडी से होगा। इससे पहले, शनिवार को अनाहत ने 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए नंबर 2 सीड सना इब्राहिम को शिकस्त देकर स्क्वैश ऑन फायर ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारतीय वर्ल्ड नंबर 31 और सातवीं सीड खिलाड़ी ने मैच में वापसी करते हुए, तीसरे और चौथे गेम दोनों में 6-5 के घाटे को पलट दिया, और पीएसए ब्रॉन्ज-लेवल इवेंट में मिस्र की वर्ल्ड नंबर 17 सना इब्राहिम को 8-11, 8-11, 11-7, 11-8, 11-7 से मात दी थी।

पीएसए टूर में बनाई अलग पहचान

अनाहत ने इस सीजन पीएसए टूर पर अपनी अलग पहचान बना ली है। खासतौर पर अक्टूबर में सिल्वर-लेवल कैनेडियन विमेंस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचकर उन्होंने सभी का ध्यान खींचा था, जिसके बाद वह जल्द ही विश्व की टॉप-30 खिलाड़ियों में शामिल हो गईं। पिछले कुछ महीनों में अनाहत शानदार फॉर्म में रही हैं।

बल्लेबाजी में बदलाव से मिली फॉर्म में वापसी में मदद: सूर्यकुमार

तिरुवनंतपुरम। भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पिछले साल दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला के बाद मिले ब्रेक और बल्लेबाजी में किए गए कुछ बदलाव से उन्हें अपनी फॉर्म में वापसी करने में मदद मिली। सूर्यकुमार ने शनिवार से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड पर भारत की 4-1 से जीत में आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए कुछ उम्दा पारियां खेली। सूर्यकुमार पिछले साल रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। वह इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं बना पाए थे लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करके न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाए और उन्हें श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के बाद सूर्यकुमार ने आत्मचिंतन किया और अपने खेल में कुछ बदलाव किए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार पारियों में वह केवल 34 रन बनाए थे, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 12 रन था। सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत की 46 रन से जीत के बाद कहा, 'दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के बाद मुझे ब्रेक मिला। मैंने घर लौटने पर अपना किट बैग एक तरफ रखा और नौ-दस दिन तक आराम किया।'

वेस्टइंडीज ने द.अफ्रीका को हराया, सीरीज की अपने नाम

एजेंसी ▶▶| बजोहानिसबर्ग

वेस्टइंडीज ने बारिश से प्रभावित तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुइस पद्धति के आधार पर छह रन से हराकर विश्व कप से पहले मनोबल बढ़ाने वाली जीत दर्ज की। पहले दोनों मैच जीतने वाले दक्षिण अफ्रीका ने इस तरह से तीन मैच की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की।

बारिश के कारण मैच लगभग दो घंटे देर से शुरू हुआ और इसे दोनों टीमों के लिए 16-16 ओवरों का कर दिया गया। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जब छह ओवर में एक विकेट पर 66 रन बनाए थे तभी बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा और बाद में इसे दोनों टीमों के लिए 10-10 ओवरों का कर दिया गया।

होप और हेटमायर ने जड़े 10 छक्के

वेस्टइंडीज ने तीन विकेट पर 114 रन बनाए। उसकी तरफ से कप्तान शाई होप ने 25 गेंदों में 48 रन और शिमरोन हेटमायर ने 22 गेंदों में नाबाद 48 रन का योगदान दिया। इन दोनों ने मिलकर 10 छक्के जड़े। दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुईस पद्धति से 125 रन का लक्ष्य मिला लेकिन उसकी टीम छह विकेट पर 118 रन ही बना पाई। क्विंटन डीकॉक ने 14 गेंद पर 28 और जैसन स्मिथ ने 10 गेंद पर 26 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से गुडाकेश मोती ने 17 रन देकर तीन विकेट लिए। भारत और श्रीलंका में हो रहे विश्व कप में वेस्टइंडीज शनिवार को कोलकाता में स्कॉटलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। दक्षिण अफ्रीका इसके दो दिन बाद अहमदाबाद में कनाडा के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा।

थाईलैंड मास्टर्स में हटी दो बार की विश्व जूनियर चैंपियन गोह

देविका ने जीता अपना पहला सुपर 300 खिताब

एजेंसी ▶▶| बैंकॉक

युवा शटलर देविका सिहाग ने 250,000 डॉलर इनामी थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में मलेशिया की गोह जिन वेई के मैच के बीच से हट जाने के बाद अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 खिताब जीता।

हरियाणा की रहने वाली 20 वर्षीय खिलाड़ी देविका तब 21-8, 6-3 से आगे चल रही थी, जब विश्व में 68वें नंबर की खिलाड़ी और दो बार की विश्व जूनियर चैंपियन गोह ने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इससे भारतीय खिलाड़ी अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीतने में सफल रही।

देविका के लिए फाइनल रहा शानदार

देविका के लिए फाइनल शानदार रहा लेकिन उनकी प्रतिद्वंद्वी गोह को पीड़ा झेलनी पड़ी। वह फाइनल से पहले तीन गेम तक चले चार मैच खेलने के बाद थकी हुई लग रही थीं और उन्हें कोर्ट को कवर करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पिछले दो वर्षों से फॉर्म और फिटनेस के लिए संघर्ष कर रही गोह ने शनिवार को भी थकान की शिकायत की थी और उन्हें कोर्ट में चलने-फिरने में परेशानी हो रही थी। उनका बायां पैर हिल नहीं पा रहा था और वह लगातार परेशान दिख रही थीं। देविका ने फाइनल में शानदार शुरुआत की। उन्होंने अपने दमदार रिटर्न और बेहतरीन स्ट्रोक के दम पर 4-0 की बढ़त बना ली। एक नेट कॉर्ड की बदौलत गोह ने अपना पहला अंक हासिल किया।

मलेशियाई खिलाड़ी लग रही थीं थकी हुई

मलेशियाई खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी के खेल को समझ ही नहीं पा रही थी। मलेशियाई खिलाड़ी थकी हुई लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उनमें ऊर्जा नहीं बची है। देविका ने शानदार क्रॉस के दम पर 13 गेम प्वाइंट हासिल किए और बैकहैंड क्रॉस से पहला गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में देविका ने जल्द ही 6-3 की बढ़त बना ली। मलेशिया की खिलाड़ी असहज दिख रही थी और उन्होंने आखिर में मैच से हटने का फैसला कर दिया। देविका ने पिछले कुछ समय से शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने अगस्त 2025 में मलेशिया इंटरनेशनल में अपना पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता था। इसके बाद उन्होंने 2025 में विश्व विश्वविद्यालय खेलों में भारत की मिश्रित टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम योगदान दिया। वह पिछले सत्र में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 में उपविजेता रही थी जबकि 2024 में चार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। इनमें स्वीडिश ओपन और पुर्तगाल इंटरनेशनल भी शामिल हैं, जहां वह विजेता रही थी।

पेज एक का शेष...

विकास को मिलेगी ...

निभाएगा। आर्थिक प्रगति को बढ़ाना, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास बजट की मुख्य विशेषता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5000 करोड़ रुपए खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने, प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण और जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की व्यवस्था से प्रदेश को बहुत लाभ होगा। केंद्रीय बजट में वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफॉर्म पर बल दिया गया है, इससे मप्र को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मप्र को पीएम मित्र पार्क के रूप में टैक्सटाइल क्षेत्र की बड़ी सौगात दी है। इससे तीन लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही 6 लाख किसानों को लाभ होगा। इस पार्क से प्रदेश का मालवा निमाड़ अंचल नई उड़ान के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की वस्त्र उद्योग सेक्टर की दूरगामी नीतियों से संपूर्ण राष्ट्र के साथ मध्यप्रदेश को भी विशेष लाभ होगा। उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिवादन किया। बजट में इनकम टैक्स में छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान करने की व्यवस्था है। राजकोषीय घाटे का 4.3% का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों के लिए एक लाख 40 हजार करोड़ रुपए का अनुदान रखा गया है, जिससे मप्र को भी लाभ प्राप्त होगा।

बजट पूरी तरह...

किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को तीन हजार रुपए प्रतिमाह भत्ता और किसानों को गेहूं तथा धान का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य प्रदान करने का वादा किया था। लेकिन इस दिशा में केंद्रीय बजट से मध्यप्रदेश को कोई सहयोग नहीं मिला है। मध्यप्रदेश के प्रति सौतेला व्यवहार किया गया है।

विकसित भारत ...

लागत कम हो और किसान को राहत मिले। नेशनल फाइबर स्कीम के तहत सिल्क, वूल और जूट जैसे फाइबर पर फोकस किया गया है, जिससे इनसे जुड़े किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। आयुष मंत्रालय में मेडिसिनल प्लांट्स के सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट से संबंधित प्रावधानों का फायदा औषधीय पौधे उगाने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। परंपरागत फसलों के साथसाथ नारियल, कोको, काजू और चंदन की लकड़ी जैसी उच्चमूल्य फसलों के लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। नारियल के पुराने बागों का पुनरुद्धार और नए बाग लगाने के लिए बजट में व्यवस्था की गई है।

तेजी से आगे ...

गतिविधियों को विस्तार देने में भी मदद मिलेगी। अन्य राज्यों की तुलना में मप्र में एमएसएमई विकास का सबसे अच्छा ईको-सिस्टम बना है। इस बजट से एमएसएमई सेक्टर को भरपूर विस्तार मिलेगा। बजट में गरीब, युवा अन्नदाता और नारी शक्ति वर्ग पर विशेष फोकस है। बायोफार्मा हब बनाने की पहल के दूरगामी परिणाम आएंगे। विनिर्माण क्षेत्रों का रणनीतिक विकास किया जाएगा। लखपति दीदी विस्तार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की पहल स्वागत योग्य है। इसके तहत सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट बनाए जाएंगे जो क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन के अंतर्गत सामुदायिक खुदरा आउटलेट्स के रूप में भी कार्य करेंगे। इससे मध्यप्रदेश में महिला उद्यमिता को भरपूर प्रोत्साहन मिलेगा।

आर्थिक हालात को ...

लाभ मिलेगा और न ही विकास को गति मिलेगी। आर्थिक सर्वे खुद स्वीकार करता है कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार है, इसके बावजूद बजट में युवाओं के लिए कोई ठोस रोजगार योजना, न शहरी रोजगार गारंटी और न ही नई भर्तियों का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया। यह बजट 'जॉबलेस ग्रोथ' को और गहरा करता है।

युवाओं, महिलाओं व ...

दी जाएगी। बड़े शी मार्ट बनेंगे, जिससे महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने में आसानी होगी। बजट से किसानों को पशुपालन के क्षेत्र में बढ़वा मिलेगा। उत्पादन वृद्धि के लिए भी प्रयास किए गए हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में तीन कॉलेज खोले जाएंगे जो एम्स की तर्ज पर काम करेंगे। वहीं, पांच मेडिकल हब बनाए जा रहे हैं। इससे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। कस्टम डयूटी कम कर राहत दी गई है। भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अधिक होने के कारण एक्सपोर्ट प्रभावित होता है। इस बजट में पहली बार अलग मालगाड़ी कॉरिडोर बनाने की बात की गई है।

टीम हसलर्स बनी सीए फ्रेंड्स क्लब टर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट सीज़न–3 की चैंपियन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

सीए फ्रेंड्स क्लब द्वारा आयोजित टर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट सीज़न-3 का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भाग लिया। इस पटूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला टीम हसलर्स (कप्तानः अनुग्रह) और टीम लीजेंड्स (कप्तानः ऋषभ) के बीच खेला गया। टीम हसलर्स ने 8 ओवर में 112 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इनमें गोविंद रिनवा ने 26 गेंदों में 62 रन बनाए, जो फाइनल का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रहा। वहीं गेंदबाज़ी में कप्तान अनुग्रह ने 2 ओवर में 2 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम लीजेंड्स 8 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 82 रन ही बना सकी। इस प्रकार टीम हसलर्स ने यह फाइनल मुकाबला 30 रन से जीतकर टूर्नामेंट सीज़न–3 की ट्रॉफी अपने नाम की।फाइनल मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोविंद रिनवा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं पूरे टूर्नामेंट में शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन के लिए राहुल गुर्मलानी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट के साथ-साथ बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेहतरीन फील्डिंग के लिए मोहित को बेस्ट फील्डर का पुरस्कार प्रदान किया गया। टूर्नामेंट के आयोजन में आयोजन समिति के सदस्य सचिन राय, राहुल, अनुनय, अनुग्रह, निर्भय, हिमांशु, चेतन, यद्वेंद्र, सक्षम, दिव्यांशु, प्रफुल्ल एवं करण का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

प्रतीक के 130 रन की बदौलत भोपाल डिवीजन मजबूत

भोपाल। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित हीरालाल गायकवाड़ ट्रॉफी अंडर -18 बॉयज इंटर डिविजनल क्रिकेट टूर्नामेंट मल्टी डे इंदौर के एमपीसीए क्रिकेट मैदान पर (चार दिवसीय) चंबल डिवीजन और भोपाल डिवीजन के मध्य मैच के दूसरे दिन कल के स्कोर 9/245 रन से आगे खेलते हुए चंबल डिवीजन ने 92 ओवर में 249 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में भोपाल डिवीजन ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 86 ओवरों में 5 विकेट पर 307 रन बना लिए हैं,जिसमें प्रतीक शुक्ला शानदार 130 रन की शतकीय पारी खेलकर नाबाद हैं और मलय श्रीवास्तव 57 रन पर आउट हुए, जिसमें पांचवें विकेट के लिए 126 रनों की पार्टनरशिप प्रतीक शुक्ला और आलिफ हसन के मध्य हुई, आलिफ हसन 39 रन पर आउट और हर्षित शर्मा 30 रन पर आउट हुए। चंबल डिवीजन से गेंदबाजी करते हुए निश्चय सिकरवार ने 4 विकेट लिए। इस तरह भोपाल डिवीजन नें पहली पारी में 58 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। कल सोमवार को मैच का तीसरा दिन है।

एचएमजी क्रिकेट मैदान डीपीएस पर हुए ट्रायल

भोपाल लेपर्ड्स के सिलेक्शन ट्रायल में 350 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, 40 शॉर्ट लिस्ट

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

आगामी सीजन मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग (एमपीएल) की तैयारियों को लेकर भोपाल लेपर्ड्स क्रिकेट टीम के चयन ट्रायल 30 व 31 जनवरी को एचएमजी क्रिकेट मैदान डीपीएस पर संपन्न हुए। इसमें सीहोर, विदिशा और भोपाल के करीब 350 युवाओं ने हिस्सा लिया जिसमें से 40 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब उनके बीच मैच कराकर कुछ प्रतिभावान खिलाड़ियों को भोपाल लेपड्र्स टीम में चयनित किया जाएगा। यह सिलेक्शन मैच 4 व 5 फरवरी को डीपीएस क्रिकेट मैदान पर आयोजित किया जाएगा।

भोपाल लेपड्र्स,जो कि मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग (सिंधिया कप)2025 की चैंपियन हैं इस सत्र में भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए चैंपियन बनने की राह पर चलेगा। इसी उद्देश्य से यह चयन ट्रायल और प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है।

कार्यालय, प्राचार्य अग्रणी शासकीय गृहविज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय नर्मदापुरम (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

महाविद्यालय में सामग्री कय किये जाने हेतु एम.पी.ई. टेंडर पोर्टल पर निविदा जारी की गई है निविदा में भाग लेने हेतु एम.पी.ई. टेंडर पर दर्शित प्रक्रिया अनुसार निविदा में भाग लिया जा सकता है।

1.	Start Date -	31.01.2026
2.	End Date -	14.02.2026

प्राचार्य
सरकारी गृह विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नर्मदापुरम (म.प्र.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कुसुम स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी मालवा जिला-नर्मदापुरम
ISO 9001:2015,ISO 14001:2015
दुरभाष 07570-224457 नेक मूल्यांकन-'B++' ग्रेड E-mail-hegkcseohos@mp.gov.in

//निविदा आमंत्रण सूचना//

महाविद्यालय में प्रयोगशाला उपकरण क्रय किये जाने पोर्टल पर निविदा जारी गई निविदा में भाग लेने हेतु जेम पोर्टल पर दर्शित प्रक्रिया अनुसार निविदा में भाग लिया जा सकता

1.	Bid Start Date	29.01.2026
2.	Bid End Date	13.02.2026

डॉ. आर.के.रघुवंशी
प्राचार्य

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, (वि.यॉ.)
लोक निर्माण विभाग, वि./यॉ.संभाग क्र.-2, बारह दफ्तर परिसर, जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.)

निविदा सूचना

सूचना प्रकाशन क्रमांक,33/व.ले.लि./2025-26 भोपाल, दिनांक : 30/01/2026

निम्नलिखित कार्यो हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	पोर्टल टेंडर क्र.	एन.आई.टी.क्र.	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	ठेके की अनु. राशि	धरोहर राशि	निविदा राशि
1	2026_PWDRB_478956_1	61/SAC/2025-26	प्रोवाईडिंग पोल शिफ्टिंग एवं हाईट रेसिंग 11 केव्ही 33 केव्ही एल टी लाईन एण्ड ट्रांसफार्मर डयू टू कन्स्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन रोड फ्राम जावर से कजलास से बिसूखेडी जिला सीहोर	प्रथम आंमत्रण	12705327.00	127053.00	12500.00
			योग :-		12705327.00		

नोटः- निविदा विक्रय दिनांक 30/01/2026 प्रातः10:30 बजे से निविदा विक्रय अंतिम दिनांक 17/02/2026 सांय 5:30 बजे तक एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत करना है। निविदा की निर्धारित तिथियों में या अन्य किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसे उपरोक्त वेबसाईटः पर देखा जा सकता है। विस्तृत एन.आई.टी.एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

(इंजी.हिमांशु उपाध्याय)
कार्यपाल यंत्री
लो.नि.वि. (वि./यां.) संभाग क्र. 02 भोपाल

जी -25157/25 स्वच्छता ही सेवा

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण शाला (एमटी), भोपाल (म.प्र.)

ऑनलाईन निविदा आमंत्रित

पी.टी.एस. (एमटी) भोपाल के अधिपत्य भदभदा स्थित 48 शासकीय क्वार्टर के 02 ब्लॉक (24) आवास) में 24 नग पानी की नई टंकिया मय फिटिंग के साथ लगाने के कार्य से सबंधित ऑनलाईन निविदा आंमत्रित की गई है। नियम एवं शर्तें तथा अनुबंध की विस्तृत जानकारी mptenders.gov.in तथा www.mppolice.gov.in की बेवसाईट पर प्राप्त की जा सकती है।

निविदा प्रकाशन की दिनांक	22/01/2026 के 17:00 बजे।
निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की प्रारंभ की दिनांक	22/01/2026 के 17:00 बजे।
प्री बिड मीटिंग दिनांक	27/01/2026 के 11:00 बजे।
निविदा जमा करने की प्रारंभ दिनांक	01/02/2026 के 09:00 बजे।
निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक	11/02/2026 के 14:00 बजे।
निविदा खोलने की दिनांक	13/02/2026 के 16:00 बजे।

पुलिस अधीक्षक
पी.टी.एस. (एमटी), भोपाल

जी -25211/25 स्वच्छता ही सेवा

आवश्यकता है | खरीदना है | बेचना है | व्यापार | चिकित्सा | ज्योतिष | डिस्प्ले विज्ञापन
हरिभूमि क्लासीफाइड संपर्क सूत्र : 9407279644 9977912473

आवश्यक सूचना

पाठकों से अनुरोध है कि वे समाचार में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार का कदम उठाने (धन भेजने, लोन संबंधित, चिकित्सकीय सलाह, विवाह संबंधित अथवा अनुबंध) से पहले अच्छी तरह जाँच पड़ताल कर लें। किसी भी उत्पाद या सेवाओं के संबंध में किये किसी विज्ञापन दाता के किसी प्रकार के दावों की हरिभूमि की जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रकाशक संपादक और हरिभूमि के स्वामी किसी विज्ञापन के संबंध में उठाये किसी कदम के नतीजे और विज्ञापन दाताओं के अपने वायदों पर खरा न उतरने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

- व्यावस्थापक

Ratnawala
रत्नवाला
141- Malviya Nagar, City Trade Center Bhopal. 89 89 678-678

हरिभूमि भोपाल बाजार विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें मो.9977912473

प्लाट मात्र 3,55,000 हजार में आसान किश्तों पर
साईट:- 220 फिट रिंग रोड न्यू बायपास से लगी हुई डायवर्सन एवं NOC एप्रूव्ड आफिस इंडिया प्रोपर्टी करोंद भोपाल मो. 7772079910

Medical Help Line
विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें : मो.9407279644

नये दागों का आना तुरन्त बंद
सफेद दाग गारंटेड इलाज
Timing 10:30 am to 8:00 pm
Dr. Safi's HOMEOPATHIC CLINIC
कृपया फोन पर अपॉइंटमेंट लें। M : 9425006131, 9827249409
5/4, संजय कॉम्पलेक्स माता मंदिर, टी.टी. नगर भोपाल | सौलत मंजिल पुरानी कजियात के सामने मोती मस्जिद भोपाल

WE PROVIDE THE BEST SOLAR ENERGY
BEST OFFER
Na 2 Lakh Mein.. Na 1.5 Lakh Mein..
Sirf ₹72,000 Mein! 3.3 kW Solar Lagaye Bachat ka Naya Tareeka!
ZERO ENERGY SOLAR
HURRY UP! 1 alkaline water bottle free on Same day Booking
Contact us: 99932-41867, 7354999381
First Floor, Aashima Mall, Bhopal
228, Dwarkadhish colony, Indore (M.P.)- 452005

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पारवती पत्नि श्री खड़ी आयु 43. वर्ष निवासी म.न. 1212, ग्राम-मोहन्द्रा, तह. सिमारिया, जिला- पन्ना म.प्र. की निवासी हूँ। मेरा विवाह के पूर्व नाम पारवती पुत्री राम किशन था एवं विवाह के पश्चात मेरा नाम पारवती पत्नि खडी हो गया है। मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कला रेकवार पत्नि खडी दर्ज हो गया है जो कि गलत है। मेरा सही नाम व सरनेम पारवती पत्नि खडी है, जो सही एवं सत्य है मैं इसी नाम व सरनेम से जानी पहचानी जाती हूँ।

नाम परिवर्तन

मैं, कल्पना पटेल, जिनकी जन्मतिथि 15 मई 2001 है और आधार नंबर 4108 8447 7345 है, मैं छोटे लाल पटेल की बेटी हूँ, जिनका आधार नंबर 8625 4274 5130 है और मैं 61, आदर्श नगर बैरागढ़ कलां हुजूर, जिला- भोपाल, पिन-462030, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, यह एफिडेविट यह बताने के लिए दिया जा रहा है कि मेरी एकेडमिक मार्कशीट और रिकॉर्ड में मेरे पिता का नाम छोटे लाल पटेल की जगह CL पटेल दर्ज और रिकॉर्ड किया गया है। अतः मेरे पिता का नाम छोटे लाल पटेल (Chhote Lal Patel) हमारे मार्कशीट और रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए।

छोटा लिंग निराश क्यों? जोश जगा दे धूम मचा दे।
18 से 80 वर्ष तक लाभदायक
लिंग को 8-9 ईन्च लम्बा मोटा, कठोर बनाये। सैक्स टाइम 30 से 45 मिनट बढाएं।
नसों की कमजोरी नामर्दी, धातु का पतलापन, शुगर, बी.पी. में भी जबरदस्त लाभदायक।
घर बैठे मंगवाये। लाभ नही तो पैसे वापिस।
8515825081 9083218330
R- 22/01/25 to12/03/26
Not , 26,27/01/26, 15/02/26 , 04,08/03/2026

शब्द पहेली - 6126

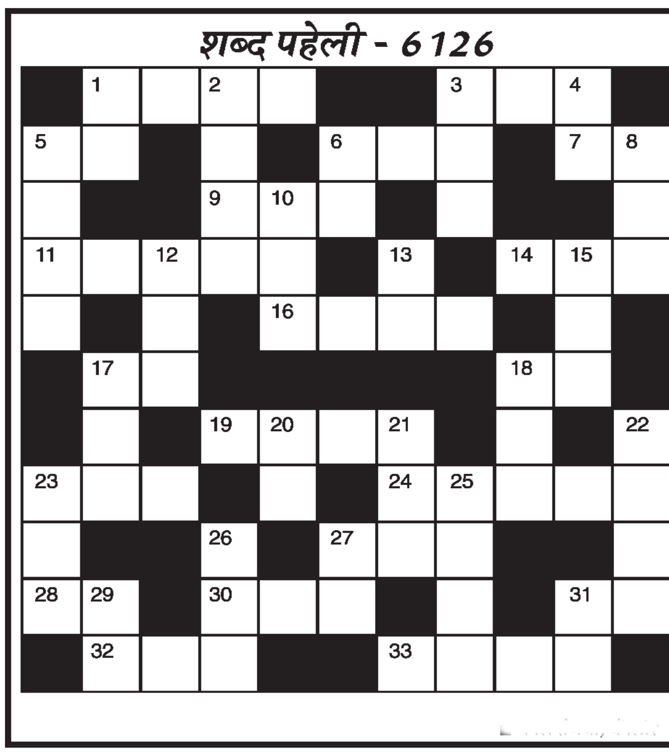

बाएँ से दाए
1.मूर्ख,बुद्धिहीन-4
3.रुई की फसल-3
5.वंश,खानदान-2
6.आह,पीड़ा भरी ध्वनि-3
7.जी,इच्छा,चित्त-2
9.पहनना-3
11.दास,नौकर,सेवक-5
14.अग्नि,आग-3
16.चयनित,स्वीकृत-4
17.जाति,संप्रदाय-2
18.उस समय-2
19.आदत,व्यवहार-4
23.माला का मोती-3
24.लालन-पालन-5
27.पूर्णिमा-3
28.वश,अधीन-2
30.खबर देने वाला-3
31.खदान,माइन-2
32.आश्रय,पनाह-3
33.संपत्ति-4

ऊपर से नीचे
1.घोड़े के पांव में लगने वाला लोहे का टुकड़ा-2
2.धारा के बीच में,अधर में-2,2
3.आफत,आपदा-3
4.एक समान-2
5.गृहपति,चांसलर-4
6.दाना-2
8.प्रतिकृति,प्रतिरूप-3
10.रोकर धनराशि-3
12.प्रेम ,आसक्ति-3
13.नीर,जल-2
15.भाग्य,तकदीर-3
17.जंबुल,जांब-3
18.टेंशन,परेशानी-3
20.काया,बदन-2
21.उष्णता-3
22.नाश होने योग्य-4
23.साम्राज्ञी,रानी-3
25.रमण करने योग्य-4
26.अदा,चोंचला-3
27.पूड़ी,गोलगप्पा-2
29.पिता की बहन-2
31.उर्वरक,गाय के गोबर से बना पदार्थ जो खेत में डाला जाता है-2

शब्द पहेली- 6125 का हल

सूडोकु नवताल - 6136

★★★★★ कठिनतम

				5	1	4		
			7				2	
		8						3
	1							8
5				4				9
7							6	
4						7		
	2				6			
		3	9	8				

MANGAL SENACHA, BANGALORE

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल - 6135 का हल

4	7	6	3	5	2	9	1	8
5	9	8	6	7	1	4	3	2
2	3	1	8	9	4	7	6	5
6	8	5	7	3	9	2	4	1
3	2	4	5	1	6	8	7	9
7	1	9	4	2	8	3	5	6
8	4	3	2	6	5	1	9	7
1	5	2	9	4	7	6	8	3
9	6	7	1	8	3	5	2	4

राशिफल

मेष – मन प्रसन्न तो रहेगा, परन्तु बातचीत में सन्तुलन बनाये रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। धर्म के प्रति श्रद्धाभाव रहेगा। चिकित्सीय खर्च बढ़ सकते हैं।

वृष – आत्मसंयत रहें। क्रोध से बचें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन – किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं। सुस्वादु खानपान में रुचि रहेगी।

कर्क – जीवनसाथी का साथ मिलेगा। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। वाणी में सौम्यता रहेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

सिंह – जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रहन-सहन कष्टमय रहेगा। आत्मविश्वास में कमी आएगी। परिवार की समस्याओं पर ध्यान दें।

कन्या – पठन-पाठन में रुचि रहेगी। शैक्षिक या शोधादि कार्यों के लिए विदेश जा सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें।

तुला – मन प्रसन्न रहेगा। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद-विवाद से बचें। कुटुम्ब के किसी बुजुर्ग से धन मिल सकता है। अपनी भावनाओं को वश में रखें।

वृश्चिक – मन में नकारात्मक विचारों से बचें। कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कुटुम्ब-परिवार में धार्मिक कार्य होंगे।

धनु – आय में कमी एवं खर्च अधिक की स्थिति रहेगी। क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें। घर-परिवार में धार्मिक एवं मांगलिक कार्य हो सकते हैं।

मकर – क्रोध से बचें। बातचीत में संयत रहें। वस्त्र उपहार में प्राप्त हो सकते हैं। पिता से धन मिल सकता है। मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

कुंभ – मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत का ध्यान रखें। परिवार के साथ यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। अनियोजित खर्च बढ़ेंगे। माता का सहयोग मिलेगा।

मीन – पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। वाणी में मधुरता रहेगी। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। सन्तान की ओर से सुखद समाचार मिलेंगे।

सरकार ने बजट में युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया

सरकार ने 2026-27 के बजट में मैन्युफैक्चरिंग 40 हजार करोड़ ,एमएसएमई के लिए 10 हजार करोड़, सेमीकंडक्टर के लिए 40 हजार करोड़ से साइंस टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में मजबूत होंगे। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। सात हाई स्पीड रेलवे से यातायात के साथ उद्योग को फायदा होगा, मेगा टेक्सटाइल पार्क, छोटे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में जोर, निजी विश्वविद्यालय को आर्थिक मदद से शिक्षा और मजबूत होगी

1.39 लाख करोड़ से शिक्षा को मजबूती मिलेगी, टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में मजबूत होंगे

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

भारत आर्थिक परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं युवा आर्थिक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अर्थशास्त्री डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा ने आने वाले बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने 2026-27 के बजट में युवाओं कि शिक्षा एवं रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया है, शिक्षा के लिए 1.39 लाख करोड़ से शिक्षा को मजबूती प्रदान होगी।

खेलों को बढ़ावा देने एवं खेल सामग्री निर्माण से रोजगार और उद्योग मजबूत होगा

विश्वकर्मा ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग 40 हजार करोड़ ,एमएसएमई के लिए 10 हजार करोड़, सेमीकंडक्टर के लिए 40 हजार करोड़ से साइंस टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में मजबूत होंगे। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

सात हाई स्पीड रेलवे से यातायात के साथ उद्योग को फायदा होगा, मेगा टेक्सटाइल पार्क, छोटे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में जोर, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा, होटल मैनेजमेंट और निजी विश्वविद्यालय को आर्थिक मदद से शिक्षा और टूरिज्म सेक्टर में मजबूती आएगी। खेलों को बढ़ावा देने एवं खेल सामग्री निर्माण से रोजगार और उद्योग मजबूत होगा, टूरिज्म सेक्टर में 10 हजार गाइड को ट्रेनिंग देने से युवाओं को नौकरी मिलेगी।

महिला समूह, पशुपालन और डेयरी उद्योगों को बजट में विशेष सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बजट में भारतीय ज्ञान परंपरा को भी मजबूती प्रदान की गई है योग शिक्षा, जड़ी बूटी, शुगर और कैंसर की दवाइयां को सस्ता किया गया है, 22 जल मार्ग, पैरामेडिकल, शहरी आर्थिक क्षेत्र का विकास एवं हाई क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात की गई है। बजट में अर्थव्यवस्था को उद्यमिता, नवाचार और आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक प्रगति और सुशासन, ताकि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सकें।

डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा, अर्थशास्त्री
एम.ए. अर्थशास्त्र, एम.ए. ग्रामीण विकास, एमबीए

केंद्रीय बजट आने वाले 10 वर्षों में भारत के विकास की दिशा तय करेगा : खंडेलवाल

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय बजट पर दी प्रतिक्रिया

भोपाल। केंद्रीय बजट आने वाले 10 वर्षों में भारत के विकास की दिशा तय करेगा। भारत को दुनिया के नक्शे पर अग्रणी देश बनना है, तो हमें उन सभी क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा जहां आज अमेरिका और चीन आगे हैं। इस केंद्रीय बजट में रेयर अर्थ सहित उन सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जिनसे भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सके। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने रविवार को केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही।

खंडेलवाल ने कहा कि रियल एस्टेट हो या चिप मैन्युफैक्चरिंग, हर क्षेत्र में भारत में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। जिन क्षेत्रों में दुनिया के केवल दो-तीन देशों का दबदबा है, उन रणनीतिक उत्पादों के निर्माण पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में पहली बार अलग मालगाड़ी कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, जिससे लॉजिस्टिक्स खर्च कम होगा। और व्यापार बढ़ेगा। लॉजिस्टिक्स लागत कम होने से भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता चीन के मुकाबले और अधिक मजबूत होगी।

उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दृष्टि से अगले 5 वर्षों में 10 हजार करोड़ के परिव्यय के साथ 'बायो-फार्मा शक्ति' योजना का प्रस्ताव अभिनंदनीय है। यह पहल देश में बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए एक मजबूत ईकोसिस्टम तैयार करेगी। देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा बच्चियों की सुरक्षा एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अत्यंत सराहनीय कदम है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खण्डेलवाल ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री की बताई चार जातियों के साथ हर वर्ग को राहत देने वाला है।

समावेशी विकास के संकल्प के साथ 'विकसित भारत 2047' को सशक्त करने वाला बजट

सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को मजबूती देने वाला, परिपूर्ण और नए आयाम स्थापित करने वाला है। यह बजट आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत के संकल्प के साथ देश के हर वर्ग के कल्याण, संरक्षण और सर्वांगीण विकास की स्पष्ट दिशा देता है।

मंत्री सारंग ने कहा कि केंद्रीय बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और विश्वास का सशक्त प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि फिस्कल डेफिसिट में कमी, महंगाई पर नियंत्रण और हाई कैपेक्स के माध्यम से हाई ग्रोथ इस बजट की प्रमुख विशेषताएं हैं। खेल क्षेत्र पर बजट के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए सारंग ने कहा कि खेल क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास और रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किए गए खेल प्रतिभाओं के व्यवस्थित पोषण को आगे बढ़ाते हुए, अगले दशक में खेल क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया मिशन को नई गति मिलेगी।

भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी राष्ट्र बनाने की मजबूत नींव रखता है बजट

भोपाल। भाजपा के जिला अध्यक्ष रविन्द्र यति ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह केंद्रीय बजट आने वाले 10 वर्षों में भारत के विकास की दिशा तय करने वाला है। यह बजट भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी राष्ट्र बनाने की मजबूत नींव रखता है। यदि भारत को अमेरिका और चीन जैसे देशों के समकक्ष खड़ा होना है, तो उन सभी रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक है, जिनमें ये देश आज अग्रणी हैं।

केंद्रीय बजट में रेयर अर्थ मिनरल्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और अन्य उन्नत औद्योगिक क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूत करने का स्पष्ट संकेत दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन रणनीतिक उत्पादों पर आज दुनिया के केवल दो-तीन देशों का वर्चस्व है, उनके घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। इससे भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा।

उच्च शिक्षा के लिए योजनाओं की क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए

दीपक तिवारी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व कुलगुरू माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार

भारत सरकार आने वाले समय में किसानों की भूमि से अधिक आमदनी के लिए लागू की गई पीएम कुसुम योजना का दूसरा चरण लाएगी, किंतु इसको लेकर बजट में नई घोषणा नहीं की गई। पिछली योजना का बचा हुआ पैसा ही जारी किया गया है, जो कि इस वर्ष मार्च में समाप्त हो रही है।

यदि कुसुम का दूसरा चरण आता ता मध्यप्रदेश के बहुत से किसानों के लिए लाभ होता। जहां तक डिजिटल क्रिएटिविटी के लिए जो कंटेंट क्रिएटर लैब्स को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं, वह स्वागत योग्य तो हैं। परंतु जब तक सरकार किसी भी तरह के शिक्षण में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देगी, तब तक इस तरह के सभी प्रयास कागजी ही साबित होंगे। सरकार के लिए वर्तमान में जो उच्च शिक्षा के लिए योजनाएं चल रही है, उनमें क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए।

2026-27 का केंद्रीय बजट सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आधारित: शर्मा

सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि 2026-27 का केंद्रीय बजट 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। केंद्र सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूत करने के साथ साथ समाज के हर वर्ग को विकास में भागीदार बनाना है।

2026-27 का ये बजट सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर आधारित है। इसमें गरीब, युवा, महिला, किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वरिष्ठ जन, दिव्यांगजन, पिछड़ा वर्ग सभी के आशाओं को पूरा करने का प्रयास किया गया है। खास बात है कि शुगर, कैंसर की जीवन रक्षक दवाओं को शुल्क में छूट दी गई है।

बायो फार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, कई क्षेत्रों में बड़े टेक्सटाइल पार्क, शहरी आर्थिक क्षेत्र पर प्रतिवर्ष 5 हजार करोड खर्च का प्रावधान, 20 नए जलमार्गों का विकास, चार राज्यों में खनिज कॉरिडोर, तीन केमिकल पार्क, तीन नए आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

जिंदगी लाइव

भाषा, संस्कृति और राष्ट्रबोध का संगम बना मातृभाषा मंच

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

भेल दशहरा मैदान में आयोजित मातृभाषा समारोह में रविवार को सांस्कृतिक विविधता का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा के यशस्वी जीवन पर प्रेरणापूर्ण एवं जानकारी वर्धक नाटक की प्रस्तुति दी गई। इसमें दिखाया कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जीवन में पर्यावरण ,पेड़ और जंगल के प्रति जो सेवा भाव रखा, अंग्रेजों से जो उन्होंने संघर्ष किया।

वहीं सायं कालीन कार्यक्रम में राम जन्मभूमि के भव्य निर्माण, संघर्ष, आरंभ, चुनौतियां और उसके निर्माण की विजय यात्रा चलचित्र का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक के राष्ट्रीय विचारक सुरेश सोनी ने स्वदेशी स्टॉल पर प्रदर्शित गुलाब से बने विविध उत्पादों एवं गुलकंद का अवलोकन व स्वाद परीक्षण किया। साथ ही स्टॉल लगाने वाली बहनों से उनके अनुभव, स्वावलंबन की यात्रा और स्वदेशी उत्पादों के प्रति जनरुचि पर संवाद किया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय विचारक सुरेश सोनी पंच परिवर्तन विषय पर स्वदेशी जागरण मंच की प्रान्त महिला कार्य प्रमुख सीमा भारद्वाज से चर्चा करते हुए। इस अवसर पर सोनी ने स्वदेशी स्टॉल पर प्रदर्शित गुलाब से बने विविध उत्पादों एवं गुलकंद का अवलोकन व स्वाद परीक्षण किया। साथ ही स्टॉल लगाने वाली बहनों से उनके अनुभव, स्वावलंबन की यात्रा और स्वदेशी उत्पादों के प्रति जनरुचि पर संवाद किया।

संगीत की अविस्मरणीय संध्या 'पूनम-41'

सरोद एवं सितार की जुगलबंदी में सजी रागात्मक संध्या

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय शास्त्रीय संगीत श्रृंखला 'पूनम-41' भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत उत्सव बन गया। शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय संध्या का साक्षात्कार उस समय हुआ, जब कार्यक्रम का शुभारंभ तीन ताल की सुसंयोजित और महाकाल बंधना सधी हुई लय के साथ किया गया। ताल की स्पष्टता और संतुलित गति ने संपूर्ण प्रस्तुति

के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया, जिससे श्रोताओं को प्रारंभ से ही संगीत की गंभीरता और गरिमा का अनुभव हुआ। वहीं पूर्वरंग कार्यक्रम में प्रस्तुत जुगलबंदी में रामेंद्र सिंह सोलंकी (तबला) एवं ज्ञानेश्वर देशमुख (पखावज) की सधी हुई लयकारी ने प्रस्तुति को संपूर्णता प्रदान की।

'जश्ने उर्दू-2026' का तीसरा दिन

मुहब्बत फूलती-फलती रही भोपाल में मेरे, कि नफरत खुदकुशी करती रही भोपाल में मेरे...

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

मप्र उर्दू अकादमी द्वारा आयोजित चार दिवसीय 'जश्ने उर्दू-2026' का तीसरे दिन प्रख्यात हास्य कलाकार एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहमान खान (मुंबई) द्वारा गिगल-ए-आजम के अंतर्गत एकल नाट्य प्रस्तुति दी। इस सत्र का संचालन मुमताज खान द्वारा किया गया। अंतिम सत्र में उर्दू का फिल्मी सफर - 'चलते चलते' संगीतात्मक नृत्य-नाट्य प्रस्तुति का मंचन हुआ। इस प्रस्तुति में प्रख्यात सिने अभिनेत्री मीना कुमारी के जीवन व उनके कृतित्व

को भी रेखांकित किया गया। इसके साथ ही युवाओं के लिए खास रहा मुशायरा। जिसकी अध्यक्षता विदिशा के उस्ताद शायर निसार मालवी ने की। मुशायरे में महावीर सिंह ने पढ़ा मुहब्बत फूलती-फलती रही भोपाल में मेरे कि नफरत खुदकुशी करती रही भोपाल में मेरे।

हरिभूमि कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक अचिंत महेश्वरी द्वारा प्लॉट नं.160 न्यू एच-सेक्टर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोविंदपुरा, भोपाल (म.प्र.) 462023 से मुद्रित एवं हरिभूमि कार्यालय, पीबी-2, चतुर्थ तल, मानसरोवर कॉम्प्लैक्स, वार्ड नं. 50, शिवाजी नगर, निकट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, होशंगाबाद रोड, भोपाल, (म.प्र.) 462016 से प्रकाशित। प्रधान संपादक : डॉ. हिमांशु द्विवेदी। स्थानीय संपादकः प्रमोद भारद्वाज। RNI No. MPHIN/2014/55906, फोन 0755-4049930